लोकतंत्र में वंशवाद की राजनीति बहुत ही गलत है। हमें देश को इससे आजाद कराना है। -नरेंद्र मोदी

पिछले दस वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने जीसीसी के लगभग सभी सदस्य देशों का दौरा किया है। लेकिन अब तक प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा संपन्न न हो पाना, भारत के पश्चिम एशियाई जुड़ाव में एक रिक्त स्थान की तरह था, जिसे पूरी तरह से पाटना और नई संभावनाओं की तलाश ही उनकी इस यात्रा का उद्देश्य था।

कुवैत में मोदी

प्रधानमंत्री मोदी की हालिया कुवैत यात्रा ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग की शुरुआत तो की ही है, इस दौरान हस्ताक्षरित महत्वपूर्ण समझौते और रणनीतिक सहमतियां पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिहाज से भी अहम हैं। भारत और कुवैत के संबंध हमेशा से मैत्रीपूर्ण रहे हैं और 1961 में जब कुवैत को अंग्रेजों से आजादी मिली, तब भारत उसके साथ संबंध बनाने वाले शुरुआती देशों में शामिल था। 1981 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद यह यात्रा 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा थी। पिछले दस वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री ने खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के लगभग सभी सदस्य देशों का और कुछ देशों का तो एक से ज्यादा बार दौरा किया है। लेकिन अब तक प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा संपन्न न हो पाना, भारत के पश्चिम एशियाई जुड़ाव में एक रिक्त स्थान की तरह था, जिसे पूरी तरह से पाटना और नई संभावनाओं की तलाश ही प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य था और इस मायने में यह पूरी तरह से कामयाब भी रही। इस दौरान, रक्षा, खेल, संस्कृति और सौर क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण समझौते तो हुए ही, यह सहमति भी जताई गई कि निवेश को लेकर जल्द ही एक महत्वाकांक्षी संधि को अंतिम रूप दिया जाएगा। दरअसल, भारत व कुवैत के बीच रणनीतिक साझेदारी कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। चूंकि कुवैत भारत का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता है, इससे यह आपूर्ति सुरक्षित होने के साथ ही खाड़ी क्षेत्र में भारत की समग्र ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। यही नहीं, कुवैत के साथ रक्षा सहयोग भारत की 'ऐक्ट वेस्ट नीति' को भी मजबूती देगा। भारतीय समुदाय कुवैत का सबसे बड़ा प्रवासी समूह तो है ही, यह वहां की सामाजिक संरचना में भी महत्वपूर्ण जगह बनाए हुए है। कुछ ही महीने पहले कुवैत के नेशनल रेडियो द्वारा स्वप्नाहिक हिंदी रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत इसका ही प्रमाण है। गत जून में कुवैत की एक

इमारत में आग लगने से हुई भारतीयों की मौतों के बाद कुवैत ने जिस तरह का सहयोग दिया, वह भी दोनों देशों के मजबूत संबंधों को ही दर्शाता है। इसके बावजूद, खाड़ी के दूसरे देशों की तरह कुवैत के साथ भी भारत के संबंध अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुंच सके हैं, तो यह वाकई चिंतनीय है। ऐसे में, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ने निस्संदेह कुवैत व भारत के संबंधों को अगले स्तर पर पहुंचाने का काम किया है। उनकी यह यात्रा निश्चित ही खाड़ी क्षेत्र में एक जिम्मेदार साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगी।

राजनीति में वंशवाद खत्म हो रहा है?

सीरिया में 50 साल बाद अल-असद के शासन का अंत हो गया है। श्रीलंका में पहली बार कोई खानदानी परिवार सत्ता में नहीं है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने अपने बेटे को दोषमुक्त कर दिया है, तो ट्रंप ने समधी को एंबेसडर नियुक्त किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई राजनीति से परिवारवाद समाप्त हो रहा है?

सीरिया में अल-असद परिवार के पचास वर्षों के शासन का अंत उस वक्त हो गया, जब राष्ट्रपति बशर अल-असद ने देश छोड़कर रूस में शरण ले ली। उनका निष्कासन एक तरह से बांग्लादेश की शेख हसीना की तरह रहा, जो अगस्त में ढाका छोड़कर दिल्ली आ गई थीं। आंखों के दक्ष सर्जन बशर अपनी प्रैक्टिस कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन हसीना सोशल मीडिया के जरिये अपने प्रतिद्वंद्वियों पर लगातार हमलावर हैं। हसीना की प्रतिद्वंद्वी खालिदा जिया जेल से बाहर हैं और राजनीति जिस तरह का रूप ले रही है, और उनके बेटे तारिक जिया के खिलाफ दर्ज मामलों को जल्द निपटाया जा रहा है, उससे उन्हें बढ़ावा मिलने के ही संकेत मिलते हैं। जाहिर है कि इससे तारिक की राजनीति में वापसी का रास्ता खुल गया है। इससे यह सवाल फिर से मौजूं हो गया है कि क्या राजवंशों या परिवारवादी शासकों के शासन का वाकई अंत हो रहा है?

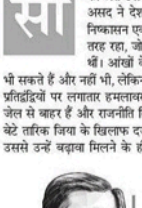

महेंद्र वेद
वरिष्ठ पत्रकार

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने जाने से पहले अपने बेटे हंटर को गंभीर अपराध में दोषमुक्त कर दिया है, जबकि निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समधी को फ्रांस में एंबेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। इस वर्ष श्रीलंका में हुए चुनाव में उसकी स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब भंडारनायके, प्रेमदासा, जयवर्धने या राजपक्षे, जैसे प्रमुख राजनीतिक परिवारों में से कोई भी सत्ता में नहीं है। नेपाल में कोइराला परिवार लंबे समय से सत्ता में नहीं है। नेपाल में कई परिवार राजनीतिक रूप से बेशक जीवित हैं, लेकिन सत्ता मार्क्सवादियों और माओवादियों के हाथों में है।

पाकिस्तान में प्रतिद्वंद्वी शरीफ और भुट्टो-जरदारी परिवार, इमरान खान को सत्ता से बाहर रखने के लिए एक हो गए हैं, जो कहते हैं कि उनका मकसद अपने परिवार को सत्ता में बनाए रखना नहीं है। फिर भी, अर्ध-सामंती समाज में सत्ता चलाने वाले कई परिवार हैं। शक्ति के बंटवारे के तहत, आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति हैं, तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम (पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी) शक्तिशाली

पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। राजनीतिक राजवंश कई लोकतंत्रों में राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण का एक प्रचलित रूप है। क्या राजशाही शासन देश के विकास में बाधक है? इस पर कई देशों में काफी अध्ययन और लेखन हुआ है। मसलन, पाकिस्तान की शिक्षाविद आयशा अली का 2016 में किया गया अध्ययन बताता है कि वर्ष 2010 में पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ के दौरान वंशवादी राजनेताओं वाले क्षेत्रों में विकास कार्यों पर 10.9 फीसदी व्यय कम हुआ।

भारत में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कई परिवार सत्ता में आए और गए। जैसे-पंजाब में बादल, जम्मू-कश्मीर में अब्दुल्ला, हरियाणा में लाल और चौटाला, उत्तर प्रदेश व बिहार में यादव, तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार, कर्नाटक में गौड़ा परिवार तथा महाराष्ट्र में पवार, चव्हाण और शिंदे आदि। नेहरू-गांधी खानदान ने अनेक वर्षों तक देश पर शासन किया। वंशवाद को जारी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर निशाना साधती रहती है। हालांकि सत्तारूढ़ दल में भी कुछ नेता हैं, जो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में परिवारवाद का अनुसरण कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने हाल ही में लोकसभा चुनाव जीतकर नेहरू-गांधी परिवार को और राजनीतिक मजबूती प्रदान की है। इसमें स्वर्गीय संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी भी शामिल हैं। क्या परिवारों में सत्ता हस्तांतरण लोकतंत्र के खिलाफ है? इसको लेकर अलग-अलग मत हैं।

कई पश्चिमी लोकतंत्र, जो दूसरों के अनुसरण के लिए लोकतांत्रिक शासन के अपने विचारों का प्रचार करते हैं, उनका नेतृत्व या तो वंशानुगत राजघरानों या प्रभुत्वशाली परिवार के पास होता है। अमेरिका में अब तक चार राजनीतिक परिवार-एडम्स, हैरिसन, रूजवेल्ट और बुश-में से प्रत्येक परिवार के दो सदस्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। यदि इस बात के स्पष्टीकरण हैं कि कुछ परिवार राजनीतिक जीवन की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, तो यह कम स्पष्ट है कि मतदाता पीढ़ी दर पीढ़ी अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हीं परिवारों के सदस्यों को क्यों चुनते हैं? यह एक प्रकार का मतदान व्यवहार है, जिसके लिए टेलीविजन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अमेरिका के राजनीतिक राजवंश औपनिवेशिक काल से चले आ रहे हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार, दुनिया के 43 संप्रभु राज्यों में, जिनका प्रमुख राजा होता है, 41 पर लंबे समय से चले आ रहे राजवंशों द्वारा शासन किया जा रहा है। प्रमुख राजनीतिक परिवारों में अमेरिका में कैनेडी, उत्तर कोरिया के किम, लेबनान के असैलान परिवार, हथोतमस, जिन्हें जापान का 'कैनेडी' कहा जाता है, फिलीपीन के एक्विनोस और इंडोनेशिया के सोएकरनोस शामिल हैं। म्यांमार में आंग सान सू की को निर्वाचित होने के बावजूद सत्ता बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा।

वास्तविकता यह है कि राजनीतिक राजवंश लंबे समय से लोकतंत्रों में मौजूद हैं, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि राजनीतिक शक्ति के वितरण में असमानता लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में खामियों को प्रतिबिंबित कर सकती है। फिर भी, जैसे व्यवसायों व फिल्मों में कामयाब परिवार अपनी आने वाली पीढ़ियों को आगे करते हैं, क्या राजनीति उनसे अलग है? कई राजनेता अपने बच्चों की शादी अपने ही वर्ग में करते हैं, क्योंकि उनका एक ही सामाजिक दायरा होता है। राजनीति में यह भी दिखता है कि किसी नेता की असमय मृत्यु के बाद उसकी पत्नी से बचे हुए कार्यकाल को पूरा करने की उम्मीद की जाती है। सार्वजनिक जीवन में भाईचारे को प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक दिखता है।

लोकतांत्रिक संगठनों में भी अघोषित कानून यह है कि नेतृत्व एक बार निर्वाचित होने के बाद खुद को सत्ता में स्थापित कर लेगा और समान अवसर के लोकतांत्रिक सिद्धांत को कमजोर कर देगा। इस पर कोई भी कानून रोक नहीं लगाता है। इस पर टेलीविजन पर भी कोई बहस नहीं होती, क्योंकि वहां 'तेरी भी चुप-मेरी भी चुप' है। यह सार्वभौमिक है और शायद आश्चर्य की बात नहीं कि इतने सारे राजनेताओं के बच्चे राजनीति में जाते हैं। आखिर यही उनके पिता का व्यवसाय है। ठीक उसी तरह, जैसे कई डॉक्टरों के बच्चे चिकित्सा क्षेत्र में जाते हैं। संसद का मार्ग कोई अलग थोड़े है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

अलेक्जेंडर रस्किन

उस अफसर ने जब मेरे पिताजी से कहा कि आखिर इन्सान क्या होता है? पिताजी खुद बच्चे थे, सोच में पड़ गए। सोचते-सोचते उन्हें यह समझ आ गया कि इन्सान वही हैं, जो बार-बार अपना इरादा न बदले।

मैं इन्सान बनना चाहता हूं

मेरे पिताजी जब छोटे थे, तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता। मगर उनका जवाब हर बार अलग-अलग होता था। शुरू-शुरू में वह कहते, 'मैं चौकीदार बनना चाहता हूं।' दरअसल, उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, तब चौकीदार जागता है। तभी एक दिन हुआ यों कि उन्होंने एक व्यक्ति को ठेले पर आइसक्रीम बेचते हुए देखा। उन्होंने सोच लिया कि वह भी आइसक्रीम वाला बनेंगे। उन्होंने सोचा कि यह तो मजेदार काम है। जब मन करे, तो आइसक्रीम खा लो। उन्होंने सोचा, 'एक आइसक्रीम बेचूंगा, तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा।'

जब उनके माता-पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, पहले तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। बाद में यह बात उन्हें अच्छी लगी और वे खूब हंसे, लेकिन पिताजी अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। लेकिन एक दिन मेरे पिताजी रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन की चाल को देखकर एक बार फिर उनका दिमाग घूम गया। हालांकि कुछ ही दिन बाद उन्होंने वायुयान का पायलट बनने की सोची। फिर उन्होंने अभिनेता बनने का निश्चय किया। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं, वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ-पैरों पर इधर-उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा, तो पिताजी ने उन्हें काटने की कोशिश तक की! उन्होंने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पिताजी कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पिताजी को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, 'यह तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, 'मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूं। तब फौजी ने पूछा, 'तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो?' पिताजी ने कहा, 'मैं काफी दिन तक इन्सान बनकर थक चुका हूं।' अफसर ने कहा, 'बात तो सही है। पर क्या तुम जानते भी हो कि इन्सान किसे कहते हैं?' पिताजी ने पूछा, 'मुझे तो नहीं पता। आप ही बता दीजिए।' अफसर ने कहा, 'इसके बारे में तुम अपने आप सोचो।' अफसर वहां से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज-रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया, तो उन्हें अफसर की याद आ गई, और उन्होंने कहा, 'मैं इन्सान बनना चाहता हूं। इस बार कोई भी नहीं हंसा। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इन्सान बनना चाहिए।

दबाव में भी याद रखें

सूत्र

बच्चे से बड़े होने के क्रम में हमसे अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि तुम क्या बनना चाहते हो? हमारे ऊपर वायुमंडलीय दबाव की तरह डॉक्टर, इंजीनियर, अभिनेता आदि बनने का अतिरिक्त दबाव होता है। इस दबाव में हम इन्सान बनना ही भूल जाते हैं। हर सपना एक लहर पैदा करता है, जिसका कोई तार्किक अंत नहीं होता।

दूसरा पहलू

डिजिटल क्रांति ने अभूतपूर्व सुविधाएं मुहैया कराई हैं। लेकिन डिजिटल प्रदूषण का खतरा भी पैदा किया है।

एक ई-मेल और चार ग्राम कार्बन डाईऑक्साइड

कल्पना कीजिए, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को अंगुलियों से ऊपर-नीचे कर रहे हैं। इसी दौरान आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि आपका क्लाउड स्टोरेज लगभग भर गया है। फिर, आप अपने डाटा को सुरक्षित रखने के लिए स्टोरेज खरीद लेते हैं। लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में यह सारा 'क्लाउड' डाटा कहां रहता है? यह आसमान में तो तैरता नहीं है, बल्कि इसे विशाल डाटा केंद्रों में संगृहीत किया जाता है, जो बहुत ज्यादा बिजली की खपत करते हैं, जिससे 'डिजिटल प्रदूषण' को बढ़ावा मिलता है।

आज हम घर बैठे मोबाइल पर एक क्लिक से मनचाही चीज ऑर्डर कर मंगवा सकते हैं। हालांकि डिजिटल क्रांति ने अभूतपूर्व सुविधाएं मुहैया कराई हैं। लेकिन डिजिटल प्रदूषण का खतरा भी पैदा किया है। एक लैपटॉप बनाने के लिए दुनिया भर के देशों से दर्जनों धातुओं की आवश्यकता होती है। उनके निष्कर्षण के लिए बहुत अधिक (जीवाश्म) ऊर्जा, पानी और संसाधनों की आवश्यकता होती है। ई-मेल भेजने, ऑनलाइन वीडियो देखने या वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आपका डिवाइस दुनिया भर में स्थित सर्वर से जुड़ता है, जो संचालन और ठंडा करने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत करते हैं। एक ई-मेल चार ग्राम कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। यदि आप ई-मेल में एक अटैचमेंट जोड़ते हैं, तो यह उत्सर्जन 50 ग्राम कार्बन डाईऑक्साइड तक पहुंच सकता है। इसी तरह एक गूगल सर्च की ऊर्जा खपत 60 वाट के बल्ब को 17 सेकंड तक जलाए रखने के बराबर होती है। फाइनल स्ट्रॉ फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर 60 सेकंड में 19 करोड़ ई-मेल किए जाते हैं।

सोशल मीडिया मैसेजर वाट्सएप पर करीब छह करोड़ मैसेज भेजे जाते हैं। सर्च इंजन गूगल पर 41 लाख लोग सर्च करते हैं। यू-ट्यूब पर 60 सेकंड में 43 लाख वीडियो देखे जाते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में दावा किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से हो रहे कार्बन उत्सर्जन के कारण 2030 तक अमेरिका में 1,300 लोग हर साल अकाल मौत का शिकार होंगे। भारत की संसद में हाल ही में शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि पिछले पांच वर्षों में स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविजन सेट और रेफ्रिजरेटर जैसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक उपकरणों से उत्पन्न ई-कचरे में 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऐसे में चुपके से पांव पसार रहा डिजिटल प्रदूषण हमारे समाने नई चुनौती बनकर खड़ा हो रहा है। इस नए प्रदूषण से निपटने को हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, इस पर हर एक डिजिटल नागरिक को चिंतन-मंथन करने की जरूरत है।

-प्रवल प्रताप सिंह

यदि आप ई-मेल में एक अटैचमेंट जोड़ते हैं, तो यह उत्सर्जन 50 ग्राम कार्बन डाईऑक्साइड तक पहुंच सकता है।

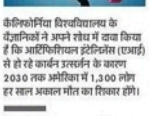

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में दावा किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से हो रहे कार्बन उत्सर्जन के कारण 2030 तक अमेरिका में 1,300 लोग हर साल अकाल मौत का शिकार होंगे।

आंकड़े

वन आच्छादन

वन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार, भारत के प्रमुख शहरों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सबसे ज्यादा वन आच्छादित शहरों में शामिल है।

दिल्ली	194.15
मुंबई	110.84
बंगलूरु	89.61
हैदराबाद	80.20
चेन्नई	20.60

आंकड़े प्रमुख शहरों के वन आवरण के, वर्ग किलोमीटर में | स्रोत : Forest Survey 2023

संतान न होने पर गंगाधरदास की पत्नी को ताने मिलते थे। गंगाधरदास ने श्रीकृष्ण की मूर्ति पत्नी को देते हुए कहा, 'प्रभु को छोड़कर दूसरा कोई उद्धारक नहीं है'।

माता! चिंता क्यों करती हो

भक्त गंगाधरदास की पत्नी स्त्रिया को संतान न होने पर कई ताने मिलते थे। एक दिन ग्रामवासियों से दुखी होकर वह गंगाधरदास से बोलीं, 'गांव की स्त्रियां मुझे ताने मारा करती हैं। कोई-कोई तो मेरे सामने भी नहीं आतीं। यदि सामने आ भी गईं, तो कहती हैं कि इसका मुंह देख लिया आज न जाने क्या अमंगल होगा। हमारे भाग्य में तो संतान है ही नहीं।'

पत्नी के शोक भरे वचन सुनकर गंगाधरदास ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। थोड़ी देर बाद गंगाधरदास भगवान श्रीकृष्ण की एक मूर्ति लेकर आए और अपनी पत्नी को देकर बोले, 'इनकी अच्छी तरह से सेवा-शुश्रूषा करना। देखो, प्रभु को छोड़कर जीवन का उद्धार करने वाला दूसरा कोई नहीं है।' एक दिन गंगाधरदास पत्नी से बोले, 'मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूं। श्रीकृष्ण जी की देखभाल करती रहना। एक क्षण भी अकेला नहीं छोड़ना।' गंगाधरदास जी व्यापार से लौट रहे थे। गांव में प्रवेश करते ही एकाएक ठोकर लगने से जमीन पर गिर पड़े और उसी क्षण बोले, 'हे कृष्ण मैं आपको देख न पाया' और प्राण त्याग दिए। यह खबर उनकी पत्नी को पता चली, तो वह श्रीकृष्ण के पास पहुंचीं और पुकार करने लगीं। भगवान माता के वचन सुनकर बोले, 'माता! तुम निश्चिंत रहो, क्यों चिंता करती हो? तुम जाकर उनको उठाओ।' पत्नी जैसे ही गंगाधरदास जी को उठाती हैं, वैसे ही वह उठ जाते हैं और कहते हैं, 'तुम यहां क्यों हो, मेरे कृष्ण को अकेला छोड़ आईं।'

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 02 दिसंबर,1962

चीन से वार्ता करना उसे अपने पैर मजबूत करने का मौका देना होगा

आगरा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आचार्य कृपलानी ने कहा, 'आज हम चीन से वार्ता व समझौते की बातें कर रहे हैं। इससे शत्रु को अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा और फिर वह हमका इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करेगा।'

महंगाई की महाचुनौती

दास के कार्यकाल में कोरोना संकट से जूझने के बावजूद भारत पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। अब नए गवर्नर को भी कई चुनौतियों से जूझना है।

डॉ. पीएस वोहरा

आर्थिकी

नए गवर्नर के रूप में सरकार ने संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बागडोर सौंपी है। पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास और वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा के माध्यम से सरकार ने अपनी मंशा को भी स्पष्ट कर दिया है कि वह देश की बैंकिंग व्यवस्था तथा आर्थिक तंत्र को चलाने के लिए खुद का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक मानती है। दास का छह साल का कार्यकाल यकीनन सरकार के साथ बिना किसी विवाद के सफलतापूर्वक खत्म हुआ।

एक समय में आरबीआई के मुखिया के तौर पर विख्यात अर्थशास्त्री रघुराम राजन इस पद पर रहे, जिन्होंने वर्ष 2003 में ही अमेरिका को चेता दिया था कि वह मंदी के दौर की ओर अग्रसर है। राजन के बाद उन्हीं की तरह उर्जित पटेल को मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में गवर्नर के लिए चुना, लेकिन एकाएक 10 दिसंबर, 2018 को उनके इस्तीफे के बाद 12 दिसंबर, 2018 को जब शक्तिकांत दास

गवर्नर के पद पर नियुक्त हुए, तो इस बात पर आर्थिक जगत में एक अंदेशा था कि क्या वह मोदी सरकार के तेजी से बढ़ रहे आर्थिक एजेंडे पर सही ढंग से कदमताल कर पाएंगे। किंतु उन्होंने करके दिखाया।

पिछले छह वर्षों के दास के कार्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोरोना के आर्थिक संकट को देखा, जब बीते 40 वर्षों में पहली दफा जीडीपी नकारात्मक रही। फिर वैश्विक मोर्चे पर जी-20 में भारत के एक वर्ष के अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान भी कई तरह की सकारात्मक सोच को वास्तविक परिणाम में बदलते हुए पाया। यह भी ज्ञात रहे कि इन्हीं वर्षों में भारत ने जीडीपी की दौड़ में बड़ी तेजी से छलांग लगाई और पांचवीं बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था का मुकाम भी हासिल किया।

संजय मल्होत्रा ने आरबीआई की कमान मुश्किल भरे दिनों में संभाली है। इन दिनों भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में गिरावट दर्ज हुई है। इसी के चलते चालू वित्तीय वर्ष में विकास दर को आरबीआई ने अब 7.2 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत पर अनुमानित किया है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर को बढ़ाना, वर्तमान समय में एक मुख्य चुनौती है और इस चुनौती का पहला मुख्य कारण लगातार बढ़ रही महंगाई है।

बीते, अक्तूबर में महंगाई 6.2 प्रतिशत पर दर्ज हुई, जो कि आरबीआई की नीतियों के मापदंड के मुताबिक अधिकतम महंगाई दर छह प्रतिशत की सीमा से भी बाहर थी। इसके अलावा, इन दिनों वैश्विक स्तर पर तेल के मूल्य में वापस बढ़ोतरी की संभावना है, जिसके चलते आने वाले दिनों में घरेलू बाजार में महंगाई का और असर रहेगा। शायद इसी के चलते आरबीआई ने अब चालू वित्तीय वर्ष के लिए महंगाई को 4.8 प्रतिशत पर अनुमानित किया है, जबकि पहले ये अनुमान 4.5 प्रतिशत था। इससे ऐसा लगता है कि नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के लिए महंगाई को नियंत्रण में रखना ही मुख्य चुनौती रहेगी। यह देखना भी आश्चर्यजनक ही होगा कि क्या आरबीआई आने वाले दिनों में रेट कट को प्राथमिकता देगा? नए गवर्नर के सामने दूसरी बड़ी चुनौती डॉलर के मुकाबले रुपये को स्थिर रखना होगी। इस संदर्भ में पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास ने रुपये को डॉलर के मुकाबले स्थिर रखने के लिए पिछले दो वर्षों में भारतीय बाजार में 130 अरब अमेरिकी डॉलर को बेचकर डॉलर की रुपये की तुलना में मांग को नियंत्रित करने की कोशिश की, ताकि रुपया अधिक कमजोर न हो।

अब इस बात की सुगबुगाहट ज्यादा है कि पिछले दो वर्षों से अधिक समय से भारतीय रुपया डॉलर के सामने 84 के स्तर पर स्थिर है, क्या इसे इसी सीमा पर नियंत्रित किया जाएगा या उसमें कुछ बढ़ोतरी की स्वीकृति रहेगी, ताकि भारत के निर्यातों को नुकसान न हो। पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास की रुपये को 84 पर नियंत्रित करने की नीतियों के चलते भारतीय निर्यातों में वर्ष 2019 से अब तक मात्र 4.5 प्रतिशत की ही वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि उससे पहले बीते दो दशकों में यह वृद्धि दर 10 प्रतिशत थी।

आने वाले समय में वैश्विक तौर पर भी कुछ चुनौतियां नए तरीके से आरबीआई के सामने आएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आर्थिक नीतियां किस तरफ करवट लेती हैं, यह भी मुख्य तौर पर देखना होगा। वहीं, शेयर बाजार में कुछ उठापटक होती है, तो उसके प्रति भी आरबीआई का क्या रुख रहेगा? यह सब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के दौर में है और आगामी एक फरवरी के बजट में निश्चित तौर पर आर्थिक विकास के मोर्चे पर सरकार की कुछ नई आर्थिक नीतियां देखने को मिलेंगी और उससे पूर्व आरबीआई का रुख भी इस पक्ष पर काफी कुछ स्पष्ट कर देगा।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 24 दिसम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

व्यापार और दोस्ती

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुवैत के महामहिम अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल सबा के साथ अपनी बैठक को उत्कृष्ट बताया। दोनों नेताओं ने व्यापक चर्चा की और भारत व कुवैत के बीच संबंध रणनीतिक साझेदारी तक विस्तारित हो गए। सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि, फिनटेक, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट किया, मैं आशावादी हूं कि आने वाले समय में हमारी दोस्ती और भी विकसित होगी। प्रधानमंत्री मोदी दो दिवसीय यात्रा पर वहां गए थे। जो बीते 43 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। उन्होंने बहुत ही सधे शब्दों में बयान किया, हिन्दुस्तान से यहां आने में चार घंटे लगते हैं मगर प्रधानमंत्री को यहां आने में चार दशक लग गये। कुवैत में दस

लाख की आबादी वाला भारतीय समुदाय सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। मोदी ने भारतीय समुदाय के कल्याण के लिए अमीर के प्रति आभार व्यक्त किया। वे वहां प्रवासियों से भी मिले। यह मोदी का अपना तरीका है। वे अपनी विदेश यात्राओं के दौरान प्रवासी भारतीयों से मिलकर अपनी लोकप्रियता ही नहीं बढ़ाते बल्कि प्रवासियों के विषय में वे खुलकर बात करते हैं और विशाल मंच से भारतीयता तथा देसी यादों का पिटारा भी पेश करने से नहीं चूकते। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता है। देश में कुवैत निवेश प्राधिकरण का निवेश दस अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुका है। कुवैत ने व्यापारिक आयात-निर्यात के लिए मुंबई, कोलकाता, पोरबंदर व गोवा में इन व्यापारिक गतिविधियों के मद्देनजर अपने दफ्तर भी बनाए हैं। मोदी ने उन्नीसवीं सदी में कुवैती व्यापारियों के गुजरात आने का जिक्र भी किया। भारत और कुवैत के अरब सागर के दो किनारों पर बसे होने के बावजूद लंबे समय से रोजमर्रा के प्रयोग की चीजों समेत आभूषणों के व्यापार का आदान-प्रदान होता रहा है। मोदी ने अपनी कूटनीति में व्यापक परिवर्तन दर्शाये हैं। चूंकि इस वक्त भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है, इसलिए अपनी गति बनाए रखने के लिहाज से उसे व्यापक परिवेश में सोचना होगा। देश के दीर्घकालिक हितों व विकास के नये तरीकों के प्रति विशेष रुचि रखते हुए हमें सिर्फ उपभोक्ता बने रहने की बजाए निर्यात के मार्ग भी प्रशस्त करने हैं। विश्व के विभिन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंध भारत को तेजी से आगे बढ़ता देखने के लिए जरूरी हैं।

संघ प्रमुख की नसीहत

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के अमरावती (महाराष्ट्र) में दिए गए बयान का प्रभाव व्यापक है। उन्होंने रविवार को यह कहकर हर किसी को चौंका दिया कि 'धर्म को समझना बहुत कठिन है। धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार गलतफहमी और धर्म की समझ की कमी के कारण हुए।' उन्होंने यह कहकर कइयों को निशाने पर लिया कि ''धर्म महत्त्वपूर्ण है और इसकी सही शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म का अनुचित और अधूरा ज्ञान अधर्म की ओर ले जाता है।' इससे पहले भागवत ने 19 दिसम्बर को भी पुणे में एक बयान में कहा था कि हर दिन मंदिर-मस्जिद विवाद उठाया जाना सही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा करके हिन्दुओं के नेता बन जाएंगे।' दरअसल, संघ प्रमुख के बयान के गहरे निहितार्थ हैं। हाल के दिनों में मस्जिदों की खुदाई और हिन्दू-मुस्लिम समुदाय में फैली कटुता और हिंसा का

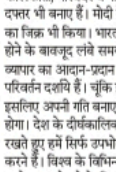

समाज में गलत असर पड़ा है। वैश्विक तौर पर भी ऐसी घटनाओं से देश की छवि प्रभावित हुई है। लिहाजा, भागवत के बयान को इसी संदर्भ में देखना चाहिए। यह पहला मौका नहीं है जब संघ प्रमुख ने कट्टर छवि से इतर बातें कही हैं। इसी महीने की 16 तारीख को उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को अहंकार से दूर रहना चाहिए। अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा तो वह गड्ढे में गिर जाएगा। इसी तरह उन्होंने जाति प्रथा पर बेहद चौंकाने वाला बयान दिया कि जाति पंडितों ने बनाई, जो गलत है। साफ है कि उनके बयान समाज में घटित घटनाक्रमों पर आधारित होते हैं और इस ओर साफ इशारा करते हैं कि विभिन्न धर्म-संप्रदाय-जाति और पंथों के बीच अगर किसी भी तरह का कसैलापन है तो वह निरर्थक है और इसके नतीजे दूरगामी हो सकते हैं। इतना तो तय है कि देश में जो कुछ हो रहा है, वह किसी भी नजरिये से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। मुस्लिम शासकों ने वर्षों पहले हिन्दू समाज पर जो अत्याचार बरपाया, उसका बदला अभी के समय में लेना भारतीय संस्कृति के उलट है। संघ प्रमुख का बयान भी इसी खांचे में रखने की दरकार है। कटुता और कट्टरता से जनता को अपने पाले में तो किया जा सकता है, मगर यह लंबे वक्त के लिए निश्चित तौर पर हास्यकारी साबित हो सकता है। जो कोई भी संघ प्रमुख के बयान की भर्त्सना कर रहे हैं, वह निश्चित तौर पर देश की गंगा-जमुनी संस्कृति को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं।

लैंगिक असमानता/सुनिधि मिश्रा

कार्यस्थल की चुनौतियां

भारतीय समाज में कार्यरत महिलाएं आज एक अभूतपूर्व संघर्ष का सामना कर रही हैं। एक ऐसी व्यवस्था में जहां पारंपरिक और आधुनिक मूल्य लगातार टकरा रहे हैं, इन महिलाओं को पेशेवर सफलता और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच एक असंभव संतुलन बनाने की चुनौती दी जा रही है।

कार्यस्थल और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना महिलाओं के लिए एक बड़ी मानसिक चुनौती है। कार्यस्थल पर हो रहे भेदभाव के कारण महिलाएं के ऊपर दिन प्रतिदिन दबाव बढ़ता ही जा रहा है, लगातार कार्य दबाव, परफॉर्मेंस के प्रति चिंता, और घर-काम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश उनमें तनाव और अवसाद पैदा करती है। महिलाएं जब भी अपनी मेहनत से कार्य को अच्छा करती है उन्हें किसी ना किसी मापदंडो पे तौला जाता है जैसे कि वह अपने परिवार और बच्चों का ध्यान सही से नहीं रखती है, उसके चरित्र पर कई सवाल खड़े कर दिए जाते हैं जब भी वह काम लेट आती है। पुरुषों के लिए ये काफ़ी बहुत आसान होता है कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, जबकि वो कभी यह नहीं समझ पाते हैं कि महिलाए कितनी जिम्मेदारियों तले दबी होती है। सामाजिक स्तर पर, कार्यरत महिलाओं को अभी भी पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं और रूढ़िवादी सोच का सामना करना पड़ता है। कार्यस्थल पर महिलाओं के सामने कई चुनौतियां हैं जो उनके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। भारतीय समाज में अभी भी महिलाओं को कम दर्जे की मानसिकता का सामना करना पड़ता है। कार्यस्थल पर उन्हें कई बार असमान व्यवहार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह दोहरा दबाव महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डाल रहा है। कार्यरत महिलाएं न केवल अपने परिवार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं, बल्कि समाज के विकास में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं। कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव और यौन उत्पीड़न पर प्रभावी कानून और नीतियों का कड़ाई से क्रियान्वयन होना चाहिए। संगठनों को महिला नेतृत्व को उभारने और उन्हें वरिष्ठ पदों पर नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

बंद मंदिर मिलने के मायने

संभल में 46 वर्षों से बंद मंदिर खुलने के बाद वहीं एक दूसरे मोहल्ले में भी बंद मंदिर मिलने के बाद वाकई देश में सनसनी पैदा हुई है। लोगों के अंदर स्वाभाविक गुस्सा है कि किसी मोहल्ले में एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ने के बाद ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि पूजा करना तक संभव नहीं रहा। संयोग कहिए कि संभल में हिंसा के बाद प्रशासन वहां कई स्तरों पर काम कर रही है जिनमें बिजली चोरी पकड़ना, अवैध अतिक्रमण समाप्त करना तथा धर्मस्थलों के लाउडस्पीकरों की ध्वनि को निर्धारित सीमा में किए जाने के नियम का कठोरता से पालन कराना शामिल है।

संभल के खग्गू सराय मोहल्ले में इसी अभियान में 46 वर्ष से बंद मंदिर मिला। दूसरा मंदिर वहां से लगभग साढ़े तीन किलोमीटर दूर सरायतरीन क्षेत्र के कायस्थान मोहल्ले में मिला। पहला 1978 के दंगे के बाद तो दूसरा 1992 के बाद बंद हो गया था। खग्गू सराय मंदिर सपा सांसद जियाउर्रहमान वर्क के घर से 200 मीटर और जिस शाही मस्जिद के सर्वे पर इतना बड़ा विवाद हुआ उससे 500 मीटर दूर है। जब मंदिर के दरवाजों पर पड़े ताले खुलवाए गए तो अंदर हनुमान जी की मूर्ति और शिवलिंग मिला। स्वाभाविक ही इस सूचना के साथ पूरे शहर में हलचल मच गया, लोग आने लगे और कई वरिष्ठ जनों ने बताना शुरू किया कि यहां क्या-क्या हो सकता है? किसी ने बताया कि सामने दिखते रैंप के नीचे अमृतकुंड था। जब जेसीबी से खुदाई की गई तो वाकई उसके नीचे कुआं मिला। इसकी खुदाई में भी कुछ मूर्तियां मिली हैं जिनमें गणेश जी और पार्वती जी की खंडित मूर्तियां हैं। क्यों?

संभल

अवधेश कुमार

अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के शहर में ऐसी स्थिति बनी तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार नहीं होती तो न पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने का साहस करता और न कब्जा करके धीरे-धीरे अस्तित्व मिटा देने की अवस्था में पहुंचे मंदिर का खुलना संभव होता। जितनी जानकारी आई है उसके अनुसार 29 मार्च, 1978 को संभल में साप्रदायिक हिंसा हुई थी। उसके बाद मोहल्ले के सारे हिन्दू पलायन कर गए। यही कायस्थान में हुआ जब हिंसा के बाद हिन्दुओं के करीब 100 परिवारों को वहां से पलायन करने को विवश होना पड़ा। 1978 के दंगों पर काम करने वाले, भुगतने वाले, आंखों देखने वाले बता रहे हैं कि उस दौरान खग्गू सराय मोहल्ले में अनेक हिन्दू घरों में आग लगा दी गई थी और लोग ऐसे बेसहारा हो गए कि उनके पास वहां से भगाने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। अगर मिले वर्तमान मंदिरों और विवादास्पद जामा मस्जिद की कहानी को ही ध्यान में रखें तो अनुमान लगाना कठिन नहीं होगा कि सारी हिंसा के पीछे कौन लोग हो सकते हैं और किन्हें इसका खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ा होगा। आज खग्गू सरय मोहल्ले में किसी हिन्दू का मतदाता सूची में नाम तक नहीं है। अनेक

मुस्लिम नेताओं और बुद्धिजीवियों का वक्तव्य है कि मंदिर बंद था तो उसे खोलना ही चाहिए लेकिन लोग वहां से क्यों चले गए? आज तक योगी सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? यह किस तरह का क्रूर बयान है? इसकी जगह मामला किसी मस्जिद का होता तो क्या ये लोग ऐसे ही वक्तव्य देते? वहां से 200-300 मीटर दूर हिन्दू आबादी है। कोई वहां आने का साहस नहीं जुटा पाता था। मंदिर संभालने वाले परिवार का बयान है कि पुजारी रखकर नियमित पूजा-अर्चना की कोशिश की गई, लेकिन डर इतना था कि कोई जाने का साहस नहीं जुटा सका।

धीरे-धीरे मुस्लिम समुदाय ने मंदिर के स्थानों को कब्जाना शुरू कर दिया। वहां जल ढालने के लिए स्थित पीपल का पेड़ भी काटा दिया गया। अब नक्शा देखकर पुलिस प्रशासन मंदिर के अतिक्रमित स्थान को खुलाछोर से घ्वस्त कर रहा है। लोग साहस करके मंदिर पर कब्जा करने वालों का नाम भी बता रहे हैं। कितनी भयावह स्थिति रही होगी कि जानते हुए भी हिन्दू समाज वहां मंदिर में पूजा करने का साहस इतने लंबे समय तक नहीं दिखा पाया। सरायतरीन कायस्थान मोहल्ले की घटना तो 32 वर्ष की है, लेकिन खग्गू सराय के मामले में इतना लंबा समय गुजरने के बाद जिनकी उम्र आज 50 - 55 की होगी उन्हें पता भी नहीं होगा कि कोई मंदिर था। किंतु ऐसे धर्मस्थलों का संस्कार स्मृतियां कभी समाप्त नहीं होने देता। एक-दो लोगों ने पूरे मंदिर का नक्शा तक बता दिया। मंदिर के दो कपाट हैं। पूरब में स्थित मुख्य प्रवेश द्वार को लगभग 30 वर्ष पहले 4 फीट दूरी पर दीवार खड़ा कर बंद कर दिया गया। निकासी द्वार उत्तर और दक्षिण की ओर है जिन पर ताला लगा हुआ था।

पाटा गया कूप दक्षिण द्वार के सामने था। सरायतरीन वाला मंदिर 15 फीट ऊंचा और 25 मीटर में बना है। आज वहां अनेक मंदिरों का अस्तित्व नहीं है। स्कंदपुराण, विष्णु पुराण से लेकर कई ग्रंथों के उद्धारण दिए जा रहे हैं जिसमें कलयुग में भगवान विष्णु के कल्की अवतार वहां होने का उल्लेख है। जिस हरि मंदिर की महत्ता के विवरण अंग्रेजों के सर्वे से लेकर आईने अकबरी और बाबरनामा में है उसका अस्तित्व नहीं है। इस्लामी आक्रमण के काल में बाबर से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक आदि द्वारा हिन्दू स्थलों को ध्वस्त करने के विवरण उपलब्ध हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भी वहां धर्मस्थल कब्जाया गया तथा 21 कुओं के बंद किए जाने की बात आई है। यह स्थिति जारी है तो मानना पड़ेगा कि उस मानसिकता के लोग आज भी हैं।

योगी आदित्यनाथ द्वारा पिछले दिनों संभल से बांग्लादेश तक हिंसा करने वालों के अंदर बाबर का डीएनए बताने पर हंगामा मचा है। उन्होंने आम मुसलमान के बारे में बात नहीं की। जो आज भी धर्मस्थलों पर कब्जा करना अपना मजहबी दायित्व मानते हैं और कब्जे किए गए जगह की छानबीन तक पर मरने-मारने को उतारू हैं उन्हें क्या माना जाए?

दुर्भाग्य है कि सेक्यूलरवाद के नाम पर हमारे देश के नेता और बुद्धिजीवी हमेशा जानते हुए भी इस कटु सच के विपरीत इसकी बात करने वाले या पीड़ित पक्ष को ही दोषी ठहराते हैं। संभल हिंसा में मृतकों के लिए छाती पीटने वाले हिंसा करने वालों के विरुद्ध कोई बोलने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1978 के दंगों के न्याय को लेकर जैसा कड़ा बयान दिया है तथा सरकार की जैसी प्रतिबद्धता दिखी है उससे उम्मीद पैदा हुई है मुकदमों के बंद फाइलें खुलेंगी, नये सिरे से न्याय होगा और केवल संभल नहीं पूरे प्रदेश में ऐसे उपासना या अन्य स्थलों का भी उद्धार होगा।

(लेख में विचार निजी हैं)

> संभल हिंसा में मृतकों के लिए छाती पीटने वाले हिंसा करने वालों के विरुद्ध कोई बोलने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1978 के दंगों के न्याय को लेकर जैसा कड़ा बयान दिया है तथा सरकार की जैसी प्रतिबद्धता दिखी है उससे उम्मीद पैदा हुई है मुकदमों के बंद फाइलें खुलेंगी, नये सिरे से न्याय होगा और केवल संभल नहीं पूरे प्रदेश में ऐसे उपासना या अन्य स्थलों का भी उद्धार होगा

भारत के
कालीन निर्यात
में यूपी की **60%** हिस्सेदारी

- भारत से 17 हजार करोड़ रुपये के कालीन का निर्यात होता है, इसमें 60 फीसद हिस्सेदारी यूपी के भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी की है
- उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीते साल कालीन के साथ ही लखनऊ की चिकनकारी, सीतापुर की दरी और बरेली की जरी-दरदोजी को प्रोत्साहित करने के लिए काफी प्रयास किए हैं। ये सभी शिल्प रोजगार सृजन के लिहाज से बेहद महत्त्वपूर्ण हैं

स्रोत - मीडिया इन्पुट्स

आज से नहीं, पिछली सदी के तीसरे दशक से ही हिन्दुत्व की राजनीति और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विचारों के दो विपरीत ध्रुव रहे हैं! बाबा साहेब की वैश्विक कीर्ति और देश में बहुजन जागरण की शुरुआत होने के दबाव के चलते हिन्दुत्ववादी आज मजबूरी में अम्बेडकर को सम्मान देने की औपचारिकता निभाते हैं!

उर्मिलेश, पत्रकार
@UrmileshJ

शोषण पर अंकुश जरूरी

उपभोक्ता दिवस | ललित गर्ग

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है। देश यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारतीय बाजार एक ऐसी आदर्श बाजार व्यवस्था को स्थापित करें जिसमें उपभोक्ताओं की ठगी की बढ़ती घटनाएं पर पूर्णतः नियंत्रण हो। इसके लिए उपभोक्ता में उत्पादकता और गुणवत्ता संवर्धित जागरूकता को बढ़ाने, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नाप-तौल, ठगी इत्यादि संकट से उपभोक्ता को मुक्ति दिलाने एवं उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी देकर उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से भारत में 24 दिसम्बर को 'राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

देश का प्रत्येक आदमी कहीं-न-कहीं ठगा जा रहा है। आनलाइन बाजार व्यवस्था एवं ई-बाजारवाद में ठगी की घटनाएं एक बड़ी समस्या एवं चुनौती बन गई है। सरकार ने उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून भी बनाया है। उन्हें जगाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी उपभोक्ता सोये हैं, क्योंकि दो तिहाई से ज्यादा आबादी अपने ही अधिकारों के प्रति सतर्क नहीं है। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए इसी दिन 24 दिसंबर, 1986 को भारत सरकार ने ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 लागू किया गया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है और इसके साथ ही अगर वह धोकाधड़ी, कालाबाजारी, घटतौली, ठगी आदि का शिकार होते है तो वह इसकी शिकायत कर सकें। इस कानून में जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक सामान और सेवाओं की बिक्री के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, खरीदी गई वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, स्तर और मूल्य, जैसा भी मामला हो, उसके बारे में जानकारी का अधिकार एवं इसके लिए आवाज उठाने का अधिकार है। बढ़ते बाजारवाद एवं उदारीकरण के इस दौर में जैसे ही हम अपनी जरूरत की कोई चीज या सेवा लेते हैं, तभी उपभोक्ता का ठग्गा हमारे ऊपर लग जाता है। कायदे से किसी चीज या सेवा के एवज में चुकाई जाने वाली कीमत में किसी भी तरह की गोखाधड़ी एवं ठगी नहीं होना चाहिए, लेकिन अक्सर उपभोक्ता ठगे जाते हैं। खराब गुणवत्ता की चीजें और सेवा प्रदाता से अपने अधिकारों के हक की लड़ाई ही जागरूक

उपभोक्ता की पहचान है। उपभोक्ता दिवस मनाते हुए हम केवल उपभोक्ता अधिकारों की ही बात नहीं करते बल्कि उपभोक्ता की उन्नत एवं सम्यक सोच को भी विकसित करते हैं। आर्थिक विसंगतियों एवं विषमताओं को दूर करने के लिए उपभोक्ता जागृति जरूरी है। आज का उपभोक्तावादी दृष्टिकोण एक प्रकार का सम्मोहन बन गया है। सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है, उनके हितों का संरक्षण भी किया जा रहा है, इसी की निष्पत्ति है 'जागो ग्राहक जागो' जैसे अभियान। उपभोक्ता अधिकारों पर काम करने वाली एनजीओ कट्स (सीयूटीएस) इंटरनेशनल ने समय-समय पर सर्वे के माध्यम से पता लगाया है कि कितने उपभोक्ता ठगे जाते हैं और कितने उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। उपभोक्ता मंत्रालय के व्यापक जागरूकता अभियान के बावजूद गलत उत्पाद बेचकर मुनाफा कमाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी ठगी के शिकार 90 प्रतिशत लोगों ने तो कभी शिकायत ही नहीं की है। चार से पांच प्रतिशत उपभोक्ता ही कंपनी या उत्पाद निर्माता के पास अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में आनलाइन खरीद और सोशल क्राइम में वृद्धि के चलते लोगों में अपने आप जागरूकता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्र के लोग कुछ ज्यादा जागरूक हुए हैं, लेकिन गांवों के लोग अभी भी अनजान हैं। हालांकि सुखद संकेत है कि कई मामलों में त्वरित समाधान मिलने से उपभोक्ता निवारण तंत्र पर भरोसा धीरे-धीरे बढ़ रहा है। ई-प्लेटफार्म पर भरोसा नहीं होने पर भी खरीदारी बढ़ रही है। एक सर्वे में बात आई है कि शहरों में 56 प्रतिशत उपभोक्ता आनलाइन खरीद करने लगे हैं। हालांकि अलग बात है कि उन्हें आनलाइन खरीदे गए उत्पादों की गुणवत्ता पर भरोसा फिर भी नहीं होता।

आज की बाजार शक्तियां उपभोक्ताओं का शोषण करती है। इन्ही उपभोक्तावादी एवं बाजार शक्तियों के कारण जीवन में सुख का अभिप्राय केवल भोग और उपभोग को माना जाने लगा है। ऐसे में झूठी शानो-शौकत के दिखावे के चक्कर में उपभोक्ता अविवेकशील होकर अनावश्यक चीजों को भी थैले में भरकर घर ला रहा है। बाजार एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के इस काले जादू के आगे उपभोक्ता बेवस एवं लाचार बहुत है, जिसके कारण वस्तुओं की गुणवत्ता के स्तर में गिरावट आ रही है। कोई भी चीज मिलाबटरहित मिलना अब संभव नहीं है। न चाहते हुए भी उपभोक्ता लूट का शिकार बन रहा है। इतना ही नहीं, उपभोक्तावादी संस्कृति ने भोगवादी जीवन जीने के लिए मनुष्य के समक्ष नए आयाम प्रस्तुत किए है तथा उसे सुविधाभोगी बना दिया है। इसी शोषण से मुक्त दिलाना ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की सार्थकता एवं उपयोगिता है।

सुख और दुख | ओशो

कोई आदमी दुख में है तो तुम कहते हो कि इतने परेशान क्यों होते हो! यह सब चलता रहता है; संसार है! अपने को जरा दूर रखो। और यही दुख तुम पर आएगा तो बड़े मजे की बात है कि हो सकता है, यही

आदमी, जिसको तुम सलाह दे रहे हो वह तुम्हें सलाह दे कि भाई, सुख दुख तो बाहर की वृत्तियां हैं। बात क्या है? कारण क्या है? कारण यह है कि जब दूसरे पर दुख आता है, तब तुम साक्षी हो। इसलिए ज्ञान उत्पन्न होता है। दूसरे पर दुख आ रहा है, तुम पर तो आ नहीं रहा है। तुम सिर्फ देखने वाले हो। इतने ही देखने वाले जब तुम अपने दुख के लिए हो जाओगे, तब इतना ही ज्ञान तुम्हें अपने प्रति भी बना रहेगा। तुमने अभी अपना ज्ञान बांटा है। मुल्ला नसरुद्दीन एक मनोचिकित्सक के पास गया और उसने कहा कि मेरी पत्नी की हालत अब खराब है, कुछ आपको करना ही पड़ेगा। मनोचिकित्सक ने अध्ययन किया उसकी पत्नी का कुछ सप्ताह तक और कहा कि इसका मस्तिष्क तो बिल्कुल खत्म हो गया है। नसरुद्दीन ने कहा कि 'वह मुझे पता था। रोज मुझे बांटती थी, मुझे देती थी। आखिर हर चीज खत्म हो जाती है।' तुम दूसरों को तो बुद्धि बांट रहे हो; लेकिन उसी बुद्धि का प्रयोग तुम अपने पर ही नहीं कर पाते। अब जब दुबारा तुम्हारे जीवन में सुख आए तो तुम उसे ऐसे देखना जैसे किसी और के जीवन में आया हो। तुम जरा दूर खड़े होकर देखने की कोशिश करना। जरा फासला चाहिए। थोड़ा-सा भी फासला काफी फासला हो जाता है। बिल्कुल सटकर मत खड़े हो जाओ अपने से। तुम अपने पड़ोसी हो। इतने सटकर मत खड़े हो जाओ। नसरुद्दीन से मैंने पूछा कि जो रास्ते के किनारे पर होटल है, उस होटल का मालिक कहता है कि तुम्हारा बहुत सगा-संबंधी है, बहुत निकट का। नसरुद्दीन ने कहा 'गलत कहता है। नाता है, लेकिन बहुत दूर का। बड़ा फासला है। हम एक ही बाप के बारह बेटे हैं। वह पहला है, मैं बारहवां हूं। बड़ा फासला है।' दूरी के बिना परिप्रेक्ष्य खो जाता है। कोई भी चीज देखनी हो तो थोड़ा-सा फासला चाहिए। तुम दर्पण में तुम बिल्कुल सिर लगा दो, कुछ भी दिखाई न पड़ेगा। जैसे-जैसे दूरी बढ़ती है, तुम रंग रोशन होकर देखोगे कि तुम व्यर्थ ही परेशान थे। जो घटनाएं तुम पर कभी घटी ही न थीं, तुमसे बाहर घट रही थीं, सिर्फ करीब खड़े होने के कारण प्रतिबिंब तुममें पड़ता था-उसी प्रतिच्छवि को तुम अपनी समझ लेते थे और परेशान होते थे।

रीडर्स मेल

संभल कर करें इस्तेमाल

विज्ञान ने हमें हर मौसम से बचने के लिए बहुत सी चीजें दी हैं, लेकिन अगर हम इनका सावधानी से प्रयोग न करें तो यह हमारे लिए कभी भी हानिकारक बन सकती हैं और अक्सर खबरें भी पढ़ने और सुनने को मिलती हैं कि इन चीजों के प्रयोग करती बार कोई हादसा हो गया। सर्दियों में गैस गीजर, कोयले की अंगीठी और अन्य गर्मी प्रदान करने वाले उपकरण लोगों की जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। लोगों को चाहिए कि जहां गैस गीजर लगा हो वहां हवा बाहर निकलने के लिए जगह होनी चाहिए अर्थात एडजोस्ट फैन बाथरूम में होना चाहिए। गैस सिलेंडर को बाथरूम में नहीं रखना चाहिए। बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, ऐसा करना जान पर भारी पड़ सकता है। बिजली से चलने वाले गीजर, हीटर, बल्बों और अन्य सभी का भी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। एक बात यह भी याद रखनी चाहिए कि बिजली से चलने वाले उपकरणों का प्रयोग घर, आफिस और अन्य जगहों पर भी जरूरत अनुसार ही करना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

ट्रंप के ऊटपटांग फैसले

ट्रंप को सत्ता में आने में अभी तीन हफ्ते और लगेंगे। मगर उनका पागलपन अभी से दिखने लगा है। वे कह रहे हैं जिन लोगों ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर आक्रमण किया था उन सब के सजा को खत्म कर दिया जाएगा। उसमें उन्होंने एक लाइन और जोड़ा कि 'जिन लोगों ने उन्हें सजा दिलाने के लिए मुकदमा दर्ज किया है उन्हें वे जेल भेजेंगे। इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा के, वे चाहेंगे कि अमेरीकियों को किसी तरह का आयकर न देना पड़े। इसके स्थान पर वे सभी आयातित वस्तुओं पर 10% टैरिफ और चीनी आयात पर 60% या उससे अधिक टैरिफ लगा देंगे। कनाडा और मेक्सिको से आयातित वस्तुओं पर 25 फीसद शुल्क तो 20 जनवरी 2025 से लगना शुरू भी हो जाएगा। इसके अलावा ट्रंप ने एक और विस्फोट कर दिया। उन्होंने कहा पनामा नहर का स्वामित्व को उनका देश फिर से हासिल करेगा। इसका मतलब ये हुआ के आने वाला 2025 में संघर्ष का एक और क्षेत्र खुलने जा रहा है, ये तय है।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

संघ प्रमुख की दो टूक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिन्दूवादी छवि बनाने को इतने आतुर हैं कि वह हर विवादित स्थल पर अपना धार्मिक स्थल देख रहे हैं। न केवल देख रहे हैं बल्कि उसका सव; कराकर उसकी खुदाई भी करवा रहे हैं। पूरा भगवा महकमा ढूंढ-ढूंढ कर छिपे मंदिर खोज रहा है। ऐसी धार्मिकता अब प्रदेशन की चीज बन गई है। ऐसी धार्मिकता का अंतकरण की शुद्धि से कोई संबंध नहीं होता। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ठीक ही कहा है कि वह हर जगह मंदिर-मस्जिद विवाद ढूंढना बंद करें। हो सकता है इस तरह के विवादों में लोग एक दम उग्र हो जाए बाद में समझ आने पर अलग थलग हो जाते हैं। आज लोग हिन्दूवादी नेता बनने की जोर आजमाइश कर रहे हैं। भागवत का इशारा अपने ही राजनीतिक दल के लिए है। संघ प्रमुख ने ऐसे लोगों को आईना दिखाया है। अब हिन्दूवादी नेता इसे आइ लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना बंद करें।

दिलीप कुमार गुप्ता, बरेली
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काजी द्वारा सहारा हीवन पक्ष कम्युनिकेशन टेक, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवीन हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
प्रधान संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश सिंह*।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23362368, 23362369, 23362371, 23362372, फैक्स - 23362370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 127
अप.एस.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी दायरों के लिए उत्तरदायी

चिंतन

नो डिटेंशन नीति खत्म होने से शिक्षा के स्तर सुधरेंगे

केंद्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए एक और कदम उठाया है। 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल होने पर अब विद्यार्थी प्रोमोट नहीं होंगे। फेल होने वालों को दो महीने में दोबारा परीक्षा में भाग लेना होगा। उसमें भी फेल होने पर हालांकि बच्चे स्कूल से नहीं निकाले जाएंगे, लेकिन वे अगली कक्षा में नहीं जा सकेंगे, उन्हें उसी कक्षा में रहना होगा। दरअसल, हाल के वर्षों में परीक्षा में पास होने के दबाव के चलते बच्चों में तनाव बढ़ने और आत्महत्या के मामले सामने आने के बाद सरकार ने 5वीं व 8वीं कक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को भी प्रोमोट करके अगली कक्षा में जाने का प्रावधान कर दिया था, इससे बच्चों की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिर रहा था। इसलिए सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी है। नई शिक्षा नीति पहले से ही काफी उदार और लर्निंग आधारित है। उसमें ऐसी नीति की जरूरत भी नहीं है। केंद्र सरकार की नई पॉलिसी का असर केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित करीब तीन हजार से ज्यादा स्कूलों पर पड़ेगा। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश (दिल्ली और पुडुचेरी) नो-डिटेंशन पॉलिसी पहले ही खत्म कर चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए राज्य इस संबंध में अपना निर्णय ले सकते हैं। 2016 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन (सीएबीई) ने तबके मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) को 'नो डिटेंशन पॉलिसी' हटाने का सुझाव दिया था। सीएबीई ने तब तर्क दिया था कि इस पॉलिसी की वजह से विद्यार्थियों के सीखने का स्तर गिर रहा है। शिक्षा पर टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी और सीएबीई के तहत बनाई गई वासुदेव देवनानी कमेटी ने नो डिटेंशन पॉलिसी को रद करने की सिफारिश की थी। यह बात भी प्रकाश में आई कि, नो डिटेंशन पॉलिसी के अंतर्गत छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों के पास पर्याप्त साधन नहीं थे। अधिकतर मामलों में छात्रों का उचित मूल्यांकन ही नहीं किया जाता था। देशभर में 10 फीसदी से भी कम स्कूलों में नो डिटेंशन पॉलिसी के हिसाब से शिक्षक और मूल्यांकन ढांचा पाया गया। इस नीति में स्कूलों का जोर अधिक से अधिक दाखिले पर था, जबकि पठन-पाठन का स्तर गिरता रहा। इससे छात्र पढ़ाई के प्रति लापरवाह होते गए, क्योंकि उन्हें फेल होने का डर ही नहीं था। नो डिटेंशन पॉलिसी राइट टू एजुकेशन 2009 का हिस्सा थी। ये सरकार की पहल थी, जिससे भारत में शिक्षा की स्थिति में सुधार हो सके। इसका उद्देश्य था कि बच्चों को शिक्षा के लिए बेहतर माहौल दिया जा सके ताकि वो स्कूल आते रहें। उस वक्त माना गया कि फेल होने से विद्यार्थी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है व बच्चे शर्म महसूस करते हैं जिससे पढ़ाई में वो पिछड़ सकते हैं। कई टीशन में आ जाते हैं। इसलिए नो डिटेंशन पॉलिसी लाई गई जिसमें 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाता था। जुलाई 2018 में लोकसभा में राइट टू एजुकेशन को संशोधित करने के लिए बिल पेश किया गया था। इसमें स्कूलों में लागू 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म करने की बात थी। इसके अनुसार 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नियमित परीक्षा की मांग की गई थी। इसी के साथ फेल होने वाले विद्यार्थियों के लिए दो महीने के अंदर री-एग्जाम कराने की भी बात थी। 2019 में यह बिल राज्यसभा में पास हुआ। इसके बाद राज्य सरकारों को ये हक था कि वो नो डिटेंशन पॉलिसी हटा सकते हैं या लागू रख सकते हैं। कई राज्यों ने इस नीति को हटा दी थी। अब जबकि केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन नीति को खत्म कर दी है, तो यह अब पूरे देश में लागू हो जाएगा। केंद्र के इस कदम से प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार देखने को मिलेगा। अब विद्यार्थी अपनी शिक्षा को लेकर लापरवाह नहीं रहेंगे। इससे वे पढ़ाई पर ध्यान देंगे।

खोज

डा. मोनिका शर्मा

कैंसर वैक्सीन : जीवन सहेजने की जगी आशा

कैंसर की व्याधि हमारे देश में ही नहीं दुनियाभर में एक बड़ी आबादी का जीवन लीलने वाली बीमारी बन गई है। यही वजह है कि रूस द्वारा कैंसर की वैक्सीन बना लेने का दावा इस भयावह रोग से जूझती दुनिया के लिए जीवन सहेजने की आशा को बल देने वाला है । इस जानलेवा बीमारी से दुनिया के हर भू-भाग पर बसे लोग जंग लड़ रहे हैं हर आयु वर्ग की महिलाएं और पुरुष कैंसर का शिकार बन रहे हैं । यहाँ तक कि बच्चे भी इस व्याधि के घेरे में आ रहे हैं। ऐसे में कैंसर के विरुद्ध जीवन की जंग जीतने का रूस द्वारा किया गया दावा समग्र वैश्विक समाज की उम्मीदों से जुड़ा है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि कैंसर के इलाज के लिए एक वैक्सीन विकसित कर ली गई है। कैंसर की रोकथाम के लिए नहीं, बल्कि कैंसर से जूझ रहे मरीजों के इलाज में उपयोगी इस टीके को बना लिए जाने की पुष्टि वहाँ के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के प्रमुख आंद्रेई कैप्रिन ने की है । साथ ही यह भी कहा गया है कि इस वैक्सीन को 2025 की शुरुआत से मरीजों को निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

चिंतनीय है कि हमारे देश में भी इस जानलेवा व्याधि के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हमारे यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख से अधिक कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। दुनियाभर में कैंसर के सबसे अधिक रोगियों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर है। वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड इंटरनेशनल का अध्ययन बताता है कि सबसे अधिक कैंसर के मामले चीन में हैं । उसके बाद अमेरिका और तीसरे नंबर पर भारत है। चीन में लगभग 48 लाख, लगभग 23 लाख और भारत में करीब 14 लाख से ज्यादा लोग कैंसर की जद में हैं। भारतीय महिलाओं में तो स्तन कैंसर की व्याधि बड़ा जोखिम बन गई है । भारत में 2022 में सामने 14.13 लाख कैंसर के मामलों में 9.16 लाख लोगों की मौत हुई थी। कुछ समय पहले हुए अध्ययन मुताबिक स्तन कैंसर कुल कैंसर मामलों का 13.5 प्रतिशत था। यह आंकड़ा हमारे देश में होने वाली सभी मौतों में 10.6 प्रतिशत है। चिंतनीय है कि हमारे यहाँ इलाज की शुरुआत करने वाली 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं स्तन कैंसर के चरण 3 और 4 से पीड़ित होती हैं। परिणामस्वरूप बड़े शहरों से लेकर गांवों-कस्बों तक, स्तन कैंसर की व्याधि स्त्रियों का जीवन लील रही है । इन हालातों में कैंसर रोगियों के बढ़ते आंकड़ों से जुड़ी सबसे बड़ी चिंता यही है कि अभी तक इस बीमारी का कोई टीका उपलब्ध नहीं है। विडम्बना ही है कि हमारे देश को आज दुनिया का कैंसर कैपिटल कहा जाने लगा है । तंबाकू के बढ़ते इस्तेमाल से लेकर पर्यावरण प्रदूषण और असंयमित जीवनशैली तक, अनगिनत कारण इस व्याधि का आंकड़ा बढ़ा रहे हैं । चिकित्सकों ने भी चेताया है कि आगामी वर्षों में इस लाइलाज बीमारी के हालात और बिगड़ सकते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार अगले दशक में कैंसर रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ने की संभावना है। 2040 तक कैंसर पीड़ितों का आंकड़ा के दोगुना होने का अनुमान है।

दुखद है कि रोगी को शारीरिक-मानसिक मोर्चे पर कमजोर करने वाली इस व्याधि का लंबा चलने वाला इलाज परिवार को भी आर्थिक रूप से कमजोर कर देता है । इतना ही नहीं यह स्थिति स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी के मुताबिक हमारे यहाँ मुख, फेफड़े, स्तन, गर्भाशय ग्रीवा और पेट के कैंसर के मामले सबसे अधिक हैं। सांस्कृतिक यानी जीवनशैली जनित स्थितियाँ और पर्यावरणीय परिस्थितियाँ इनका अहम कारण हैं । विशेषकर युवा वर्ग में बढ़ रहे कैंसर के मामले धूम्रपान, शराब सेवन, निष्क्रिय-तनावपूर्ण जीवनशैली और अस्वास्थ्यकर भोजन से गहराई से जुड़े हैं। ऐसे में जागरूक सोच, सजगता और स्वस्थ जीवनशैली से ही इस व्याधि को परास्त किया जा सकता है । साथ ही अच्छी चिकित्सा व्यवस्था और सटीक उपचार भी जीवन सहेजने के लिए आवश्यक हैं । यही वजह है कि इस बीमारी के निदान और उन्नत इलाज से जुड़े अध्ययनों के सकारात्मक परिणामों की प्रतीक्षा दुनिया के हर देश को है ।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

बीस वैश्विक सर्वोच्च सम्मान के मायने

विश्लेषण
ओमकार चौधरी

नरेन्द्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'आर्डर आफ़ मुबारक अल कबीर' से सम्मानित किया गया। इस्लामिक देशों की ओर से पहली बार उन्हें इस तरह का सम्मान नहीं मिला है, इससे पूर्व भी कई मुसलिम देश उन्हें अपने यहां के 'सर्वोच्च सम्मान' से नवाज़ चुके हैं। क़रीब साढ़े दस साल में उन्हें दुनिया के बीस देशों का शिखर सम्मान मिल चुका है। यह अपने आप में अनूठा कीर्तिमान है क्योंकि उनसे पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री को दुनिया में इतना सम्मान नहीं मिला। उन्हें 2016 में दो देशों ने, 2018 में फिलिस्तीन, 2019 में यूएई, बहरीन और मालदीव, 2020 में अमेरिका ने, 2023 में पाँच देशों ने जबकि 2024 में अब तक सात देशों ने सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया है।

तेरह सितंबर 2013 को जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2014 के लिए प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया, तब कांग्रेस सहित विपक्ष के कई दलों ने नाक-भौं सिकोड़ते हुए नुक्ताचीनी की थी। तब के केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा था कि वो तो कूप मंडूक हैं। गुजरात के बाहर वो जानते ही क्या हैं ? बतौर प्रधानमंत्री मोदी विदेश नीति पर कैसे काम करेंगे, उन्हें तो कुछ जानकारी ही नहीं है। बाद में इससे और दो कदम आगे बढ़कर तात कटोरा स्टेडियम में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के मौके पर मौडिया में मणिशंकर अय्यर ने वो आत्मघाती बयान दे डाला था कि नरेन्द्र मोदी इक्कीसवीं सदी में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। वो चाहें तो यहां चाय की दूकान खोल लें, हम उन्हें जमीन उपलब्ध करा देंगे। नरेन्द्र मोदी 2014 में न केवल भारत के प्रधानमंत्री बने बल्कि वो 2019 में भी पीएम चुने गए और अब 2024 में तीसरी बार देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके प्रमाणिक नेतृत्व के कारण ही नागरिकों ने लगातार तीसरी बार कांग्रेस और उसके नेतृत्व राहुल गांधी को नकार दिया। रविवार को उन्हीं नरेन्द्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'आर्डर आफ़ मुबारक अल कबीर' से सम्मानित किया गया। इस्लामिक देशों की ओर से पहली बार उन्हें इस तरह का सम्मान नहीं मिला है, इससे पूर्व भी कई मुसलिम देश उन्हें अपने यहां के 'सर्वोच्च सम्मान' से नवाज चुके हैं। क़रीब साढ़े दस साल में उन्हें दुनिया के बीस देशों का शिखर सम्मान मिल चुका है। यह अपने आप में अनूठा कीर्तिमान है क्योंकि उनसे पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री को दुनिया में इतना सम्मान नहीं मिला। उन्हें 2016 में सऊदी अरब और अफ़ग़ानिस्तान ने, 2018 में फिलिस्तीन, 2019 में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और मालदीव, 2020 में अमेरिका ने, 2023 में पाँच देशों फिजी, पापुआ न्यू गिनी, मिस्र, फ्रांस और ग्रीस ने जबकि 2024 में अब तक सात देशों रूस, भूटान, नाइजीरिया, डोमिनिका, गुयाना, बारबाडोस और कुवैत ने सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया है।

जहां तक कुवैत द्वारा दिए गए इस 'सम्मान' का प्रश्न है, 'ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर' उसका प्रतिष्ठित नाइटहुड पुरस्कार है, जो राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। इससे पहले यह सम्मान बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसी हस्तियों को दिया जा चुका है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। यह कुवैत के ऐतिहासिक नेता मुबारक अल-सबाह की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने 1897 में कुवैत को स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित किया था।

2014 में जब मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी, तब अपने शपथ समारोह में सार्क देशों के प्रमुखों को आमंत्रित तक उन्होंने आस-पड़ोसियों से रिश्ते मजबूत करने के संकेत दे दिए थे । पहले पाँच वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने दुनिया के ऐसे कई देशों की यात्रा कीं, जहां दशकों से कोई प्रधानमंत्री गया ही नहीं था। दुनिया की प्रमुख शक्तियों से उन्होंने दोस्ताना रिश्तों को न केवल नई ऊर्जा प्रदान की अपितु भारत में पूंजी निवेश का मार्ग भी प्रशस्त किया। वह जहां भी गए, वहां की बड़ी

कंपनियों के सीईओ और औद्योगिक घरानों के प्रमुखों से बात की और उन्हें भारत आमंत्रित भी किया। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टर से लेकर तमाम प्रोजेक्ट और कार्यक्रमों के जरिए न केवल भारतीय टेलेंट को अवसर उपलब्ध कराए बल्कि दुनिया के लिए द्वार खोले । जहां आवश्यकता अनुभव की, वहां वाइब्रेंट गुजरात का मॉडल भी लागू किया । अपने दूसरे कार्यकाल में वह इन रिश्तों को दूसरे पायदान पर ले गए। विकसित ही नहीं, कई विकासशील देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ उनकी निकटता और घनिष्ठता रंग लाती हुई दिखाई देने लगी । सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का प्रश्न हो अथवा वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका हो, उनके प्रयासों की धमक सुनाई देने लगी। यह उनकी स्वतंत्र और आक्रामक परंतु सूझ-बूझ वाली कूटनीति का ही नतीजा था कि जब यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ने के बाद अमेरिका और नाटो देशों ने रूस को दुनिया में अलग-थलग करने की कोशिश की, तब भारत मजबूती के साथ अपने पुराने मित्र के साथ खड़ा नजर आया।

2014 के बाद की विश्व की घटनाओं, दुर्घटनाओं, आपदाओं और बदले हुए वर्ल्ड आर्डर पर जब नजर दौड़ाते हैं तो बहुत सारी चीजें जेहन में उतर आती हैं। कोविड का विनाशकारी काल हो या चीन की ओर से इस पूरे क्षेत्र में कई देशों के समक्ष पेश की जा रही चुनौती हो, कई देशों की उथल-पुथल रही हो या रूस-यूक्रन, इजरायल-हमास-हिजबुल्ला-ईरान के बीच की जंग, मोदी की अगुआई में भारत ने बेहद सूझ-बूझ के साथ हर चुनौती का सामना किया है और इन सभी घटनाक्रमों में एक सार्थक भूमिका भी अदा की है। यूक्रेन युद्ध के आलाप में भारत के रूस के साथ रिश्तों को लेकर अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की । वहां से ईंधन न खरीदने का प्रेशर डाला। उससे एस-400 प्रणाली न खरीदने को कहा परंतु भारतीय नेतृत्व ने उसे हिंदी में समझा दिया कि उसकी विदेश नीति का आधार सर्वोच्च राष्ट्रहित है। यह सही है कि पिछली डेढ़-दो दशक में हमारे अमेरिका से रिश्ते बहुत बेहतर हुए हैं परंतु बराक ओबामा रहे हों या ट्रंप, बीच में बाइडन आए हों या अब फिर से ट्रंप अमेरिका की कमान संभालने जा रहे हों, सबको संदेश साफ़ है कि भारत उनके साथ मित्रता के भाव से काम करेगा, किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगा। हमारे आस-पड़ोस में भी इस दौरान काफी उथल-पुथल रही। श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान में सरकारों के तख्ते उलट दिए गए। पाकिस्तान में आर्थिक संकट भी रहा और हमेशा की तरह सरकार-सेना के बीच उठा-पटक भी । नेपाल की चीन परस्ती हो या बांग्लादेश में कट्टरपंथी तत्वों की हरकतें, भारत ने इन सबसे शानदार तरीके से डील किया है और हर घटना पर रिएक्ट करते समय भारतीय हितों को सर्वोच्च रखा है।

मोदी के नेतृत्व वाले बदले हुए भारत दुनिया को यह संदेश भेजने में सफल रहा है कि वह अब केवल बिग-मार्केट नहीं है उनके लिए। वह पांचवीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी बनने की दिशा में बढ़ रहा है । जानी-मानी मल्टीनेशनल कंपनियों और प्रतिभाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खोल चुका है। विश्व के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों में अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है। नई दिल्ली में जी-20 देशों के सफल सम्मिट के उपरांत दुनिया के देशों ने मोदी की लीडरशिप क्वालिटी का लोहा माना है। जिन्हें वहम था कि वह गुजरात के कूप मंडूक हैं, वो अब मुँह छुपाते घूम रहे हैं ।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

मृत्युंजय मंत्र यानी मृत्यु पर विजय का मंत्र

संकलित
दर्शन

शिव का मृत्युंजय मंत्र वैदिक परंपरा में सबसे प्रतिष्ठित मंत्रों में से एक है। मृत्युंजय का अर्थ है मृत्यु पर विजय। आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है। यह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। मृत्युंजय का अर्थ है क्षणभंगुर पर मन की विजय और शाश्वत की ओर बढ़ना। जब मन को यह एहसास होता है कि मैं शाश्वत हूं। मुझमें कुछ ऐसा है जो बदल नहीं रहा है। फिर कोई भय नहीं रहता। भय मृत्यु के लक्षणों में से एक है। जब आप भय पर विजय प्राप्त करेंगे, तब नाशवान के साथ पहचान की लघु मानसिकता पर विजय प्राप्त कर लेंगे और अविनाशी की ओर बढ़ेंगे। हम इन दोनों का मिश्रण हैं। हमारी आत्मा अविनाशी है और शरीर नाशवान है। अक्सर हमारा मन नाशवान से जुड़ा होता है और उसे लगता है कि वह मर रहा है। मृत्युंजय मंत्र हमारे मन को सीमित पहचान से असीमित पहचान की ओर ले जाता है। इसमें एक प्रार्थना है- शिव मुझे सबल बनाएं। उन्हें मुझे दृढ़ बनाने दो, वह मुझे बंधन से मुक्ति दिलाएं। आमतौर पर लोग पूछते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है? सृजन का उद्देश्य क्या है? यह ब्रह्मांड किसी स्थान पर जाने की यात्रा नहीं है। सृष्टि का कोई उद्देश्य नहीं है। यह मात्र चेतना का एक खेल और प्रदर्शन है। जैसे नर्तक और नृत्य अलग नहीं हो सकते, वैसे ही सृष्टि और रचयिता दो अलग वस्तुएं नहीं हैं। इस सत्य को नटराज (शिव के रूपों में से एक) के रूप में दर्शाया गया था। नटराज स्वयं चेतना हैं, उनमें पांच तत्वों को दर्शाया गया है। चेतना का नृत्य संपूर्ण ब्रह्मांड है।

गुरु की सीख से मुश्किलें होती है दूर

संकलित
प्रेरणा

बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। महाभारत के आदि पर्व के मुताबिक, बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं और अपने ज्ञान से देवताओं का मार्गदर्शन करते हैं। एक कथा है कि एक बार देवराज इंद्र की जगह राजा नहुष को स्वर्ग का राजा बनाया गया था। स्वर्ग का राजा बनते ही राजा नहुष अहंकारी हो गया। वह देवताओं को तरह-तरह से परेशान करता रहता था। सभी देवगण राजा नहुष से त्रस्त हो गए थे। इसी बीच बलशाही होने के कारण राजा नहुष के मन में इंद्र की पत्नी शची के लिए पाप आ गया। वह उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। इससे डरकर शची देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचीं। बृहस्पति ने शची को एक योजना बताई। बृहस्पति ने शची से कहा कि आप नहुष से कहना कि जब वह सप्त ऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में बैठकर आएगा, तब ही वह उसे अपना स्वामी मानेंगी। शची ने यही किया। बृहस्पति की योजना के अनुसार शची ने ये बात नहुष से कह दी। नहुष ने ऐसा ही किया। सप्तऋषि जब पालकी उठाकर चल रहे थे, तभी अहंकारी राजा नहुष ने एक ऋषि को लात मार दी। क्रोधित होकर ऋषि ने उसे उसी समय स्वर्ग से गिरने का शाप दे दिया। शाप के बाद राजा नहुष ने स्वर्ग का राजपाठ खो दिया। इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति की सलाह से शची की रक्षा हो गई। गुरु की सीख से बड़ी-बड़ी मुश्किलें दूर हो सकती हैं।

महाकुंभ 2025

प्रयागराज में सोमवार को महाकुंभ मेले से पूर्व नागा साधु रुद्राक्ष की माला पहने धुनी रमाते हुए।

आज की पाती

किसानों से संवाद जरूर हो

23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किसानों की दशा और उनकी जिंदगी में सुधार लाने के लिए अपने कार्यकाल में उनके लिए बहुत-सी नीतियों को हरी झंडी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसानों की दशा सुधरेगी तो देश सुधरेगा। उन्होंने किसानों की दशा सुधारने के लिए देश को आजाद होने से पहले भी और बाद में भी खूब प्रयास किए। उनकी कोशिश की वर्ष 1952 में जमींदारी उन्मूलन विधेयक पारित हो सका था। आज स्थिति यह है कि किसानों की समस्याओं की तरफ गंभीरता दिखाने वाले कम और उनके मुद्दों पर राजनीति करने वाले राजनीति में बहुत हो गए हैं। किसान आज आंदोलित हैं। सरकार को गंभीरता से उनके साथ संवाद करना चाहिए।

- मदन बंद्राकर, दुर्ग

ट्रेंड

सिंह किसानों को समर्पित

पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह किसानों के सच्चा हितैषी के लिए प्रतिबद्ध थे। कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बुनियादी आधार हैं। 12वीं जयंती पर श्री सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह संकल्प लेने का अवसर है कि भारत के उत्थान के लिए कृषि अहम है। -नागेंद्र धलाइ, उपराष्ट्रपति

किसान दिवस की शुभकामनाएं

किसान ही हिन्दुस्तान है। सभी किसान बाबा-बाइयों को, खेत-खलिहानों को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के किसानों के लिए संघर्षरत रहे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। -मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस अध्यक्ष

सबकी नीयत में खोट

संविधान के निर्माता डा. बीआर आंबेडकर का अपमान/अपमान व उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति हीन मानसिकता का दुखद परिणाम है कि परसाणी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं। संविधान के प्रति कर्तव्य व मानवता आदि कोई इनका तथा हितैषी नहीं। सबकी नीयत, नीति में खोट है।। - मायावती, बसपा प्रमुख व पूर्व सीएम

यूपी क्राइम में नंबर वन

उत्तर प्रदेश अब 'इज ऑफ डूइंग क्राइम' में हुआ नंबर एक। आज तक उपेक्षित... लखनऊ का ओकलीज बैंक, जहाँ लॉकर धारकर बहुमूल्य सामान छोड़े हुए। वाल सहारनपुर में बैंक लूटा गया। -अखिलेश यादव, पूर्व सीएम

करंट अफेयर

टिकटॉक पर प्रतिबंध जल्दबाजी में नहीं

अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा वीडियो सेवा 'टिकटॉक' पर शनिवार को लगाया गया प्रतिबंध, 'किसी एक घटना पर जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है।' अल्बानिया के प्रधानमंत्री ने शनिवार को 'टिकटॉक' पर, खासकर बच्चों में, हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए उसे एक साल के लिए बंद किए जाने की घोषणा की थी।

अल्बानियाई अधिकारियों ने नवंबर के मध्य में 'टिकटॉक' पर शुरू हुए झगड़े के उपरांत एक विशोर की दूसरे विशोर द्वारा छाछू घोंपकर हत्या किए जाने की घटना के बाद शिक्षकों और अभिभावकों के साथ 1,300 बैठकें कीं। उनमें से 90 प्रतिशत ने 'टिकटॉक' पर प्रतिबंध का समर्थन किया। रामा ने रविवार को कहा, 'अल्बानिया में एक साल के लिए टिकटॉक पर प्रतिबंध, किसी एक घटना को लेकर जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि देशभर के स्कूलों में अभिभावक के परामर्श के बाद सोच-समझकर लिया गया फैसला है।' वहीं, टिकटॉक ने वाछू घोंपने वाले विशोर के मामले में अल्बानिया सरकार से तत्काल स्पष्ट जानकारी मुहैया कराने को कहा है। कंपनी ने कहा कि उसे 'इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि अपराधी या पीड़ित का 'टिकटॉक अकाउंट' था।

ऑफ बीट

काम से उचित ब्रेक लेना स्वास्थ्य के लिए अच्छा

हमेशा काम में ही जुटे रहना ठीक नहीं होता। यहां तक कि जब हम छुट्टी पर होते हैं, तब भी हमारे फोन और लैपटॉप हमें व्यस्त रखते हैं। हममें से कई लोग

खुद से वादा करते हैं कि हम छुट्टी के दौरान ईमेल नहीं देखेंगे। लेकिन हम ऐसा ही करते हैं। कार्यस्थल से दूर होना और यहां तक कि किसी नए स्थान पर होना भी, मनोदैहानिक रूप से अवसर काम से दूरी के लिए पर्याप्त नहीं होता है। हम छुट्टियों के दौरान भी उस 'प्रोजेक्ट' के बारे में सोच रहे होते हैं जिसे हमें जल्द से जल्द पूरा करना है या फिर हमारे बजाय किसी और के उस 'प्रोजेक्ट' से जुड़ने के कारण हम खुद को दोषी महसूस कर सकते हैं। 'डिजिटल मौजूदगी' हमारे नियोक्ताओं ने भले ही स्पष्ट रूप से नहीं कहा हो, लेकिन फोन और लैपटॉप के होने से हमेशा यह अपेक्षा बनी रहती है कि हम किसी भी वक्त आसानी से उपलब्ध रहेंगे, यहां तक कि काम के सामान्य कार्य घंटों के अलावा भी हमसे काम के लिए उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है। जुड़ाव या 'डिजिटल उपस्थिति' की यह भावना, हमें तनावग्रस्त, चिंतित और थकान पैदा कर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, जब हम कार्यालय से बाहर हों या छुट्टी पर हों तो अपने कार्य उपकरणों को बंद करके इन समस्याओं से दूर रह सकते हैं।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

सम्पादकीय

इस महीने के अंत तक भरी जाएंगी मेडिकल सीट, स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति देख लिया गया फैसला

भारत में चिकित्सकों की कमी को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे रेखांकित किया है। दरअसल, अदालत ने मेडिकल कालेजों के चिकित्सा पाठ्यक्रमों में खाली पड़ी सीटों को भरने का निर्देश देते हुए कहा कि देश में डाक्टरों की पहले ही इतनी कमी है, उसमें सीटें बर्बाद नहीं जानी चाहिए। इस महीने के अंत तक काउंसिलिंग करा कर उन सीटों को भरा जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की दुर्दशा पर जब-तब सवाल उठते रहते हैं।

लगभग सभी अस्पतालों में चिकित्सकों के बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। इस मामले में ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों की दशा सबसे खराब है। सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि मार्च 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सर्जन, चिकित्सकों, स्त्री रोग विशेषज्ञों और बाल रोग विशेषज्ञों की लगभग अस्सी फीसद कमी थी। यूनेस्को भी कई बार बता चुका है कि भारत में एक हजार लोगों पर एक से भी कम चिकित्सक हैं। ऐसी स्थिति में, अगर चिकित्सक तैयार ही नहीं होंगे, तो इस कमी को पूरा कैसे किया जा सकेगा। हालांकि सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी के अन्य कई कारण भी स्पष्ट हैं। पहले तर्क दिया जाता था कि हमारे यहां इसलिए जरूरत के मुताबिक योग्य चिकित्सक नहीं तैयार हो पा रहे कि मेडिकल कालेजों में सीटें बहुत कम हैं। इसके मद्देनजर कुछ नए कालेज खोले गए और सभी कालेजों में सीटें बढ़ा दी गईं। इस तरह पिछले दस वर्षों में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ कर करीब दोगुनी हो गई हैं।

इसके अलावा हर वर्ष हजारों विद्यार्थी विदेशी संस्थानों से पढ़ाई करके वापस लौटते हैं। फिर, निजी अस्पतालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उनमें चिकित्सकों की कमी नजर नहीं आती। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी की बड़ी वजह उनमें भर्तियों पर गंभीरता से ध्यान न दिया जाना है। ग्रामीण इलाकों में चिकित्सकों की कमी दूर करने के मकसद से नियम बनाया गया था कि चिकित्सा की पढ़ाई के बाद हर डाक्टर को कम से कम एक वर्ष ग्रामीण इलाकों में जाकर सेवा देनी होगी, मगर उस नियम का गंभीरता से पालन नहीं हो पाता। हर डाक्टर शहर में रहना चाहता है। वहां उसे कमाई के अधिक मौके नजर आते हैं। इन स्थितियों में शीर्ष अदालत की टिप्पणी को न केवल मेडिकल कालेजों में खाली पड़ी सीटों, बल्कि व्यापक अर्थ में लेने की जरूरत है। चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले को लेकर इसीलिए अधिक संघर्ष देखा जाता है कि वहां से निकलने के बाद युवाओं को एक तरह से रोजगार की गारंटी होती है। वे निजी तौर पर भी अपना चिकित्सालय खोल कर अच्छी कमाई कर लेते हैं। मगर चिंता उस बहुसंख्यक आबादी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने को लेकर है, जो अपने इलाज पर पैसे खर्च कर पाने में सक्षम नहीं है। फिर, बहुत सारे योग्य चिकित्सक बेहतर वेतन और सुविधाओं के मोह में दूसरे देशों का रुख कर लेते हैं। यही वजह है कि अनेक रोगों के विशेषज्ञों की भारी कमी बनी हुई है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर विशेष

उपभोक्ता के बढ़ते शोषण पर अंकुश जरूरी

उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए इसी दिन 24 दिसंबर, 1986 को भारत सरकार ने ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 लागू किया गया था। इस अधिनियम एवं बाद में किये गये संशोधनों का उद्देश्य उपभोक्ताओं का दोषपूर्ण वस्तुओं, लापरवाह सेवाओं एवं अनुचित व्यापार प्रथाओं से संरक्षण करना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के छह मौलिक अधिकार सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, सूचित किये जाने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण पाने का अधिकार एवं उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार हैं। यह दिन भारतीय ग्राहक आन्दोलन के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है।

ललित गर्ग

भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है और यह आजादी की शताब्दी वर्ष 2047 तक उच्च मध्य आय के दर्जे तक पहुंचने की आकांक्षा के साथ विश्व बाजार बनने के पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। देश यह भी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारतीय बाजार एक ऐसी आदर्श बाजार व्यवस्था को स्थापित करें जिसमें उपभोक्ताओं की ठगी की बढ़ती घटनाएं पर पूर्णतः नियंत्रण हो। इसके लिये उपभोक्ता में उत्पादकता और गुणवत्ता संबंधित जागरूकता को बढ़ाने, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नाप-तौल, ठगी इत्यादि संकटों से उपभोक्ता को मुक्ति दिलाने एवं उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के बारे में लोगों को जानकारी देकर उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में उपभोक्ता का मतलब ही ठगी का शिकार हो गया है। देश का प्रत्येक आदमी कहीं न कहीं अक्सर ठगा जा रहा है। आनलाइन बाजार व्यवस्था एवं ई-बाजारवाद में ठगी की घटनाएं एक बड़ी समस्या एवं चुनौती बन गयी है। सरकार ने उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून भी बनाया है। उन्हें जागने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। फिर भी उपभोक्ता सोये हैं, जबकि मुनाफे के लिए छल के नए-नए तरीके आजमाए जा रहे हैं, क्योंकि दो तिहाई से ज्यादा आबादी अपने ही अधिकारों के प्रति सतर्क नहीं है।

उपभोक्ता संरक्षण कानून से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यह है की किसी भी शासकीय पक्ष ने इस विधेयक को तैयार नहीं किया बल्कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने प्रथमतः इस विधेयक का मसौदा तैयार किया। हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिये सामान खरीदता है, वह उपभोक्ता है। उपभोक्ता क्योंकि संगठित नहीं हैं इसलिए हर जगह ठगा जाता है। इसलिए उपभोक्ता को जागना होगा और खुद को इन संकटों से बचाना होगा। बहुत कम उपभोक्ता जानते होंगे कि उनके क्या अधिकार हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है और इसके साथ ही अगर वह धोकाधड़ी, कालाबाजारी, घटतौली, ठगी आदि का शिकार होते हैं तो वह इसकी शिकायत कर सकें। इस कानून में जीवन एवं संपत्ति के लिए हानिकारक सामान और सेवाओं की बिक्री के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, खरीदी गई वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, स्तर और मूल्य, जैसा भी मामला हो, उसके बारे में जानकारी का अधिकार एवं इसके लिए आवाज उठाने का अधिकार है। बढ़ते बाजारवाद एवं उदारीकरण के इस दौर में जैसे ही हम अपनी जरूरत की कोई चीज या सेवा लेते हैं, तभी उपभोक्ता का ठप्पा हमारे ऊपर लग जाता है। कायदे से किसी चीज या सेवा के एवज में चुकाई जाने वाली कीमत में किसी भी तरह की धोखाधड़ी एवं ठगी नहीं होना चाहिए, लेकिन अक्सर उपभोक्ता ठगे जाते हैं। खराब गुणवत्ता की चीजें और सेवा प्रदाता से अपने अधिकारों के हक की लड़ाई ही जागरूक उपभोक्ता की पहचान है। उपभोक्ता दिवस मनाते हुए हम केवल उपभोक्ता अधिकारों की ही बात नहीं करते बल्कि उपभोक्ता की उन्नत एवं सम्यक् सोच को भी विकसित करते हैं। आर्थिक विसंगतियों एवं विषमताओं को दूर करने के लिये उपभोक्ता जागृति जरूरी है। आज का उपभोक्तावादी दृष्टिकोण एक प्रकार का सम्मोहन बन गया है, हिस्टीरिया की बीमारी बन गया है। सम्मोहन करने वाला जैसा नचायेगा, उपभोक्ता वैसा ही नाचेगा, फिर उपभोक्ता संरक्षण कैसे संभव होगी? यह तभी संभव है जब हमारा उपभोग के प्रति सम्यक् दृष्टिकोण होगा। नया उपभोक्तावाद एक प्रकार से नई हिंसा का उपक्रम है। हिंसा, प्रतिस्पर्धा, सत्ता की दौड़ एवं आर्थिक साम्राज्य को इससे नया क्रूर आकार मिला है। क्योंकि उपभोक्तावाद की अंधी दौड़ ने व्यक्ति को संग्रह, सुविधा, सुख, भोग-विलास एवं स्वार्थ से जोड़ दिया है। स्वार्थों के संघर्ष में अन्याय, शोषण एवं अनैतिकता होने लगी। आज की उपभोक्तावादी एवं सुविधावादी जीवन-धारा में जैसे-जैसे भोगवाद बढ़ता जारहा है, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, प्रकृति दोहन, आतंकवाद, युद्ध, संघर्ष की स्थितियाँ बढ़ती जा रही है। समाज, राष्ट्र एवं विश्व में व्याप्त प्रदर्शन, दिखावा एवं फिजूलखर्ची पर नियंत्रण जरूरी है। सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है, उनके हितों का संरक्षण भी किया जा रहा है, इसी की निष्पत्ति है 'जागो ग्राहक जागो' जैसे अभियान। उपभोक्ता अधिकारों पर काम करने वाली एनजीओ कट्स (सीयूटीएस) इंटरनेशनल ने समय-समय पर सर्वे के माध्यम से पता लगाया है कि कितने उपभोक्ता ठगे जाते है और कितने उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। उपभोक्ता मंत्रालय के व्यापक जागरूकता अभियान के बावजूद गलत उत्पाद बेचकर मुनाफा कमाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी ठगी के शिकार 90 प्रतिशत लोगों ने तो कभी शिकायत ही नहीं की है। चार से पांच प्रतिशत उपभोक्ता ही कंपनी या उत्पाद निर्माता के पास अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में आनलाइन खरीद और साइबर क्राइम में वृद्धि के चलते लोगों में अपने आप जागरूकता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्र के लोग कुछ ज्यादा जागरूक हुए हैं, जबकि गांवों के लोग अभी भी अनजान हैं। गांवों के लोग यह भी नहीं जानते कि खरीदारी से पहले आईएसआई, आईएसओ एवं एगमार्क जैसे गुणवत्ता प्रमाणन की छानबीन करनी चाहिए। इंटरनेशनल कंस्यूमर पालिसी एक्सपर्ट प्रो. बीजान मिश्रा का कहना है कि अगर किसी से प्रेरित होकर कोई व्यक्ति उचित फोरम में चला भी गया तो गारंटी नहीं कि उसे समाधान मिल ही जाए। शिकायत दर्ज कराने वाले केवल 18 से 20 प्रतिशत उपभोक्ताओं को ही संतोषजनक समाधान मिलता है। बाकी को या तो समाधान नहीं मिला या कार्रवाई से संतुष्टि नहीं मिली।

हालांकि सुखद संकेत है कि कई मामलों में त्वरित समाधान मिलने से उपभोक्ता निवारण तंत्र पर भरोसा धीरे-धीरे बढ़ रहा है। ई-प्लेटफार्म पर भरोसा नहीं होने पर भी खरीदारी बढ़ रही है। एक सर्वे में बात आई है कि शहरों में 56 प्रतिशत उपभोक्ता आनलाइन खरीद करने लगे हैं। हालांकि अलग बात है कि उन्हें आनलाइन खरीदे गए उत्पादों की गुणवत्ता पर भरोसा फिर भी नहीं होता। आज की बाजार शक्तियां उपभोक्ताओं का शोषण करती है। इन्हीं उपभोक्तावादी एवं बाजार शक्तियों के कारण जीवन में सुख का अभिप्राय केवल भोग और उपभोग को माना जाने लगा है। ऐसे में झूठी शानो-शौकत के दिखावे के चक्कर में उपभोक्ता अविवेकशील होकर अनावश्यक चीजों को भी थैले में भरकर घर ला रहा है। बाजार एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के इस काले जादू के आगे उपभोक्ता बेबस एवं लाचार खड़ा है। जिसके कारण वस्तुओं की गुणवत्ता के स्तर में गिरावट आ रही हैं। कोई भी चीज मिलावटरहित मिलना अब संभव नहीं है। न चाहते हुए भी उपभोक्ता लूट का शिकार बन रहा है। इतना ही नहीं, उपभोक्तावादी संस्कृति ने भोगवादी जीवन जीने के लिए मनुष्य के समक्ष नए आयाम प्रस्तुत किए हैं तथा उसे सुविधाभोगी बना दिया है। भोग्य वस्तुओं का उपयोग ही जीवन का प्रमुख लक्ष्य बन गया है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विधियां लगाते जो पूरा करोगे। तब आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे परिवर्तन क्या है, जब आपके सितारे बुलंद होंगे और दुनिया तथा, आपकी किस बातों से लगातार तरक्की होगी। हम न सिर्फ हमारे तरफ से और अंतिम शुद्धों को लुप्तप्रायः ऐसा लाकरकाल उन्नत को सरकृत करेंगे, बल्कि पराकाष्ठित तरीकों से भी, जहां तक लाकरकाल तरीकों तक और कानूनी से लाभ प्रदान करेंगे

मेष
प्रतिद्वंद्विता कम होगी। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। बात बिगड़ सकती है। शत्रुभय रहेगा। कोर्ट व कचहरी के काम मनोनुकूल रहेंगे। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा।

वृष
सही काम का भी विरोध हो सकता है। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। निवेश शुभ रहेगा। सट्टे व लॉटरी के चक्कर में न पड़ें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर करें। किसी अनहोनी की आशंका रहेगी।

मिथुन
आय में निश्चितता रहेगी। दुःखद समाचार मिल सकता है। व्यर्थ भागदौड़ रहेगी। काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बेवजह किसी व्यक्ति से कहासुनी हो सकती है। प्रयास अधिक करना पड़ेंगे। दूसरों के बहकावे में न आएं।

कर्क
व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। शेयर मार्केट आदि से बड़ा फायदा हो सकता है। परिवार की चिंता बनी रहेगी। शारीरिक कष्ट संभव है। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। किसी आमंत्रण में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। फालतू बातों पर ध्यान न दें।

सिंह
विवाद से क्लेश होगा। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। ऐश्वर्य के साधनों पर सोच-समझकर खर्च करें। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि बाद में पछताना पड़े। दूसरे अधिक अपेक्षा करेंगे।

कन्या
निवेश शुभ रहेगा। व्यापार में वृद्धि तथा सम्मान में वृद्धि होगी। किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बचें। जल्दबाजी से हानि होगी। राजभय रहेगा। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। घर में मेहमानों का आगमन होगा। व्यय होगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी।

तुला
सही काम का भी विरोध होगा। कोई पुरानी व्याधि परेशानी का कारण बनेगी। कोई बड़ी समस्या बनी रहेगी। चिंता तथा तनाव रहेंगे। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सामाजिक कार्य करने के प्रति रुझान रहेगा।

वृश्चिक
मान-सम्मान मिलेगा। रुके कार्यों में गति आएगी। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में चैन बना रहेगा। धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। कोर्ट व कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। चोट व रोग से बचें। सेहत का ध्यान रखें।

धनु
दुष्टजन हानि पहुंचा सकते हैं। झंझटों में न पड़ें। व्यापार-व्यवसाय में वृद्धि होगी। नौकरी में मातहतों का सहयोग मिलेगा। निवेश शुभ रहेगा। परिवार में प्रसन्नता रहेगी। शत्रुभय रहेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी।

मकर
स्त्री वर्ग से सहायता प्राप्त होगी। नौकरी व निवेश में इच्छा पूरी होने की संभावना है। भूमि व भवन संबंधी खरीद-फरोख्त की योजना बनेगी। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। आर्थिक उन्नति होगी। संचित कोष में वृद्धि होगी। देनदारी कम होगी।

कुंभ
पुराना रोग परेशानी का कारण बन सकता है। जल्दबाजी न करें। आवश्यक वस्तुएं गुम हो सकती हैं। चिंता तथा तनाव रहेंगे। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। भेंट व उपहार देना पड़ सकता है। प्रयास सफल रहेंगे। कार्य की बाधा दूर होगी।

मीन
खाद्य मनोरंजक रहेगी। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति मार्गदर्शन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। झंझटों में न पड़ें। शत्रुओं का पराभव होगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। शारीरिक कष्ट संभव है।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार है डॉक्टर सुखबीर तंवर। 17 जुलाई सन 1986 को ग्राम भिवाड़ी तहसील तिजारा जिला अलवर में जन्मे डॉक्टर सुखबीर तंवर बचपन से ही होनाहार विद्यार्थी रहे। कक्षा 2 तक ग्राम में सरकारी स्कूल में अध्ययन किया तीसरी से और आठवीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल एक गांव के पास ही था वहां अध्ययन किया। कक्षा 8 से 12वीं तक शिवलाल सिंह पब्लिक स्कूल सिद्दावली ग्राम हरियाणा में किया। एमबीबीएस गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर में सन 2008 में किया। प्रथम पोस्टिंग सन 2015 में पस रामगढ़ ब्लॉक कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा में मिली इसके बाद इन्होंने एमडी सन 2018 में महात्मा गांधी हॉस्पिटल जयपुर से किया। एमडी के बाद 2021 में पोस्टिंग एमडी अलवर 2022 में सीनियर रेजिडेंट करने एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर गए 2023 को वापस अलवर पोस्टिंग ली। कैंसर के मरीजों का रिकॉर्ड रखा 2021 में 1168 मरीज थे 2022 में 2883 मरीज हुए 2023 में 9139 मरीज हुए 2024 में 16000 मरीज होने पर चिंता जताई और लोगों को अवेयर करने का जिम्मा उठाया। कड़ी मेहनत कर इतने मरीजों का उपचार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और कैंसर जैसी घातक बीमारी में लोग अवेयर रहे इसका प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए जगह-जगह अवेयरनेस कैंपेन लगाकर शिविर लगाकर लोगों को समझाइश कर रहे हैं सामान्य चिकित्सालय में इस समय कैंसर स्पेशलिस्ट के तौर पर लोगों को उपचार दे रहे हैं। हर आने जाने वाले मरीज और उनके परिजनों से बहुत बेहतरीन से बात करके उन्हें उचित सलाह में मार्गदर्शन देते हैं अलवर में सामान्य चिकित्सालय में बैठने वाले पहले कैंसर रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

रूपक शर्मा

सुखबीर तंवर
(कैंसर रोग विशेषज्ञ)

आज का इतिहास

24 दिसंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- स्वीडन की सेना ने 1715 में नार्वे पर कब्जा किया।
- रूस और ब्रिटेन के बीच 1798 में दूसरे फ्रांस विरोधी गठबंधन पर हस्ताक्षर।
- कलकत्ता में 1894 में पहले मेडिकल कांफ्रेंस का आयोजन।
- क्रोयडोन लंदन की एयर फील्ड में 1924 में हुई विमान दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु हो गई।
- अल्बानिया सन 1924 में गणतंत्र बना।
- सोवियत संघ ने 1962 में नोवाया जेमल्या में परमाणु परीक्षण किया।
- चीन ने 1967 में लोप नोर क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया।
- वियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया।
- लोटस टेंपल 1986 में श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था।
- भारत में 1986 में संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसलिए भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- देश का पहला अम्यूजमेंट पार्क 'एसेल वर्ल्ड' 1989 में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में खोला गया।
- ताजिकिस्तान में गृहयुद्ध को समाप्त करने के लिए 1996 में समझौता सम्पन्न।
- विश्वनाथन आनंद 2000 में विश्व शतरंज चैंपियन बने।
- दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ 2002 में शहादरा तीस हज़ारी लाईन से हुआ था।
- अमेरिकी विदेश विभाग ने 2003 में 30 जून, 2004 को इराक में सत्ता सौंपने की तैयारी शुरू की।
- यूरोपीय संघ ने 2005 में 'खालिस्तान जिन्दाबाद फ़ोर्स' नामक संगठन को आतंकी सूची में शामिल किया।
- सन 2006 में हुयी शिखर बैठक में फ़िलिस्तीन को इस्रायल कई सुविधाएँ देने के लिए तैयार।
- मंगल ग्रह के रहस्यों की खोज करने के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यान मार्स ने 2007 में मंगल ग्रह की कक्षा में अपने चार हज़ार चक्कर पूरे किये।
- क्यूबा की सरकार ने 2011 में 2900 कैदियों को रिहा करने की घोषणा की।
- चीन के जियांगसी में 2012 में एक वैन पलटने से 11 केजी स्कूल के 11 बच्चों की मौत।
- अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 2014 में भारत रत्न देने की घोषणा हुई।

24 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति

- प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, गाँधीवादी और पत्रकार भोगराजु पट्टाभि सीतारामैया का जन्म 1880 में हुआ।
- प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्यकार बनारसीदास चतुर्वेदी का जन्म 1892 में हुआ।
- अमेरिकी अभिनेत्री आवा गार्डनर का जन्म 1922 में हुआ।
- स्वतंत्रता सेनानी एवं महादेव देसाई के पुत्र नारायण भाई देसाई का जन्म 1924 में हुआ।
- भारतीय गायक मुहम्मद रफ़ी का जन्म 1924 में हुआ।
- पत्रकार एवं साहित्यकार उषा प्रियंवदा का जन्म 1930 में हुआ।
- अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करज़ई का जन्म 1957 में हुआ।
- भारतीय अभिनेता अनिल कपूर का जन्म 1959 में हुआ।
- भारतीय हिन्दी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रीति सप्रू का जन्म 1961 में हुआ।

विशेष आलेख

संसद के कलुषित परिवेश का जिम्मेवार कौन?

प्रियंका सौरभ

पिछले कुछ दिनों से संसद में जो कुछ हो रहा है, उससे देश निराश है। संसद चलाकर ही सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब सही ढंग से दे सकती है। हंगामे के माहौल में सांसदों को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिलता। कोई बच्चा भी समझ सकता है वेल में जाकर नारेबाज़ी और हंगामा कर सदन की कार्यवाही रोकने से कैसे विरोध जताया जा सकता है। अच्छी बात तो तब कही जाएगी, जब आप अपने सवाल साफ़-साफ़ रखें और सरकार साफ़-साफ़ जवाब दे पाए। लेकिन इससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि संसद की कार्रवाई में बाधा अपवाद की बजाय नियम बन गया है और हमारे राजनेताओं को इस पर कोई पछतावा नहीं होता है। पिछले वर्षों में यह गिरावट बड़ी तेजी से आई है। सांसद एक-दूसरे पर चिल्लाते हैं, विधायी कागजों को छीनकर फाड़ देते हैं, छोटे से मुद्दे पर सदन के बीचों-बीच आ जाते हैं। पिछले वर्षों में ज्यादातर विधेयकों को बिना चर्चा के ही पारित किया गया है। यह संसदीय प्रणाली का दुरुपयोग है। अब विपक्षी पार्टियों और कुछ सांसदों ने संसद की दुर्गति कर रखी है। दोनों सदनों में निजी एजेंडों को लेकर अनुत्पादक हंगामा कर कार्यवाही ठप करा देना आम बात है। संसद में शोर-शराबा, वेल में जाकर नारेबाज़ी करना, एक-दूसरे पर निजी कटाक्ष करना यहां तक कि कई बार हाथापाई पर उतारू हो जाना आज संसद की आम तस्वीर है। आखिर सियासी पार्टियों और सांसदों का बर्ताव इतना अराजक क्यों हो गया है? क्या आज पार्टियों के निहित स्वार्थों ने संसद को मज़ाक बनाकर रख दिया है। सांसदों के रवैये को देखते हुए लगता नहीं है कि उसकी मंशा देश के विकास की योजनाएं बनने देने की है। ऐसा लग रहा है कि सांसदों ने पूरे संसदीय लोकतंत्र को बंधक बना लिया है। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आजकल टीवी पर लाइव दिखाई जाती है, लिहाज़ा देश का आम आदमी भी वह सब कुछ देखता है, जो संसद में रोज़ हो रहा है। आख़िर सांसद लोगों के सामने अपनी क्या छवि पेश कर रहे हैं? ज़रा सोचिए कि देश के लोगों के मन में आपकी क्या छवि बनती जा रही है? यह सच है कि इस गिरावट का कारण यह है कि राजनीति आज संख्या का खेल बन गई है जिसके चलते क्षेत्रीय क्षत्रप अपनी मनमर्जी कराने के लिए दबाव डालते हैं। वे न केवल दादागिरी की राजनीति में विश्वास करते हैं अपितु सफल संसद सत्र के पैमाने को 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' भी बनाते हैं। आज विषय-वस्तु की बजाय आकार महत्वपूर्ण बन गया है जिसके चलते संसद में गली-मोहल्लों के झगड़ों जैसे दृश्य देखने को मिलते हैं। इसलिए इस गिरती राजनीतिक संस्कृति और नैतिक मूल्यों में संसदीय कार्रवाई में राजनीति को प्रभावित करने वाली विषय सामग्री नहीं मिलती है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि संसद अब महज़ एक स्कोरिंग क्लब बन कर रह गई है। बहुतों को पता होगा कि संसद की एक मिनट की कार्यवाही पर ढाई लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। इस तरह एक दिन की सामान्य कार्यवाही पर औसतन छह करोड़ रुपए का खर्च आता है। जिस दिन कार्यवाही लंबी चलती है, उस दिन खर्च और बढ़ जाता है। ज़रा सोचिए कि यह पैसा आता कहां से है। ज़ाहिर है कि देश के आम लोगों की जेब से ही आता है। लोकतंत्र में इससे बड़ा और क्या मज़ाक होगा कि संसद की कार्यवाही लगातार उप रहे या फिर दिन भर रह-रह कर हंगामा होता रहे, फिर भी एक दिन में छह करोड़ रुपए खर्च हो जाएं। ज़रा सोचिए कि छह करोड़ रुपए से क्या-क्या हो सकता है? हज़ारों गांवों की क़िस्मत संसद की एक दिन की कार्यवाही पर होने वाले खर्च से बदल सकती है। लाखों ग़रीब लड़कियों की शादी हो सकती है। लघु और कुटीर उद्योगों से हज़ारों नौजवानों की क़िस्मत संवर सकती है। लेकिन सांसद यह सब नहीं सोचते। विकास की योजनाएं भले न बनें, व्यक्तिगत हित ज़रूर सुधरने चाहिए। क्या सांसद देश से ऊपर हो गए हैं? एक बात और सारे सांसद हंगामेबाज़ हों, ऐसी बात नहीं हैं। जो कामकाज को लेकर गंभीर हैं, वे कुछ नहीं कर पाते। सवाल है कि सांसद हर बार माहौल क्यों नहीं बनाते? क्या सांसद केवल हंगामा करने के लिए ही पहुंचते हैं? सांसदों ने लोकसभा को पंगु बना कर रख दिया है। हक़ीक़त यह है कि लोकतंत्र का लोक यानी देश की जनता लोकसभा का चुनाव सीधे तौर पर करती है। ऐसे में अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदन को लोक के सदन यानी लोकसभा की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोकसभा में हुए हर काम में अड़ंगा डाल दिया जाए। लोकसभा में तय दिनों में सभी सांसदों को तीन-तीन मिनट ही सही, अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में बोलने दिया जाए। बार-बार हंगामा करने वाले सांसदों को चिन्हित किया जाए और उनकी सूची प्रचारित कराई जाए। ऐसे नियम बनाए जाएं कि वेल में आने या पर्चा लहराने या दूसरा किसी भी क़िस्म का हंगामा करने वाले सांसद के ख़िलाफ़ खुद-ब-खुद कोई तय कार्यवाही हो जाए। कुछ सांसद वॉकआउट करने के बाद दोबारा सदन में क्यों आ जाते हैं? केवल दिखावा करने के लिए ऐसा करते हैं, उन्हें देश के विकास से कोई लेना-देना नहीं है।वे संसद में कुछ कर नहीं पा रहे हैं और उधर उनके लोकसभा क्षेत्र की जनता त्रस्त, क्योंकि वे उनकी समस्याएं सुलझा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सांसद में केवल हंगामा हो रहा है। इसलिए संसद को अखाड़ा बनने से रोकें। नेतृत्व को भी अपनी बात समझाएं, उनके हर ग़लत-सही आदेश का आंख मूंदकर पालन न करें। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की गरिमा बचाए रखना सांसदों का प्रथम काम है। संसद को महत्वहीन बनाने के खतरनाक आयामों को शायद ये लोग नहीं समझते हैं। हमारी संसद हमारे राष्ट्र की आधारशिला है जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है और जिससे अपेक्षा की जाती है कि वह हमारे राष्ट्रीय हितों पर संप्रभु निगरानी रखे। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और सरकार का अस्तित्व उस पर लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीरपुरा रोड खरडवा,जिला टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान* । प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-योहाल सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 265

मुश्किल विकल्प

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकार की आय और व्यय के रुझानों की अर्द्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत की है। अगर सरसरी तौर पर देखा जाए तो इस दस्तावेज के पाठ में कुछ खास नहीं नजर आता है। वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया है कि चालू वर्ष की पहली छमाही में हुई राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान की करीब 52 फीसदी रहीं। यह पांच वर्ष के औसत से बेहतर प्रदर्शन है। इस दौरान राजकोषीय घाटा भी सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी के प्रतिशत के रूप में साल की पहली छमाही के लिए तय मानक से कम रहा। इससे ऐसा प्रतीत हो सकता है कि अब जबकि केंद्रीय बजट जल्दी ही पेश किया जाना है, तो उसकी तैयारी के दौरान देश की वृहद आर्थिक स्थिति खासी सहज है। यकीनन दस्तावेज तो यही बताता है कि सरकार राजकोषीय मजबूती की राह पर बढ़ रही है। इसमें कोई खास चिंता नहीं दर्शाई गई है। बहरहाल, अर्द्धवार्षिक समीक्षा से राहत की बात शायद पूरी तरह सच नहीं हो।

यदि इस दस्तावेज को अलग ढंग से देखा जाए तो यह ऐसी उल्लेखनीय कमियां भी सामने लाता है जो वित्त मंत्रालय को चिंतित कर सकती हैं। ऐसी कमियों वाले अधिकांश क्षेत्र वृद्धि के क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शन से संबंधित हैं। अर्थव्यवस्था में यह कमजोरी पिछली तिमाही में नजर आई। चुनावों के चलते कम व्यय के साथ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक वृद्धि केवल छह फीसदी रही। चूंकि नॉमिनल वृद्धि, जैसा कि केंद्रीय बजट में प्रावधान किया गया, 10.5 फीसदी होनी थी लेकिन यह एक फीसदी से अधिक कम हो गई। ऐसे में बजट का गणित जटिल हो गया है। ये बातें अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट के डेटा में सामने आई हैं।

राजस्व प्राप्तियां पांच साल के औसत से अधिक होने के बावजूद कोई फर्क पड़ता नहीं नजर आता है। ऐसा इसलिए कि बीते पांच साल की इस गणना में वे असाधारण वर्ष भी शामिल हैं जब देश और दुनिया महामारी की चपेट में थी। पूंजीगत व्यय की बात करें तो वृद्धि में मदद करने वाला यह व्यय भी पहली छमाही में तुलनात्मक वर्षों की अपेक्षा कम रहा है। यह भी सरकार की दुविधा को उजागर करता है। अगर उसे वृद्धि को गति देनी है तो वह व्यय बढ़ाने का जोखिम ले सकती है। परंतु मौजूदा वर्ष के बजट अनुमानों के आधार पर पहली छमाही में राजकोषीय घाटे के कमजोर आंकड़े, वास्तविक नॉमिनल जीडीपी को सही ढंग से परिलक्षित नहीं करते। वर्ष के अंतिम राजकोषीय घाटे की गणना इसी आधार पर की जाती है। एक वास्तविक जोखिम यह है कि व्यय के लिए पहले अनुमानित मार्ग पर वापसी भी सरकार को घाटे के लक्ष्य से गुजरने पर विवश करेगी।

जाहिर है सरकार के सामने आसान विकल्प नहीं हैं। वर्ष की अंतिम तिमाही में वृद्धि को लेकर आशावादी दृष्टिकोण अपनाने का लालच रहेगा ताकि बजट के गणित को आसान बनाया जा सके। परंतु ऐसा करना गलत होगा। मौजूदा प्रशासन ने वृद्धि और राजस्व को लेकर तार्किक और बचाव योग्य बाह्य निष्कर्षों के इस्तेमाल पर जोर दिया है। बाजारों ने इस संयम के लिए पुरस्कृत भी किया है। कड़े परिश्रम से हासिल इस प्रतिष्ठा से मिली वृहद आर्थिक स्थिरता को अत्यधिक आशावादी अनुमानों के कारण जोखिम में नहीं डालना चाहिए। आखिर में सरकार को अपेक्षाकृत कम वृद्धि (तथा राजस्व एवं व्यय) अथवा राजकोषीय लक्ष्यों को टालने के बीच चयन करना होगा। आखिर में अगर यह वर्ष वृद्धि के क्षेत्र में सकारात्मक ढंग से चौंकाने वाला साबित होता है तो अच्छा ही होगा। परंतु अब तक के आंकड़ों के आधार पर सरकार को बजट में कुछ मुश्किल चयन करने होंगे।

अमेरिका-चीन व्यापार में किसकी जीत और हार

व्यापार में चीन का दबदबा कम करने और अमेरिका में विनिर्माण तथा रोजगार बढ़ाने के लिए ऊंचे शुल्क ही काफी नहीं होंगे, उनसे परे रणनीति बनानी होगी। समझा रहे हैं अजय श्रीवास्तव

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध मार्च 2018 में शुरू हुआ था, जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने स्टील के आयात पर 25 फीसदी और एल्यूमीनियम आयात पर 10 फीसदी शुल्क लगा दिया। बाद में यह शुल्क चीन से आने वाली सैकड़ों वस्तुओं पर लगा दिया गया ताकि व्यापार असंतुलन ठीक हो सके और अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण भी मिल सके।

ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद मेक्सिको, कनाडा, चीन और अन्य देशों पर नए शुल्क लगाने की योजना बनाई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि पिछले छह साल में अमेरिका के शुल्कों और अन्य व्यापार प्रतिबंधों का विश्व व्यापार पर कैसा प्रभाव पड़ा। व्यापार युद्ध में जीत किसकी हुई और सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? यह जानने के लिए हमने 2017 (व्यापार युद्ध शुरू होने से एक साल पहले) और 2023 (जिसके आंकड़े आ चुके हैं) के बीच विश्व व्यापार में हुए बदलावों पर गौर किया। नतीजों ने हमें हैरान कर दिया।

अमेरिका का बढ़ता आयात: जब अमेरिका ने शुल्क लगाया तब उसे उम्मीद थी कि चीन और बाकी दुनिया से आयात घटेगा तथा अमेरिका के भीतर उत्पादन बढ़ेगा। चीन से अमेरिका में होने वाले आयात में 2017 और 2023 के बीच 81.56 अरब डॉलर की कमी आई और यह 519.52 अरब डॉलर से घटकर 437.96 अरब डॉलर रह गया। मगर अमेरिका का कुल आयात 31.51 फीसदी बढ़कर 2,310 अरब डॉलर से 3,040 अरब डॉलर तक पहुंच गया यानी 763.1 अरब डॉलर का इजाफा, जो चीन से आयात में हुई कमी का लगभग 10 गुना है। इसे पता चलता है कि विनिर्माण के मामले में प्रतिस्पर्द्धा करने की अमेरिकी क्षमता घट गई है। इस बीच चीन ने दुनिया भर को अपने निर्यात में 1,100 अरब डॉलर का शानदार इजाफा किया है और 2,300 अरब डॉलर से बढ़कर अब यह 3,400 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। उधर अमेरिका का निर्यात 383 अरब डॉलर बढ़ा और 1,310 अरब डॉलर से 1,690 अरब डॉलर पर ही पहुंच पाया है।

सबसे ज्यादा फायदा: अमेरिका में चीन से होने वाला आयात कम हुआ, लेकिन उसकी जगह लेने दूसरे देश आ गए और सबसे ज्यादा लाभ मेक्सिको को हुआ। मेक्सिको से अमेरिका को होने वाले निर्यात में 2017 और 2023 के बीच 164.3 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। उसके बाद कनाडा से निर्यात में 124 अरब डॉलर, वियतनाम से 70.5 अरब डॉलर, दक्षिण कोरिया से 46.3 अरब डॉलर और जर्मनी से होने वाले निर्यात में 43 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। ये पांचों ही अमेरिका को सबसे अधिक निर्यात करने वाले देश रहे। भारत छठे स्थान पर रहा और यहां से अमेरिका को होने वाला निर्यात इस दौरान 36.8 अरब डॉलर ही बढ़ा। अमेरिकी कदम का फायदा उठाने वाले अन्य देशों में आयरलैंड से निर्यात 33.6 अरब डॉलर, थाईलैंड से 26.5 अरब डॉलर, इटली से 23.8 अरब डॉलर और सिंगापुर से 21.1 अरब डॉलर बढ़ा। अमेरिका को होने वाले आयात में इस दौरान हुए कुल इजाफे में मेक्सिको, कनाडा और आसियान देशों की 57 फीसदी या 427.5 अरब डॉलर की भागीदारी रही। इसमें से ज्यादातर वृद्धि अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौते से होने वाले मुक्त व्यापार तथा अमेरिका-वियतनाम मुक्त व्यापार समझौते के जरिये हुई।

चीन की बढ़ती भूमिका: अमेरिका के लिए चीन का निर्यात 2017 से 2023 के बीच कम हुआ मगर कई अन्य देशों को इसका निर्यात काफी बढ़ गया। वियतनाम को चीनी निर्यात 92.14 फीसदी बढ़कर 137.61 अरब डॉलर पर पहुंच गया। दक्षिण कोरिया को निर्यात में 45.06 फीसदी की वृद्धि देखी गई, मलेशिया को निर्यात 109.46 फीसदी बढ़ा और चीन से मेक्सिको को होने वाला निर्यात सबसे अधिक 126.88 फीसदी इजाफे के साथ 81.46 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

चीन ने अमेरिकी शुल्कों से बच निकलने के लिए दो तरीके अपनाए। पहला, उसने कच्चा माल और विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाली दूसरी सामग्री मेक्सिको, वियतनाम तथा दूसरे आसियान देशों को निर्यात कर दी। वहां उस सामग्री की प्रसंस्करण हुआ और उसे अमेरिका को निर्यात कर दिया गया। दूसरा, चीन की कंपनियों ने इन देशों खास तौर पर मेक्सिको में वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा भारी मशीनरी के विनिर्माण और वियतनाम, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और वाहन के विनिर्माण में भारी निवेश किया। वहां से अमेरिका को होने वाला ज्यादातर निर्यात मुक्त व्यापार समझौतों के तहत शुल्क रहित होता था।

भारत के लिए लाभ: भारत से अमेरिका को निर्यात 2017 से 2023 के बीच 50.5 अरब डॉलर से बढ़कर 87.3 अरब डॉलर हो गया यानी इसमें 36.8 अरब डॉलर की वृद्धि हुई। भारत इसके साथ ही अमेरिकी आयात में हुई कुल वृद्धि का छठा सबसे बड़ा भागीदार बन गया। भारत से होने वाले निर्यात मे सबसे ज्यादा 6.2 अरब डॉलर की वृद्धि स्मार्टफोन और दूरसंचार उपकरणों के कारण हुई, जो कुल वृद्धि की 17.2 फीसदी रही। दवा क्षेत्र की भागीदारी 4.5 अरब डॉलर (12.4 फीसदी), पेट्रोलियम उत्पादों की 2.5 अरब डॉलर (6.8 फीसदी) और सोलर सेल की भागीदारी 1.9 अरब डॉलर (5.3 फीसदी) रही। सोने के गहनों और प्रयोगशाला में बने हीरों ने निर्यात 2.3 अरब डॉलर बढ़ा दिया। कपड़ों, मोटर वाहन के कलपुर्जों, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसमिशन शाफ्ट जैसे सामान का निर्यात भी अच्छा-खासा बढ़ा।

जैसी चीजों के निर्यात ने भी अच्छी-खासी वृद्धि दर्ज की है।

निर्यात लगातार जारी रखना है तो भारत को स्थानीय स्तर पर मूल्यवर्द्धन बढ़ाना होगा क्योंकि अमेरिका को निर्यात होने वाला काफी सामान दूसरे देशों से सामग्री मंगाकर तैयार किया जाता है। उदाहरण के तौर पर स्मार्टफोन असेंबल करने के लिए ज्यादातर पुर्जे आयात किए जाते हैं, सोलर पैनल असेंबल करने के लिए सोलर सेल मुख्य रूप से चीन से आती हैं। इसी तरह दवा बनाने के लिए 70 फीसदी तक सक्रिय दवा सामग्री (एपीआई) चीन से मंगाई जाती है।

शुल्क पर पुनर्विचार करे अमेरिका: व्यापार में चीन के दबदबे का मुकाबला करने और अमेरिका में विनिर्माण तथा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऊंचे शुल्क से परे कोई रणनीति जरूरी है। स्रोत पर जोर नहीं देने का नियम बदलकर अमेरिकी आयात में चीनी सामग्री का इस्तेमाल कम से कम कराना इसका कारगर तरीका हो सकता है। यह तरीका मुक्त व्यापार समझौतों में शामिल कर सभी प्रकार के आयात पर लागू किया जा सकता है और यह शुल्क से ज्यादा कारगर साबित होगा क्योंकि शुल्क बढ़ाने पर वही सामान दूसरे देशों के रास्ते आ जाने का खतरा रहता है। व्यापार समझौतों में स्रोत का नियम शामिल किया जाएगा तो मामूली प्रसंस्करण के बाद शुल्क से बचते हुए दूसरे स्थानों से वही सामान आ जाने का खतरा भी खत्म हो जाएगा।

बड़े दायरे वाले उपायों से आसानी से बचकर निकला जा सकता है। इसलिए उनके बजाय उन अहम क्षेत्रों पर शुल्क लगने चाहिए, जो तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं जैसे सेमीकंडक्टर, अक्षय ऊर्जा और दवा। इस तरह के शुल्कों के साथ अमेरिकी फर्मों को देश के भीतर से या सहयोगी देशों से सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते कर लाभ या सब्सिडी भी दी जा सकती हैं। चिप्स एक्ट का दायरा बढ़ाते हुए उच्च प्रौद्योगिकी वाले और भी क्षेत्रों को उसमें शामिल करना, आपूर्ति श्रृंखला सहयोगी देशों में पहुंचाए जाने को बढ़ावा देना और दुर्लभ खनिजों, एपीआई तथा लीथियम आयन बैटरी जैसी जरूरी सामग्री में निवेश करना भी जरूरी है। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, रोबॉटिक्स और हरित प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास के लिए और अधिक पूंजी देने से अमेरिका भविष्य में भी प्रतिस्पर्द्धी देश बना रहेगा।

निष्कर्ष: ट्रंप नए शुल्क लगाने की योजना बना रहे हैं लेकिन अमेरिका को कड़वी सच्चाई का सामना करना चाहिए: उसने चीन को दुनिया का कारखाना बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। यह निर्भरता खत्म करना अगर मुमकिन हुआ तो भी इसके लिए उसे कई साल मेहनत करनी पड़ेगी और देसी उद्योगों को मजबूत करना होगा। इसके नतीजे रातोरात नहीं मिल सकते।

(लेखक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनीशिएटिव के संस्थापक हैं)

आत्मनिर्भर बनें शहरी स्थानीय निकाय

नगर निकायों के वित्त पर भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट बताती है कि 50 फीसदी से ज्यादा नगर निगम अपने बल पर आधे से भी कम राजस्व अर्जित कर पाते हैं और 2022-23 में सरकार से उन्हें मिलने वाली रकम 20 फीसदी से भी ज्यादा बढ़ गई।

नगर निकायों को अधिक प्रशासनिक स्वायत्ता तथा वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए स्थानीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। नगर निकायों का राजस्व बढ़ाना वित्तीय जरूरत नहीं है बल्कि यह प्रभावी शहरी प्रशासन के लिए बुनियादी जरूरत है। नगर पालिकाएं अपने आय के स्रोतों में विविधता लाकर तथा राजकोषीय क्षमताओं को बढ़ाकर अधिक सक्रिय तथा टिकाऊ शहरी प्रबंधन नीतियां तैयार कर सकती हैं।

नगरीय निकायों के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन में दोहरा दृष्टिकोण शामिल होता है, जिसके तहत सरकार के उच्चतर स्तरों से वित्तीय अंतरण और स्थानीय राजस्व का अच्छे ढंग से सृजन, उपयोग तथा आवंटन जरूरी होता है। भारत में शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय स्वायत्तता हासिल करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें सीमित मात्रा में अधिकार और संसाधन मिले हैं।

भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 0.45 फीसदी हिस्सा वित्तीय अंतरण के तौर पर नगर निकायों को दिया जाता है। इसके उलट ब्राजील, इंडोनेशिया, फिलिपींस और मेक्सिको जैसे देशों में जीडीपी का 1.6 फीसदी से 5.4 फीसदी तक नगर निकायों को मिल जाता है। यूरोपीय देशों में उन्हें जीडीपी का 6 से 10 फीसदी तक आवंटित किया जाता है। इससे पता चलता है कि स्थानीय प्रशासन को सहारा देने के लिए मजबूत अंतरसरकारी राजकोषीय व्यवस्थाएं कितनी जरूरी हैं। इन अंतरराष्ट्रीय मानकों से यह भी पता चलता है कि भारत में नगर निकायों को मिलने वाला धन या वित्तीय अंतरण बढ़ाए जाने की कितनी अधिक जरूरत है। साथ ही यह भी जरूरी है कि नगर निकाय स्वयं राजस्व तैयार करें, जिसमें अभी तक वे बुरी तरह पिछड़ रहे हैं।

इस दूसरे पहलू की बात करें तो देश में नगर निकायों की वित्तीय स्थिति कई चुनौतियों से जूझती है। इसमें राजस्व संग्रह कम रहना, राज्यों और केंद्र से वित्तीय अंतरण पर बहुत अधिक निर्भर होना और म्युनिसिपल उधारी में इजाफा होना शामिल हैं। रिजर्व बैंक की 'नगर निकायों में राजस्व सृजन के अपने स्रोत: अवसर और चुनौतियां' शीर्षक वाली इसी साल आई रिपोर्ट में इन चुनौतियों पर नजर डाली गई है।

अमित कपूर

नगर निकायों ने जीडीपी के 0.6 फीसदी के बराबर ही राजस्व तैयार किया, जबकि राज्य सरकारों ने 14.6 फीसदी और केंद्र सरकार ने 9.2 फीसदी राजस्व सृजित किया। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय अंतरण पर निर्भरता बहुत अधिक हो गई। 2022-23 में केंद्र से 24.9 फीसदी और राज्य सरकारों से अंतरण 20.4 फीसदी बढ़ गया। नगर निकायों की उधारी भी सबको चौंकाते हुए 363.06 फीसदी बढ़ गई है। 2019-20 में यह केवल 2,886 करोड़ रुपये थी, जो 2023-24 में बढ़कर 13,364 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

शहरी इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाली जन सेवाओं की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए रिपोर्ट में भौगलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) से मैपिंग, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संपत्ति के बढ़ते मूल्य को सही तरीके से दिखाने वाली बेहतर संपत्ति कर प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की गई। ध्यान रहे कि कर राजस्व का सबसे अहम स्रोत संपत्ति कर ही होता है।

स्थानीय निकाय कर से राजस्व नहीं कमा सकते, इसलिए कर के अलावा अन्य स्रोतों से राजस्व बढ़ाना बहुत जरूरी है और उसके लिए रिपोर्ट महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और त्रिपुरा का उदाहरण देकर 'उपयोगकर्ता शुल्क' शुरू करने का सुझाव देती है। यह शुल्क जलापूर्ति, सफाई और कचरा प्रबंधन जैसी जरूरी सेवाओं पर लगाया जा सकता है।

हालिया रिपोर्ट 'म्युनिसिपल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन सिटीज: एन इवैलुएशन बेस्ड ऑन यूओएफ डेटा' में भारत के शहरी निकायों की चुनौतियां दी गई हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जुटाए गए आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए इस अध्ययन में 134 नगर पालिकाओं के प्रदर्शन को कसौटी पर कसा गया है। इसमें पांच अहम अंगों - प्रशासन, सेवा, प्रौद्योगिकी, नियोजन तथा वित्त को 20 क्षेत्रों और 100 संकेतकों पर परखा गया है।

इस आकलन में वित्तीय स्थिति का अध्ययन अहम जानकारी देता है। इसमें नगर पालिकाओं को चार अहम पैमानों - राजस्व प्रबंधन, व्यय प्रबंधन, राजकोषीय उत्तरदायित्व और राजकोषीय विकेंद्रीकरण पर जांचा गया है। राजस्व प्रबंधन की बात करें तो लगभग 50 फीसदी नगर पालिकाएं अपने कुल राजस्व का केवल 23 प्रतिशत स्वयं सृजित करती हैं और कर राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर रहती हैं। 22 नगर पालिकाओं का 80 फीसदी राजस्व कर से ही आता है। शायद सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि आधी नगर पालिकाएं राज्य तथा केंद्र सरकार के अनुदान को छोड़कर वित्त के दूसरे वैकल्पिक स्रोत तैयार नहीं कर पा रही हैं।

व्यय प्रबंधन की पड़ताल करने पर नगरपालिकाओं की वित्तीय कुशलता पर और भी बारीक जानकारी मिलती है। केंद्र से मिले अनुदान का इस्तेमाल करने में नगर पालिकाओं की औसत दक्षता दर 59 फीसदी है और राज्य अनुदान के मामले में औसत दर 67 फीसदी है। अधिकतर नगर पालिकाएं कर राजस्व को सबसे पहले वेतन पर खर्च करती हैं, जिससे उनका प्रति व्यक्ति पूंजी व्यय कम रह जाता है।

राजकोषीय जवाबदेही में नगर पालिकाओं के अनुभव उम्मीद जगाते हैं। पिछले तीन साल से नगर पालिकाओं ने 10 फीसदी से अधिक बजट अधिशेष रखा है। इससे संकेत मिलता है कि उन्होंने काफी वित्तीय समझदारी और स्थिरता दर्शाई है। मगर राजकोषीय विकेंद्रीकरण पर मिले निष्कर्ष बड़ी व्यवस्थागत चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं। 109 नगर पालिकाओं यानी करीब 81 फीसदी नगर पालिकाओं के पास स्वयं उधारी लेने या निवेश करने के अधिकार नहीं हैं। वित्तीय निर्णयों के लिए उन्हें राज्यों से मंजूरी लेनी पड़ती है। इससे स्थानीय शासन की स्वायत्तता बहुत घट जाती है। ये आकलन नगर निकायों की वित्तीय स्थिति पर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से मेल खाते हैं। इन रिपोर्ट में दी गई जानकारी नए संस्थागत ढांचे की जरूरत बताती हैं, जहां नगर पालिकाएं विकास की रणनीतियों के केंद्र में होनी चाहिए और उनके पास अधिक प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता भी होनी चाहिए।

भविष्य में दो रणनीतियों की जरूरत है। पहली, केंद्र और राज्यों से वित्तीय आवंटन बढ़ना चाहिए। दूसरी, नगर पालिकाओं को अपने राजस्व स्रोतों में विविधता लानी चाहिए और वित्तीय निर्णय लेने की स्वायत्तता उन्हें मिलनी चाहिए। निजी-सरकारी साझेदारी, लागत के भरपूर इस्तेमाल के लिए डिजिटल समाधान और म्युनिसिपल तथा ग्रीन बॉन्ड जैसे वित्तीय साधनों के जरिये ऐसा किया जा सकता है। इन उपायों से छोटे नगर निकाय खास तौर पर अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकते हैं। जैसा रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है, इन तरीकों से जरूरी शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करने, टिकाऊ विकास करने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद मिलेगी। बेहतर जवाबदेही, वित्तीय लचीलेपन और रणनीतिक संसाधन प्रबंधन के साथ नगर निकायों के संचालन की नई परिकल्पना उनकी विकास की संभावनाओं को पूरी तरह बदल सकती है और जटिल शहरी चुनौतियों का ज्यादा कारगर ढंग से समाधान कर सकती है।

आपका पक्ष

भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार

भारत और चीन के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता में सीमा विवाद सुलझाने में कुछ प्रगति हुई है। दोनों देशों ने मानसरोवर यात्रा, सीमा व्यापार और नदी जल बंटवारे जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। हालांकि, चीन की नियंत्रण रेखा पर सैन्य तैनाती को देखते हुए भारत की सतर्कता बरकरार है। वार्ता में दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग और संवाद को मजबूत करने पर जोर दिया है। लेकिन सीमा विवाद का हल निकालने में कुछ चुनौतियां हैं। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए चीन को अपने रवैये में सुधार करना होगा तभी अमेरिकी दबाव से बचना संभव होगा। यह बात चीन अच्छी तरह समझता है कि भारत के सहयोग के बिना वर्तमान अंतरराष्ट्रीय स्थिति में संतुलन कायम रखना संभव नहीं है। भारत और चीन को एक दूसरे के बीच दूरियों को खत्म करके संबंधों की नई परिभाषा लिखनी होगी।

सुभाष बुड़ावनवाला, रतलाम

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल (बाएं) ने पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी

आयकर की दरों में रियायत देना समय की जरूरत

आयकर व्यवस्था में बदलाव की दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि सरकार अब आयकर ढांचे में संशोधन करें। निरंतर बढ़ती बेतहाशा महंगाई के कारण आम जनता विशेषकर मध्यम वर्ग को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। बिगड़ते घरेलू बजट को राहत देने और आयकर बोझ को कम करने के लिए आयकर छूट और मानक छूट की सीमा बढ़ाना जरूरी है। आयकर छूट की सीमा बढ़ाने से बचत में वृद्धि के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

रमेशचंद्र कर्नाट, उज्जैन

मानक कटौती में हो इजाफा

सरकार को कर दरों में कटौती करना चाहिए। जिससे आयकर संग्रह और बढ़ेगा। मानक कटौतियां जैसे 80 सी और 80डी में और बढ़ोतरी करने की जरूरत है। आयकर दाखिल करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटलीकृत करने से आयकर रिटर्न भरना आसान होने के कारण कर संग्रह बढ़ा है। लिहाजा अब नौकरीपेशा व व्यापारी वर्ग को कर में और छूट दी जाए। वरिष्ठ नागरिकों को 70 साल की उम्र पूरी होने पर आयकर में पूर्ण छूट दी जाए।

भगवानदास छारिया, इंदौर

पेंशनर को आयकर से मुक्त रखा जाए

आयकर में छूट सीमा को और बढ़ाया जाना चाहिए। पेंशनरों को आयकर से पूर्णतया मुक्त किया जाना भी आवश्यक है। बैंक द्वारा काटे गए टीडीएस को आयकर में शामिल किया जाना चाहिए। आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए।

ललित महालकरी, इंदौर

ई-कॉमर्स में रुचि

आज लोग अपना समय बचाने और छूट के कारण ऑनलाइन खरीदारी करने लगे हैं। ई-कॉमर्स के क्षेत्र के बढ़ने से बहुत से युवाओं को रोजगार भी मिला है। ई-कॉमर्स के नियमन से देश के छोटे बड़े कारोबारियों और दुकानदारों को कोई नुकसान न हो, इसका सरकार को ध्यान रखना होगा। ई-कॉमर्स देश के शत प्रतिशत लोगों तक अपनी पहुंच बनाए तथा इसका विस्तार गांवों तक भी हो।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को दिल्ली स्थित वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल के छठे दीक्षांत समारोह में प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।

दैनिक जागरण

वास्तविकता को स्वीकार न करना आत्मघाती होता है

खालिस्तानी आतंकी

पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस को पीलीभीत में तीन खालिस्तानी आतंकियों को मार गिराने में जो सफलता मिली, वह एक बड़ी कामयाबी है। इसे इससे समझा जा सकता है कि मारे गए आतंकियों के पास से दो एके-47 राइफलों के साथ विदेशी पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस मिले। माना जाता है कि यही आतंकी पिछले कुछ समय से पंजाब में थानों और चौकियों पर बम फेंककर आतंक का माहौल कायम करने में लगे हुए थे। इनका संबंध खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स नामक आतंकी संगठन से था। चूंकि यह सामने आ रहा है कि विदेश में बैठे खालिस्तानी तत्वों ने पीलीभीत में मारे गए आतंकियों को हथियार उपलब्ध कराए, इसलिए इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि वे ऐसा करने में कैसे समर्थ हो गए? पड़ताल इसकी भी होनी चाहिए कि मारे गए आतंकी पंजाब में थानों और चौकियों को निशाना बनाने के बाद पीलीभीत में क्या करने आए थे? पीलीभीत उनके छिपने के लिए सुरक्षित ठिकाना था या फिर वे यहां कोई वारदात करने की फिराक में थे? इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जिस समय पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद अपने चरम पर था, तब पीलीभीत और उसके आसपास का तराई का इलाका खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बन गया था। उस समय इन आतंकियों ने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। सिख आबादी की ठीक-ठीक संख्या के चलते तराई के इस इलाके को मिनी पंजाब कहा जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस इलाके में खालिस्तान समर्थक फिर से सक्रिय हो गए हैं और उनके चलते ही मारे गए आतंकी पीलीभीत आए हों? जो भी हो, यह ठीक नहीं कि पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है।

खालिस्तानी आतंकियों के बढ़ते दुस्साहस का पता इससे चलता है कि बीते कुछ समय से पंजाब में एक के बाद एक आठ थानों और चौकियों में बम से हमले हो चुके हैं। इन हमलों की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी संगठनों ने अपने सिर ली है। इनमें से एक संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स भी है। पंजाब में थानों और चौकियों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं का आकलन करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आशंका जताई है कि विदेश से संचालित खालिस्तानी आतंकी संगठन पंजाब में कोई बड़ी वारदात करने की ताक में हैं। यह आशंका कितनी प्रबल है, इसका पता इससे चलता है कि चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह ठीक है कि कुछ खाली पड़ी पुलिस चौकियों पर भी बम फेंके गए, लेकिन इन घटनाओं से यह तो पता चलता ही है कि खालिस्तानी आतंकी बेलगाम हो रहे हैं। अब जब पीलीभीत की घटना से यह स्पष्ट हो रहा है कि खालिस्तानी आतंकी पड़ोसी राज्यों में पैर पसार रहे हैं, तो पंजाब पुलिस को ऐसे सभी राज्यों और खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल आदि की पुलिस से अपना सहयोग एवं समन्वय बढ़ाना होगा।

ट्रामा सेंटर की अनदेखी

स्वास्थ्य और शिक्षा दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिनकी अनदेखी कोई भी देश-प्रदेश नहीं कर सकता। इन दोनों क्षेत्रों को गंभीरता से न लेना समाज भी पसंद नहीं करता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रपटें यह साबित करती हैं कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को उन्नत बनाने के दावों के बावजूद वास्तविकता कुछ और ही है। धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रस्तुत की गई कैग की रिपोर्ट में यह हैरान करने वाला विषय है कि 2015 से लेकर 2022 के बीच प्रदेश की सरकारें ट्रामा सेंटर स्थापित करने की दिशा में गंभीरता नहीं दिखा पाईं। इससे भी बड़ी हैरानी इस बात की है कि केंद्र सरकार से आठ ट्रामा सेंटर खोलने के लिए केंद्र एवं प्रदेश सरकार ने 38 करोड़ रुपये जारी किए। पैसा होने के बावजूद इस दौरान प्रदेश में सिर्फ एक ट्रामा सेंटर ही स्थापित हो पाया। इस वर्ष शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में दूसरा ट्रामा सेंटर शुरू हुआ है। हिमाचल प्रदेश जैसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश में ट्रामा सेंटर का महत्व कोई रहस्य नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़ी दुर्घटना होने के बाद घायलों का उपचार करवाने के लिए स्वजन को चंडीगढ़, लुधियाना या जालंधर के अस्पतालों में भटकना पड़ता है। यह समय अत्यंत संवेदनशील होता है और स्वजन को जीवन बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। आशा करनी होगी कि प्रदेश सरकार इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेगी और केंद्र से मिले पैसे का सदुपयोग कर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ट्रामा सेंटर स्थापित करने के प्रयास में तेजी लाएगी।

> हिमाचल जैसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में ट्रामा सेंटर के प्रति अगंभीरता उचित नहीं है

नए रूप में साम्राज्यवादी शक्तियां

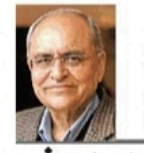

बलबीर पुंज

वर्तमान में साम्राज्यवादी तत्वों ने सांस्कृतिक, सामाजिक, मजहबी और आर्थिकी पर गढ़े जाने वाले नैरेटिव को अपना हथियार बना लिया है

संसद के हालिया सत्र का एक बड़ा हिस्सा विवादित अमेरिकी उद्यमी जार्ज सोरोस को लेकर सत्तापक्ष एवं विपक्ष में तल्ख बयानबाजी की भेंट चढ़ गया। सोरोस उस अधिनायकवादी और साम्राज्यवादी विचारधारा के प्रतीक हैं, जो अपने वैश्विक दृष्टिकोण और व्यापारिक-रणनीतिक हितों के लिए वैश्विक भूगोल, इतिहास और संस्कृति को बदलने पर आमादा हैं। यह रहे पारंपरिक औपनिवेशवाद के दिन अब लद चुके हैं। अब न तो सैन्यबल से किसी समाज को नष्ट किया जाता है और न ही किसी देश पर कब्जे से। इसके बावजूद साम्राज्यवादी मानसिकता का अंत नहीं हुआ है। उसने केवल अपना चोला बदला है। अब इसके हथियार सांस्कृतिक, सामाजिक, मजहबी और आर्थिकी पर गढ़ा जाने वाला नैरेटिव है। विदेशी ताकतें लक्षित देशों में बिकाऊ लोगों की एक फौज खड़ी करती हैं, जो लोग इशारा मिलते ही उनके बनाए नैरेटिव पर अपने देश को विरूपित करना शुरू कर देते हैं। इससे माहौल बिगड़ना शुरू हो जाता है।

अपने कुत्सित इरादों की पूर्ति के लिए सोरोस ने दुनिया भर में दांव लगाए हैं। इसी कड़ी में 94 वर्षीय सोरोस ने कई अमेरिकी मीडिया संस्थाओं में निवेश किया है। उनकी कुल संपत्ति 44 अरब डालर है, जिसका बड़ा हिस्सा उन्होंने 'मानवाधिकार' और 'लोकतंत्र' के नाम पर खर्च किया है। इस उपक्रम का उद्देश्य दुनिया को अपनी कल्पना के अनुरूप ढालना और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना है। यही कारण है कि सोरोस पर दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने का आरोप है। वर्ष 1992 में इंग्लैंड के बैंकों को बर्बाद करके अकूत धन अर्जित करना, 1997 में थाइलैंड की करेंसी को गिराना, 2002 में फ्रांसीसी अदालत द्वारा अनैतिक-अनधिकृत व्यापार का दोषी ठहराना और कई देशों द्वारा सोरोस की संस्थाओं पर जुर्माना-प्रतिबंध लगाना इसके कुछ उदाहरण हैं। सोरोस और उनकी संस्था अपने नापाक एजेंडे की पूर्ति के लिए अक्सर समाजसेवा और परोपकार का मुखौटा लगाए रहते हैं।

भारत सहित तमाम देश विदेशी ताकतों के व्यापक हस्तक्षेप के भुक्तभोगी रहे हैं। इसके प्रभावों की गहन पड़ताल भी हुई है। राजनयिक नरेंद्र सिंह सरीला ने अपनी पुस्तक 'विभाजन की असली कहानी' में लिखा कि अंग्रेजों ने दुनिया के इस हिस्से में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भारत का विभाजन करके इस्लामी पाकिस्तान को जन्म दिया था। इसके लिए अंग्रेजों ने 'भारतीयों' का ही उपयोग किया। अब सोरोस जैसे लोग भी उसी काम में लगे हैं।

अवधेश राजपूत

बीते दिनों सीरिया में जो हुआ, वह किसी से छिपा नहीं। उससे पहले बांग्लादेश भी नाटकीय घटनाक्रम का साक्षी बना। यह सब विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप और संघर्ष का परिणाम रहा। ऐसे में सोरोस का भारत के आंतरिक मामले में बार-बार दखल देना और उन्हें मिल रहा प्रत्यक्ष-परोक्ष भारतीय समर्थन हमें इतिहास के काले पन्नों की ओर ले जाता है। क्रूर औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में मुगल शासन कमजोर पड़ा तो मराठा परचम अटक से कटक तक लहरा रहा था। तब सूफी प्रचारक शाह वलीउल्लाह देहलवी ने अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण के लिए लंबी चिट्ठी लिखी, क्योंकि वह 'काफिर' मराठों को पराजित कर भारत में पुनः इस्लामी राज स्थापित करना चाहता था। जब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, तब वलीउल्लाह द्वारा आमंत्रित अब्दाली को भारत में पश्तून रोहिल्लाओं, बलूचियों, शुजाउद्दौला आदि नवाबों के साथ स्थानीय मुस्लिमों का समर्थन मिला और उन्होंने मिलकर मराठों को पराजित कर दिया। इसने मराठाओं का बल घटा दिया, जो वर्ष 1803 के दिल्ली (पटपड़गंज) युद्ध में मराठों की अंग्रेजों के हाथों मिली पराजय का एक बड़ा कारण बना। वलीउल्लाह के विचार ही तालिबान के आधार रहे।

यदि 18वीं शताब्दी में 'अपनों' ने अब्दाली को बुलाया नहीं होता या फिर मीर जाफर-जयचंद ने 'अपनों' को धोखा नहीं दिया होता, तो संभवतः भारत का इतिहास कुछ और होता। दुर्भाग्य से अब भी बहुत कुछ वैसा ही है। अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति हेतु आज भी कई 'अपने' आत्मसम्मान और हितों को दांव पर लगा रहे हैं। कई अवसरों पर कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी असंतोष जता चुके हैं कि अमेरिका या कोई यूरोपीय देश भारत के आंतरिक मामलों पर कुछ क्यों नहीं बोलते। अगस्त 2020 में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन भी एक लेख के माध्यम से तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मोदी सरकार को अपनी नीतियां लागू करने के लिए 'फ्री-पास' देने पर आपत्ति जता चुके थे। ऐसे उदाहरण अंतहीन हैं।

ब्रिटिशराज से पहले भारत विश्व की बड़ी आर्थिक महाशक्ति था। पहले अंग्रेजी दासता और स्वतंत्रता के 50 वर्षों के लिए वामपंथ प्रेरित समाजवादी विचारधारा ने भारत का दिवाला निकाल दिया। भारतीय उद्यमिता को 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद नया जीवन मिला और 2014 के बाद उसे तेजी के नए पंख लगे। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। वैश्विक राजनीति में भारत अग्रिम देशों की पंक्ति में है। ऐसे में, कोई आश्चर्य नहीं कि कुंठित औपनिवेशिक शक्तियां भारत की विकास की गाड़ी को पटरी से उतारना चाहती हैं। अफसोस कि हमारे एक वर्ग ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा और वह सत्ता हथियाने हेतु वही पुरानी गलतियां दोहरा रहा है।

(स्तंभकार हाल में प्रकाशित 'ट्रिस्ट विद अयोध्याः डिकालोनाइजेशन आफ इंडिया' पुस्तक के लेखक हैं)

response@jagran.com

और सरल बने टैक्स की व्यवस्था

डा. जयंतीलाल भंडारी

विकसित भारत के लिए कर सुधारों के साथ-साथ कर संग्रह में लगातार वृद्धि भी जरूरी है

हाल में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की बैठक में जीएसटी के सरलीकरण एवं राहत संबंधी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। छोटे कर्जदारों को राहत दी गई। अब ऋण शर्तों का पालन नहीं करने पर ऋणदाताओं द्वारा जो जुर्माना लगाया जाएगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। खास किस्म के फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी कम किया गया है। कैंसर की जीन थेरेपी को कर मुक्त किया गया है। साथ ही पुराने वाहनों की बिक्री पर कर की दर को 18 प्रतिशत कर दिया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार ने आयकर अधिनियम सरल बनाने के लिए मुख्य आयकर आयुक्त बीके गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। यह समिति कर रियायतों को तर्कसंगत बनाने, कर गणना के तरीके का स्तर बढ़ाकर इसे विश्वस्तरीय बनाने और अपील करने की व्यवस्था में जटिलता कम करने संबंधी सुधारों पर तेजी से काम कर रही है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर नए आयकर विधेयक का मसौदा तैयार किया जाएगा। वास्तव में आयकर अधिनियम, 1961 की करीब 90 धाराएं अप्रासंगिक हो चुकी हैं। ये धाराएं विशेष आर्थिक क्षेत्र, दूरसंचार, पूंजीगत लाभ सहित कर छूट एवं कटौती जैसे मामलों में कारगर नहीं रह गई हैं। इनमें सुधार होने से कानूनी जटिलताएं और मुकदमेबाजी में काफी कमी आएगी तथा कर कटौती प्रक्रिया अधिक सरल एवं पारदर्शी होगी।

पिछले एक दशक में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में सुधारों का सिलसिला तेज हुआ है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। देश में अंग्रेजों ने 1922 में आयकर की शुरुआत की थी। आजादी के बाद वर्ष 1961 में आयकर अधिनियम लागू किया गया, लेकिन इसमें कार्यान्वयन संबंधी जटिलताएं रहने से विभिन्न रियायतों और छूटों के कारण कर अनुपालन में मुश्किलें भी बढ़ती गईं। यद्यपि इन कमियों को दूर करने के लिए प्रयास किए जाते रहे, लेकिन पिछले एक दशक से आयकर कानून में जो अहम सुधार किए गए हैं, उससे आयकरदाताओं को सुविधा मिलने के साथ उनकी संख्या बढ़ाने में भी मदद मिली है। इनमें देश भर में करदाताओं के लिए लागू फेसलेस अपील व्यवस्था, टैक्सपेयर चार्टर और फेसलेस असेसमेंट जैसे बड़े आयकर सुधार प्रमुख हैं। इसके अलावा नान फाइलर्स मानिटरिंग सिस्टम के जरिये ऐसे लोगों की पहचान की जाती है, जिन्होंने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है, लेकिन आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इसके कारण पिछले 10 वर्षों में आयकर संग्रह में करीब 182 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में आयकर संग्रह लगभग चार गुना बढ़कर 10.45 लाख करोड़ रुपये रहा। मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष से अधिक आयकर रिटर्न और आयकर प्राप्ति की संभावना दिखाई दे रही है।

जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री। प्रेट्र

आयकर संबंधी सुधारों से जिस तरह आयकरदाताओं की संख्या और आयकर राशि में तेजी से इजाफा हुआ है, उसी तरह जीएसटी के लागू होने से अप्रत्यक्ष कर में भी हुआ है। जीएसटी के तहत 17 केंद्रीय और राज्य स्तरीय टैक्स के साथ-साथ करीब 23 अलग-अलग तरह के उपकरों को समाहित किया गया है। जीएसटी विनिर्माताओं, कारोबारियों, निर्यातकों और आम लोगों के लिए लाभप्रद बन गया है। जीएसटी लागू होने के पूर्व वित्त वर्ष 2016-17 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह (केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क आदि) से करीब 8.63 लाख करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई थी। जीएसटी के बाद टैक्स संग्रहण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में जीएसटी संग्रहण 20.18 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, जो पूर्ववर्ती साल के मुकाबले 11.7 प्रतिशत अधिक था। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से नवंबर के बीच जीएसटी संग्रह पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि के मुकाबले नौ प्रतिशत बढ़कर 14.56 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

हालांकि आयकर और जीएसटी संग्रहण में वृद्धि के बावजूद अभी भी भारत का कर-जीडीपी अनुपात करीब 11.7 प्रतिशत है, जबकि कई विकासशील देशों में यह अनुपात अधिक है। इसे देखते हुए देश में आयकर एवं जीएसटी के कर दायरे में वृद्धि के उपाय खोजे जाने चाहिए। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर सुधारों के साथ कर संग्रह में लगातार वृद्धि जरूरी है। ऐसे में आयकर प्रणाली के साथ जीएसटी की जटिलताओं को कम करके इसे अधिक सरल एवं कारगर बनाना होगा। जीएसटी अनुपालन जितना अधिक कारगर होगा, उतना ही अधिक जीएसटी संग्रह बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा जीएसटी चोरी के खिलाफ अभियान चलाना होगा, क्योंकि अभी कई कारोबारी फर्जी बिल के साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही जीएसटी दरों के साथ जीएसटी स्लैब को कम किया जाना चाहिए। जीवन और स्वास्थ्य बीमा की खरीदारी पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी में राहत दी जानी चाहिए। बिक्रय कामर्स कंपनियों पर लगने वाले जीएसटी को लेकर निर्णय लिया जाना चाहिए। पेट्रोलियम उत्पादों और रियल एस्टेट को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए।

(लेखक एग्रोपोलिस इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, इंदौर के निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

इच्छा

मनुष्य के मन में अनेकानेक इच्छाएं नित्य उत्पन्न होती रहती हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य की समस्त इच्छाएं, कामनाएं पूर्ण ही होती हैं, कुछ शेष भी रह जाती हैं। जब मनुष्य की कोई इच्छा पूर्ण होती है तो वह सुख का अनुभव करता एवं खुश होता है और जब कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती तो दुखी होता है। यही मानवीय स्वभाव की विडंबना है।

मनुष्य को अपने मन-मस्तिष्क को सदा सकारात्मक रखना चाहिए। किसी प्रकार के स्वार्थ, लोभ का भाव मन में नहीं होना चाहिए। इच्छा पूर्ण एवं अपूर्ण होने की स्थिति में खुश एवं दुखी होना मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन लोगों को संतों की तरह दुख-सुख से परे होने का प्रयास करना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, नहीं हुआ सो नहीं। पीछे की बातों में उलझने से आगे बढ़ना मुश्किल होता है। आगे की बात व्यक्ति सोच नहीं पाता और पीछे की बातों पर अफसोस करने में व्यक्ति उलझा रह जाता है। जो अपूर्ण इच्छा है, उसे पूर्ण करने में सदा कर्मठतापूर्वक जुटे रहें। हो सकता है भविष्य में वह पूर्ण हो जाए, क्योंकि जिस कार्य में मेहनत की जाती है, उसका फल कभी जरूर मिलता है। देर भले हो, पर कर्म का फल अवश्य मिलता है। ज्ञानी लोगों की इच्छा कभी अपूर्ण नहीं रहती। वे प्रभु-भक्ति करके सब कुछ पा लेते हैं। प्रभु के दरबार में कुछ दुर्लभ नहीं, किंतु व्यक्ति प्रभु का भक्त बन जाए तभी ऐसा संभव है। प्रभु किसी तरह से अपने भक्त की अभावग्रस्त नहीं रहने देते। भगवान भक्त की इच्छा को जानते हैं, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। भक्त की इच्छा भगवान की इच्छा होती है। जब सुदामा ने श्रीकृष्ण की शरण ली तो सुदामा को सब प्राप्त हो गया। इसलिए प्रभु भक्ति की इच्छा जागृत करना जीवन के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ है।

मुकेश ऋषि

मलेरिया को रोकेंगे मच्छर

प्रदीप

हाल में शोधकर्ताओं ने मलेरिया का एक नया टीका विकसित किया है, जो मच्छरों के माध्यम से इंसानों को दिया जाता है

मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक नई और क्रांतिकारी खोज सामने आई है। विज्ञानी अब एक ऐसे टीके (वैक्सीन) पर काम कर रहे हैं, जिसे मच्छरों के डंक के माध्यम से दिया जा सकता है। यह दृष्टिकोण टीकाकरण की पारंपरिक विधियों से बिल्कुल अलग है और मलेरिया उन्मूलन की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। हाल में नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने मलेरिया का एक नया टीका विकसित किया है, जो मच्छरों के माध्यम से इंसानों को दिया जाता है। इस टीके में प्लाज्मोडियम फाल्सिपैरम (मलेरिया फैलाने वाले परजीवी) का कमजोर जीन संस्करण डाला गया है। यह परजीवी मलेरिया का संक्रमण नहीं फैलाता, लेकिन इंसान की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करता है। इस परजीवी को जीन-संपादित मच्छरों में डाला गया है। जब ये मच्छर किसी व्यक्ति को काटते हैं, तो उनकी लार के साथ कमजोर परजीवी इंसान के शरीर में प्रवेश करता है। परजीवी इंसान के शरीर में पहुंचने के बाद प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है, जिससे इंसानों को मलेरिया के गंभीर संक्रमण से बचाने में मदद मिल सकती है। दरअसल शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इसे पहचान कर उसके खिलाफ एंटीबाडी विकसित कर लेती है।

विज्ञानियों द्वारा हालिया विकसित टीका सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है, जो मलेरिया के इलाज में कारगर साबित हो सकता है। इस टीके को जीए2 कजन पैरासाइट नाम दिया गया है। इसका नौ लोगों पर परीक्षण भी किया गया था, जिसमें आठ लोगों को मलेरिया मुक्त पाया गया है। इस पैरासाइट को मच्छरों में भी डाला जा सकता है, ताकि जब ये इंसानों को काटे तब ये पैरासाइट इंसान के शरीर में चला जाए। इससे उनके शरीर में मलेरिया के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित हो जाएगी। यह विधि टीके की एक नई तरह की 'हिलीबर्ड सिस्टम' बन सकती है, जिससे मच्छरों को एक प्रकार का 'जीवित वैक्सीन वाहक' बनाया जा सकता है। मलेरिया एक घातक और संक्रामक बीमारी है, जिसका प्रमुख कारण प्लाज्मोडियम नामक परजीवी है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मानव रक्त में प्रवेश करता है।

इस तकनीक को वैश्विक स्तर पर लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर मच्छरों का उत्पादन और उनका सही प्रबंधन एक चुनौती हो सकता है। यह तकनीक न केवल मलेरिया के खिलाफ एक प्रभावी हथियार हो सकती है, बल्कि अन्य मच्छर-जनित बीमारियों, जैसे डेंगू और जीका वायरस के टीकों के विकास में भी मदद कर सकती है।

(लेखक विज्ञान संचारक हैं)

सस्ती हो मेडिकल की पढ़ाई

'छात्रों के विदेश जाने का बढ़ता चलन' शीर्षक से लिखे आलेख में प्रणय कुमार ने देश की प्रतिभाओं का विदेश रुख करना देश के लिए हानिकारण बताया है। देश के युवाओं का विदेश जाकर पढ़ाई और नौकरी करने का एक लाभ भी है। भारतीय मूल के लोग विदेश में अपनी ईमानदारी और मेहनत से भारत की छवि अच्छी बनाते हैं। अमेरिका के विकास में भारतीय मूल के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। सवाल है कि आखिर भारत के होनहार पढ़-लिख कर क्यों दूसरे देशों का रुख कर लेते हैं? क्या उनकी प्रतिभा और योग्यता की भारत में कोई कद्र नहीं होती है? क्या सरकारों की बेरुखी उनको भारत छोड़ने पर मजबूर कर देती है? या फिर ज्यादा कमाई के चक्कर में वे भारत से चले जाते हैं? इन सवालों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को देश में ही अच्छे मौके मिलने शुरू हो जाएं तो भारत टेक्नोलाजी, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में दुनिया में नंबर वन बन जाएगा। हमारे देश में बहुत से प्रतिभाशाली युवा आर्थिक तंगी के कारण चिकित्सा की पढ़ाई नहीं कर पाते। सरकार को चाहिए कि वह चिकित्सा की पढ़ाई को सस्ती करने की तरफ गंभीरता दिखाए। जो युवा इस क्षेत्र में कुछ कर दिखाना चाहते हैं उनकी हरसंभव मदद करे, ताकि देश में चिकित्सकों की संख्या बढ़े और इसकी पढ़ाई करने उन्हें विदेश का रुख न करना पड़े।

raju09023693142@gmail.com

मेलबाक्स

भारत की बढ़ती भूमिका

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान "द आर्डर आफ मुबारक अल-कबीर" सम्मान से नवाजा गया है। यह पुरस्कार कुवैत सरकार द्वारा मित्रता के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। इससे पहले यह सम्मान बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स एवं जार्ज बुश को भी दिया जा चुका है। सभी भारतीयों को देश के प्रधानमंत्री पर गर्व करना चाहिए, जिनके कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान मजबूत हुई है और विश्व के ज्वलंत मुद्दों पर भी भारत की दखल और भूमिका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। यह भारत की बढ़ती साख का परिणाम है कि पिछले दिनों यूएई की राजधानी अबू धाबी में एक भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया था। जिसका उद्घाटन नरेन्द्र मोदी ने किया था। खाड़ी देशों से भारत के अच्छे संबंध के खास मायने हैं। इन देशों के साथ व्यापार, पर्यटन औद्योगिक सहभेदारी बढ़ेगी। भारत की कूटनीतिक-राजनीतिक समझ के कारण इन खाड़ी देशों को आतंकवाद के विरुद्ध भारत का समर्थन एक बड़ी जीत है।

बीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

एक भाव है अहिंसा

अहिंसा का अर्थ है अगाध प्रेम और प्रेम का अर्थ है कष्ट सहने की अपार क्षमता। अहिंसा बाहर से सीखा गया गुण नहीं है। जैसे फूल में सुगंध, चीनी में मिठास और पानी में शीतलता है, वैसे ही आत्मा में अहिंसा उसका व्यवहारिक गुण है। पानी का स्वभाव शीतलता है। आग पर पानी को गरम कर दें तो कालांतर में वह शीतल हो जाएगा। पानी अपने मूल स्वभाव को प्राप्त कर लेगा। हम जहां-जहां भी हिंसा देखते हैं, वहां ऊपर से ओढ़ा गया विकार है। हिंसा कभी स्थायी नहीं रहती। सिंह हिंसक प्राणी है, पर भरे पेट वाला सिंह कभी भी हिंसा नहीं करेगा। कसाई अपने पालतू जानवरों को न तो कष्ट देता है और न दूसरे को मारने देता है। अशोक को कलिंग युद्ध में हिंसा से विरक्ति हुई और वह इतिहास प्रसिद्ध अहिंसक शासक हुए। इसका कारण उसका अपनी आत्मा के स्वभाव में लौट आना था। काकभुशुण्डि से गरुड़ जी ने पूछा कि सबसे ऊंचा धर्म कौन सा है तो काकभुशुण्डि ने उत्तर दिया-वेदों में प्रतिपादित अहिंसा ही सबसे बड़ा परम धर्म है। यानी इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*

विचार
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। मंगलवार, 24 दिसंबर 2024

धर्म की सही समझ

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को अमरावती में एक कार्यक्रम के दौरान जो कुछ कहा, वह हालिया घटनाओं की रोशनी में खासा अहम हो जाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में धर्म के नाम पर जितने भी अन्याय, अत्याचार होते हैं उनके पीछे धर्म की गलत समझ काम कर रही होती है। बीते सप्ताह ही RSS प्रमुख ने यह भी कहा था कि जगह-जगह मंदिर विवाद खड़े करना ठीक नहीं है। संघ प्रमुख के बयानों के पीछे छिपी चिंता को समझे जाने की जरूरत है।

धर्म की जटिलता | संघ प्रमुख ने बिल्कुल ठीक कहा कि धर्म बड़ा जटिल विषय है और इसे समझने में अक्सर गलती होने की आशंका रहती है। कब धर्म की उदार वृत्ति पर संप्रदाय विशेष की संकीर्ण दृष्टि काबिज हो जाती है और कब धार्मिक समावेशिता को सांप्रदायिक कट्टरता ढक लेती है, यह कई बार समझ में नहीं आता। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में देखा जाए तो, बांग्लादेश के बनने के बाद पाकिस्तान के सत्ता परिवर्तन ने कैसे समाज को कट्टरपंथी तत्वों के चंगुल में ला दिया, यह सबके लिए सबक हो सकता है।

संघ प्रमुख का अहम संदेश

खतरा वास्तविक | ऐसे उदाहरण दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिलते हैं। एक धर्म विशेष के नाम पर पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में आतंकवाद का जैसा खौफनाक अभियान चला, उसे उस धर्म की सही समझ का उदाहरण कतई नहीं माना जा सकता। लेकिन संघ प्रमुख की बातें सिर्फ दूसरे देशों के संदर्भ में नहीं कही गई हैं। धर्म की गलत व्याख्या के कारण 'सबका साथ, सबका विकास' का अजेंडा पीछे छूटने का खतरा अपने देश में भी कम नहीं है।

एकता के सूत्र | इसी खतरे की ओर संकेत करते हुए संघ प्रमुख ने कहा है कि जगह-जगह मंदिर का विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है। विविधताएं हमारा वर्तमान तो हैं ही, ये हमारे अतीत का भी हिस्सा रही हैं। अलग-अलग धर्म, संस्कृति से जुड़े लोग यहां आते रहे, शुरुआती मतभेद और कड़वाहट दफन करते हुए विशाल भारतीय संस्कृति में घुलते-मिलते रहे। तभी इन विविधताओं के बीच एकता के मजबूत सूत्र विकसित हुए। देश भर में ऐसे हजारों श्रद्धाकेंद्र हैं जहां एक से अधिक धर्मों के चिह्न, संकेत, सबूत ढूंढे जा सकते हैं। इस आधार पर वर्तमान में विवाद खड़ा करना हमें कहीं नहीं ले जाएगा।

विकास में बाधा | इसी खतरे से बचने के लिए कानून के जरिए यह तय किया गया कि देश की आजादी के वक्त जिस पूजा स्थल का जैसा स्वरूप था, उसे अंतिम मान लिया जाए। अब चाहे जिस किसी भी बहाने से ऐसे विवाद खड़े किए जाएं, वे सामाजिक समरसता के लिए ठीक नहीं होंगे और देश के विकास में बाधा बनेंगे।

धूप-छांव

चाय? ना से हां तक

प्रणव प्रियदर्शी

'मैं चाय नहीं पीता', एक समय था जब यह वाक्य मुझे आसपास की प्रशंसात्मक निगाहों का निशाना बना दिया करता था। बचपन में घर का माहौल ऐसा था, जिसमें 'बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए' या 'अच्छे बच्चे चाय नहीं पीते' जैसे नहीं वचनों को किसी तरह की चुनौती मिलने की कोई संभावना नहीं रहती थी। सो, परिजनों, संबंधियों, करीबी पारिवारिक मित्रों के जुटान के किसी भी मौके पर जब 'कौन-कौन चाय पिएगा' जैसा सवाल सामने आता तो मेरे जवाब पर किसी न किसी के मुंह से 'वाह' निकल ही जाता। चाय का स्वाद न मिलने के गम की उन प्रशंसात्मक निगाहों से भरपाई हो जाया करती थी।

पहली बार इस मूल्यबोध को चुनौती मिली दसवीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान, जब आसपास के सहपाठी मित्रों में से कई यह बताते कि यार रात को नींद का झोंका आया, तो किचन में जाकर खुद ही चाय बना ली। गरमागरम चाय के उस प्याले ने फिर से फ्रेश कर दिया। रात को जागकर पढ़ाई करने का अपना ग्लैमर था और जो चाय उसमें मदद कर रही हो, वह भला बुरी चीज कैसे हो सकती है? जाहिर है, रात वाली यह चाय भी प्रशंसा भरी निगाहें पाने में उतनी ही मददगार हो सकती थी, जितनी 'मैं चाय नहीं पीता' वाला जवाब। बल्कि उलटा था। दसवीं तक पहुंचते-पहुंचते आप वैसे मासूम बच्चे नहीं रह जाते कि उस जवाब से सब प्रसन्न हों। फिर भी मेरा जवाब कायम रहा। और एक बार पारिवारिक जुटान के ऐसे ही मौके पर जब सबके लिए चाय आई तो मैंने आदतन मना किया, पर मेरे साथ ही बैठी एक हमउम्र बहन ने लपक कर कप ले लिया। फिर चुस्की लेते हुए जोर से बोली, 'पता नहीं किस बेवकूफ ने यह कहा कि चाय पीना स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। देखो, मैं चाय पीती हूं और ये चाय नहीं पीता।' उसका हाइ-कट्टा स्वस्थ बदन और वहीं बगल में दुबला-पतला बेचारा-सा मैं, कमरा अगले ही पल ठहाकों में डूब चुका था।

बहरहाल, चाय पीना शुरू करने की जरूरत शिद्दत से महसूस हुई कुछ साल बाद, जब घर-परिवार के दायरे से निकल कर मैं प्रफेशनल दुनिया का हिस्सा बना। यहां चाय ऑफर करना सामान्य शिष्टाचार था। 'चाय नहीं पीता' जैसा जवाब दो तरह की प्रतिक्रियाएं पैदा करता। एक तो यह कि सामने वाला आपको मासूम बच्चा समझता। दूसरे, उसके चेहरे पर असमंजस के भाव आते कि अब क्या पूछा जाए- कॉफी या ठंडा? ये चाय जितना आसान विकल्प नहीं हुआ करते थे। ऐसे में सबसे आसान यही था कि इस जवाब को अलविदा कह दिया जाए। सो कह दिया। हालांकि बचपन की उस एक अच्छी आदत का छूटना एक मूल्यबोध से मुक्त होना था जिसके अपने खतरे भी कम नहीं होते।

बोल वचन

सुलग रहा कउरा

राहुल पाण्डेय

सर्दी आ गई है, कउरा जल चुका है। क्या बूढ़-पुरनिया, क्या बच्चे, क्या जवान- अब तो कउरा ही सबसे बड़ा सुख है। गांव ही नहीं, शहर के चौक-चौराहों पर भी कउरा जल रहा है। कउरा, यानी अलाव, यानी bonfire. वैसे bonfire में सिर्फ लकड़ी में आग लगाते हैं, लेकिन कउरा में गोबर के कंडे प्रमुख हैं। कंडे के अलावा इन दिनों धान का पैरा भी खूब होता है। Bonfire और कउरे में एक और फर्क यह है कि एक जलता ज्यादा है तो दूसरा सुलगता ज्यादा है। कहते भी हैं कि फलाने जलकर कउरा हो रहे हैं, यानी आधे जले हैं, आधे सुलग रहे हैं। साथ में भुन भी रहे हैं क्योंकि भूनने की भी कउरना कहते हैं। जलने-भूनने और सुलगने से इतर कउरा कौर भी कहलाता है, यानी निवाला। अवध से लेकर बघेलखंड में कहावत है, जियत न देवै कउरा, मरत उठावै चउरा। जीते जी तो एक निवाला न खिलाया, मरने पर भात खाने आए हैं। गाय-भैंस के लिए उनके मालिक जो रोटी या अन्न का हिस्सा रातिब के तौर पर अलग रखते हैं, उसे भी कउरा कहते हैं। बघेलखंड में कउरा भीख को भी कहते हैं तो हिंदी में कहीं-कहीं कउरा कड़वा अर्थ भी पाता है। वैसे जिस कउरे को हम सर्दी में एकदम सामने रखते हैं, जब वही जाति में जाता है तो पिछड़ा हो जाता है। झारखंड में एक कउरा जाति है, जो पिछड़ों में आती है। इतने सारे कउरे के सामने अंग्रेजी का bonfire तो टिक नहीं सकता। वैसे भी लंबा टिकने के लिए सुलगना जरूरी होता है, और सुलगता तो सिर्फ कउरा ही है, या फिर कउरे जैसा दिल!

Subrata Char

अवैध आप्रवासी भारतीय इकॉनमी, राजनीति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पेश कर रहे हैं

बांग्लादेश से घुसपैठ क्यों है ख़तरनाक

पूर्णिमा शर्मा

भारत में NH 44 की लंबाई श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 4,110 किलोमीटर है। करीब इतना लंबा ही है भारत-बांग्लादेश का 4,096 किलोमीटर लंबा बॉर्डर जो जंगल, पहाड़ और नदियों के बीच से गुजरता है। बॉर्डर से अवैध बांग्लादेशी का घुसना भारत के लिए सीमा पर सबसे गंभीर समस्या है।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर | ये अवैध प्रवासी भारत की अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रहे हैं। ये बॉर्डर के इलाकों में तो बस ही चुके हैं, देश के लगभग हर राज्य तक पहुंच चुके हैं। ऐसे लोगों का सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बसना देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, खासतौर पर जब चीन, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं।

राजनीति पर असर | 2003-04 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेशी घुसपैठिए 25 लोकसभा सीटों और 120 विधानसभा सीटों पर प्रभावी भूमिका में हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि 2003 तक दिल्ली में 6 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए भारतीय पहचान पत्र हासिल कर चुके थे। लगभग यही स्थिति देश के कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में हो सकती है।

ISI का खेल | सितंबर 11, 2001 के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने बांग्लादेश में आतंकी गतिविधियां और तेज कर दी थीं। 2002 में कोलकाता में कई ISI एजेंटों की गिरफ्तारी हुई थी, जो बांग्लादेश बॉर्डर पार कर भारत आए थे। तब भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने संसद में कहा था, 'ढाका में पाकिस्तानी हाई कमिशन, ISI का नर्व सेंटर है, जो भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में लिप्त है।'

आतंकवादियों की सक्रियता | अक्टूबर 2002 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने बांग्लादेश में चल रहे 99 आतंकी ट्रेनिंग कैंपों की लिस्ट बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को सौंपी थी। 2002 में बांग्लादेश में अल कायदा, रोहिंग्या और कट्टरपंथी ताकतों के नेक्सस की रिपोर्ट भी मिली। यह नेक्सस अमेरिका के अफगानिस्तान में एक्शन के बाद और मजबूत हुआ, अल कायदा के 150 आतंकवादियों ने बांग्लादेश में शरण ली। सबसे खतरनाक बात यह थी कि इन्हें बांग्लादेश में प्रशासन और आर्मी का सपोर्ट मिला। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके में अल कायदा आतंकियों के मूवमेंट से भारत के लिए खतरा पैदा होने लगा। म्यांमार, चिटगांव और समुद्र के करीब होने से आतंकियों के लिए कॉक्स बाजार से कहीं भी जाना आसान था। इस इलाके में कई आतंकी संगठनों के कैंप की मौजूदगी भी रिपोर्ट हुई।

घुसपैठ का असर

- कई चुनावी क्षेत्रों में प्रभावी भूमिका
- आतंकवादी समूहों की रहती है नजर
- पुलिस-प्रशासन को सतर्क होना होगा

दिल्ली में रविवार 22 दिसंबर को अवैध बांग्लादेशियों की पहचान का पुलिस अभियान

घुसपैठ में बढ़ोतरी | करीब 25 साल पहले, साल 2000 में भारत के गृह सचिव माधव गोडबोले ने भारत सरकार को एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा गया था कि करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि सालाना 3 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी अवैध तरीकों से भारत में घुसते हैं। पिछले 25 सालों में इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है।

सिन्हा ने चेताया | असम के गवर्नर रहे एसके सिन्हा ने 1998 में भारत के राष्ट्रपति को सौंपी एक रिपोर्ट में लिखा था कि जिस तेजी से अवैध बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ रही है, एक समय ऐसा आ सकता है, जब वे इंटर बांग्लादेश की मांग करने लगें। यानी ये कहें कि भारत के जिन इलाकों में अवैध बांग्लादेशियों की आबादी बढ़ गई है, उन्हें भी बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। जनरल सिन्हा ने इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए इसके राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक खतरों से भी आगाह किया था।

बिचौलिए बेलगाम | बांग्लादेश और भारत की सीमा के करीब फर्जी आधार कार्ड और बाकी भारतीय पहचानपत्र बनाने वाले बिचौलियों की बात भी लगातार सामने आती रही है। इनसे पता चलता है कि कोई बांग्लादेशी बाद में भारत में दाखिल होता है, बिचौलिए पहले ही उसका फर्जी पहचानपत्र बनवा लेते हैं। ये सीमा के दोनों ओर मौजूद हैं। ऐसे में अवैध बांग्लादेशियों के लिए घुसपैठ करना आसान हो जाता है।

प्रशासन हो सक्रिय | दूसरी ओर, वीजा लेकर भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी आते हैं, लेकिन उनमें कई वापस नहीं लौटते। साल 2023 में करीब 16 लाख बांग्लादेशी वीजा लेकर भारत आए थे। इनमें से कितने वापस गए? और कितने पासपोर्ट फाड़ कर गायब हो गए? इसे लेकर पूरे देश में आइडेंटिफिकेशन ड्राइव चलाने की जरूरत है। इसके अलावा, सभी राज्य सरकारों, खास तौर पर बॉर्डर से सटे राज्यों की पुलिस और जिला प्रशासन को घुसपैठियों को पकड़ने और फ्राड कर फर्जी पहचानपत्र बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

बॉर्डर गाइडलाइंस | हालांकि 1974 में जब भारत-बांग्लादेश बॉर्डर गाइडलाइंस बनी थी, तब बांग्लादेश में माहौल बिल्कुल अलग था, तब शायद भारत को भी अंदाजा नहीं था कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ ऐसा माहौल होगा जैसा अब है, लिहाजा अब भारत-बांग्लादेश बॉर्डर गाइडलाइंस की समीक्षा की भी जरूरत है।

'स्मोकिंग ज़ोन' का माफिक 'मारामारी ज़ोन'

दीपक पाण्डेय

अबी दो दिन पैले अपुन अपना फ्रेंड का पास बैठैला। तुम उसका नाम जानताए न भिड़? उसका कोई बी आईडिया होन दो, एकेदम झक्कास होएंगा! वो दिन अपुन उसकूं सिंपल पूछेला, 'बाबूराव, अक्खा तरफ इत्ता मारामारी काएकूं होताए? पब्लिक कूं शांति से रैना मांगताए कि नई?' बाबूराव कैताए कि 'इदर गल्ली से लेके दिल्ली तलक जिदर बी देखोगे खाली मारामारी दिखेगा। ट्रेन का भीतर सीट का वास्ते मारामारी होएंगा। उसकूं मांडवली करने कूं कोई तीसरा जाएंगा तबी दोनों मिलके उसका ठोकाई करेंगा। भिड़, समज के लेने का, तुम कित्ता बी ट्राई मारेंगा, मारामारी कों आईटम नई रोकने कूं सकताए। फिर वो गल्ली का मवाली लोग का बीच होन दो कि दो कंट्री-कंट्री का बीच होन दो।'

अपुन कहेला- 'बाबूराव, फिर मारामारी चालू रैने देने का क्या? दो पार्टी मचमच करेगा तबी अपुन का कोई फर्ज बनताए कि नई?' बाबूराव अपुन कूं समज दिएलो- 'डादर, जास्ती इमोशनल नई होने का! तुमसे नई सलटताए वाले मान के चलने का कि इदर आईसाईच होताए। इसकूं खाली पीली टाइम पास नई समजने का। अबी अपुन क्या कैताए, तो ध्यान लगाके सुनने का! अपुन शांति करने कूं के सकताए पन शांति करा नई सकताए। अपुन कूं शांति का वो नोबेल प्राइज नई मांगताए। अपुन तो एकईच सल्ला देताए कि जिदर बी चार लोग बईठताए उदर एकाधा आठ बाई दस नई तो दस बाई चारा का एक स्पेस छोड़ना मांगताए। तुम बड़ा-बड़ा सोसायटी नई तो कमर्शियल कांप्लेक्स देखताए न? उदर वो बिल्डर 'स्मोकिंग जोन' का वास्ते जगा छोड़ताए। जगा का कित्ता बी टंचाई होएंगा पन धुंवा छोड़ने का वास्ते खाली जगा छोड़ेगा। वईसाइच 'फाइटिंग जोन' बनाना मांगताए। कोई बी फ्लैट का भीतर हस्बैंड-वाइफ का कोई लफड़ा होएंगा। नई सलटेगा तबी सोसायटी का 'फाइटिंग जोन' जाके सलटाने का। हाफिस-कचेरी का भीतर कोई आईटम नई सलटताए तबी बॉस, जूनियर ऑफिसर, पार्टी को ऊपर 'फाइटिंग जोन' का भीतर चार घड़ी शांति से बईठ के फाइल क्लोज करने का। किसी का ऑर्डर का जरूरत नई।'

अपुन पूछेला कि, 'बाबूराव तुमारा आईडिये से खाली सोसायटी अऊर कमर्शियल कांप्लेक्स का भीतरईच 'मारामारी जोन' बनाना मांगताए कि अऊर बी किदर होना मांगताए?' बाबूराव कहेला- 'अक्खा बाजू में होन दो भिड़, कोई वांदा नई। पोलिस थाना, कोर्ट-कचेरी का काम कमती होएंगा। आईसाए कि इदर आदमी फुल टू टेंशन में मिलेंगा। उसकूं महेंगाई, छोकरा-छोकरी का नोकरी, सादी, अलग खोली बांधने का लफड़ा सब होताए। एनी टाइम वो भरेलाए। इस करके फटाक से वो किसी का भी कंप्लेंट करताए, कोर्ट केस करताए। इस करके अपुन कैताए कि टाइम निकाल के 'फाइटिंग जोन' में दोनों-तीनों पार्टी जाने का। लगे तो उदरईच चा-पानी रखने का। भाई लोग बईठ के प्यार से एक-दूसरे कूं दो चार पंच मारने का। केस उदर का उदरईच सलट जाएंगा, खल्लास...!'

'... पन ब्रादर, अपुन क्या बोलताए कि बड़ा-बड़ा जगा पे बी स्मोकिंग लफड़ा होताए। उसकूं भी अईसाईच मारामारी करके सलटाने का क्या?' अपुन पूछेला। बाबूराव- 'स्कूल, हॉस्पिटल, मॉल, मैरिज हॉल, विधानसभा, पार्लियामेंट, यूनाइटेड नेशंस अक्खा बाजू मारामारी जोन बनाएंगा तबी किदर कूं बी भंकसगिरी नई होएंगा। इसाइच ख्याल रखने का कि सब अपना-अपना बिल्डिंग का फाइटिंग जोन का भीतरईच मचमच करेंगा। बिल्डिंग बनाने का बखत लगे तो वास्तु एक्सपर्ट का सल्ला लेके बनाने का तबी स्मोकिंग फाइटिंग देखने कूं मिलेगा।'

AI Image

खाली पीली

शेयर करें अपने अनुभव
आम मुंबइया भाषा में यह लेख कैसा लगा हमें बताएं nbtreader@timesofindia.com पर, और सब्जेक्ट में लिखें-'खाली पीली'

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

यीशु का प्रेम और करुणा, मां की ममता के रूप

रमेश भाई ओझा

क्रिसमस भगवान यीशु के जन्म का उत्सव है, जो प्रेम, शांति और ममता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और करुणा हमें हर जगह मिल सकते हैं, विशेषकर हमारे घरों में, जहां मां की ममता का साकार रूप देखने को मिलता है। जैसे प्रभु यीशु ने इस संसार में आकर सभी को प्रेम और दया का संदेश दिया, वैसे ही मां की ममता निरंतर जीवन की खुशियों का स्रोत बनकर बहती रहती है।

प्रभु यीशु का प्रेम और स्नेह जब साकार रूप में प्रकट होते हैं, तो यह संसार में एक अद्वितीय और अमूल्य संदेश लेकर आता है। यीशु का प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके कार्यों, उनके बलिदान, और उनके जीवन के हर पहलू में प्रकट होता है। उनका प्रेम न केवल इंसानियत से, बल्कि हर जीव से जुड़ा हुआ था। ये सच्चे प्रेम के उदाहरण बने, जो बिना शर्त और बिना भेदभाव का था।

वह अपनी शिक्षा में लोगों से प्रेम करने, दूसरों को क्षमा करने और सेवा की भावना से जीने की बात करते थे। उनका प्रेम ऐसा था जो किसी सीमा को नहीं मानता था। प्रभु यीशु का यह प्रेम आज भी हमारे दिलों में जीवित है, और हमें सच्चे प्रेम की ओर प्रेरित करता है। उनका प्रेम आज भी मां के रूप में दिखता है। जैसे बादल अपनी बारिश से धरती को जीवन देते हैं, वैसे ही मां की ममता की निरंतर बारिश होती रहती है।

क्रिसमस का पर्व हमें यह याद दिलाता है कि जिस तरह से प्रभु का प्रेम सर्वव्यापी और अनंत है, वैसे ही मां की ममता भी सीमातीत होती है। मां महासागर की तरह है, जिसका कोई अंत नहीं। जैसे सागर के विभिन्न नाम हैं, वैसे ही मां भी विभिन्न रूपों में दिखती है, लेकिन हर रूप उसी ममता, उसी स्नेह से भरा होता है। यही कारण है कि जब बच्चा जन्म लेता है, तो उसकी जुबान से पहला शब्द 'मां' ही निकलता है। जब मां के प्रेम का जिक्र होता है, तो पिता के वात्सल्य को भी नहीं भूल सकते। लेकिन, माता-पिता दोनों के स्नेह को समझना जरूरी है। पिता ज्ञान और शिक्षा, जबकि मां हृदय और भक्ति का स्रोत होती हैं। पिता अपने बच्चों को सफलता के रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन मां का प्रेम और आशीर्वाद बच्चों को हर संकट से उबारता है।

क्रिसमस सिखाता है कि हमें हर किसी के प्रति ममता और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। क्रिसमस प्रेम और स्नेह का सच्चा उत्सव है, जो हमें परमात्मा की कृपा के रूप में मिलता है। मां की ममता एक ऐसा ऋण है, जिसे कोई चुका नहीं सकता, क्योंकि उसकी ममता अपरिमित होती है। वह खुद कष्ट सहकर अपने बच्चों के लिए प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करती है। जैसे मां हर दर्द को सहकर अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाती है, वैसे ही हमें अपने जीवन में भी दूसरों के लिए ममता और प्रेम का प्रदर्शन करना चाहिए। यही संदेश क्रिसमस देता है।

इस क्रिसमस के मौके पर हम मां की ममता को भी सलाम करें, क्योंकि वह सच्चे प्रेम और जीवन की सबसे बड़ी गुरु हैं। वे हमारे जीवन में उसी तरह हैं जैसे पेड़ की छांव होती है। प्रभु यीशु ने दुनिया को इसी प्रेम का संदेश दिया है।

प्रस्तुति : सुभाष चन्द्र शर्मा

अब अंदर की चुनौतियों से लड़ना होगा

मंजरी चतुर्वेदी

खत्म हो रहा साल सियासत के लिहाज से कई मायनों में अहम रहा। इसी साल जनवरी में अयोध्या में भव्य आयोजन के साथ रामलला विराजमान हुए और फिर उसी माहौल में चार-पांच महीने बाद देश में आम चुनाव हुए। इस चुनाव में बिखरे हुए विपक्ष ने संगठित होकर पीएम मोदी की अगुआई वाली BJP को अपने बल पर पूर्ण बहुमत लाने से रोक दिया। यह बात और है कि उसके महज चार-पांच महीने बाद चार राज्यों के असेंबली चुनावों और कई उपचुनावों में वापस फिर BJP अपनी कमियों व नाकामियों से सबक लेती हुई संभल गई। उसने महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाबी पाई। सियासत की इस रस्साकशी के बीच खत्म होने जा रहा 2024 हालिया शीतकालीन सत्र के आखिर में सत्तापक्ष-विपक्ष के बीच आपसी टकराव की ऐसी बानगी दे गया, जिसकी परिणति अस्पताल और पुलिस थाने में हुई।

विपक्ष के तीखे तेवर

दरअसल, आंबेडकर और संविधान का मुद्दा देश की उस बड़ी आबादी को सीधे लक्षित करता है, जिसे ध्यान में रखकर कांग्रेस सहित विपक्ष के तमाम राजनीतिक दल जाति जनगणना की पुरजोर मांग कर रहे हैं। आने वाले साल में दिल्ली और बिहार जैसे राज्यों में चुनाव होने हैं। ये चुनाव BJP और उसके सहयोगियों के अलावा I.N.D.I.A. के दो मजबूत घटक आप और RJD के लिए अपने सियासी वजूद की लड़ाई भी है। अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के सामने उनके लंबे राजनीतिक भविष्य का सवाल है। इस लिहाज से यह साल उनके लिए राजनीतिक जीवन-मरण का है। ऐसे हालात में जाहिर है, संविधान और बाबासाहेब को लेकर चल रहे इस सियासी घटनाक्रम को चुनावी रूप से अपनी ओर मोड़ने की कोशिश दोनों ओर से रहेगी।

चाहे RJD का MY (मुस्लिम-यादव) फॉर्मूला हो या पिछले लोकसभा चुनाव में BAAP (बहुजन, अगड़े, आधी आबादी व पिछड़े) का, या फिर नीतीश कुमार का आजमाया दलित-महादलित फॉर्मूला, सभी को आंबेडकर के बनाए संविधान से ही ताकत मिलती है। दिल्ली और बिहार को जीतना I.N.D.I.A. के लिए अहम है। खासकर बिहार के नतीजे देश की सियासत से लेकर केंद्र सरकार के समीकरणों तक को प्रभावित करेंगे।

वहीं इस साल एक अहम चुनाव महाराष्ट्र में BMC का भी होना है। वैसे इसमें भी कांग्रेस की भूमिका नगण्य ही रहेगी, क्योंकि यहां असली मुकाबला BJP, शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच होना है।

आने वाला साल विपक्षी खेमे के लिए अहम है। देखना होगा कि क्या कांग्रेस इस खेमे की अगुआई करने में सक्षम हो पाएगी? क्या I.N.D.I.A. के भटक दल कांग्रेस को अपना नेता मानते रहेंगे? या फिर इस खेमे में नेता को लेकर फिर से मंथन शुरू होगा? इसका जवाब भी चुनावों के नतीजों के बाद मिलेगा। जिस तरह से विपक्ष के भीतर से TMC चीफ ममता बनर्जी को I.N.D.I.A. का नेता बनाए जाने को लेकर अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं, वे भी कहीं न कहीं विपक्षी खेमे के भीतर आपसी टकराव और वर्चस्व की जद्दोजहद दिखाते हैं। कांग्रेस के भीतर सबसे बड़ा सवाल पार्टी और संगठन की मजबूती के साथ-साथ जमीनी पकड़ बनाने का है। कांग्रेस में आमूल-चूल बदलाव की बात भीतर-बाहर सभी मानते हैं, लेकिन उसे अमल में लाने का साहस मौजूदा नेतृत्व कर पाता है या नहीं, यह भी देखना अहम होगा।

'झुकेगा नहीं' मोड में BJP

दूसरी ओर, महाराष्ट्र व हरियाणा जीतने के बाद जिस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में BJP ने वक्फ और एक देश, एक चुनाव से जुड़े बिलों को आगे बढ़ाया है, उससे साफ है कि उसने तय कर लिया है, भले ही सरकार NDA की हो, लेकिन राज मोदी का है, जहां फैसला 'ऊपरवाला' ही करता है। जिस तरह से हाल में संसद में पीएम ने UCC को आगे बढ़ाने का संकेत दिया, उससे भी साफ है कि BJP अपने अजेंडा पर शुरू हो चुकी है। ऐसे में आने वाले साल में अपने 100 साल पूरे करने जा रहा संघ और BJP जमीन पर अपनी मजबूती के लिए पुरजोर प्रयास करने की तैयारी में है। यह साल BJP व संघ के लिए इस लिहाज से भी अहम होने जा रहा है, क्योंकि इसी साल पीएम मोदी अपनी उम्र के 75 साल पूरे करेंगे। दोनों के सामने बड़ा सवाल होगा कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का नियम क्या नरेंद्र मोदी के साथ भी लागू होगा? आने वाले साल में BJP को लंबे समय से प्रतीक्षित उसका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलेगा। BJP की राजनीति को लेकर उसकी भावी रणनीति से जुड़े तमाम जवाब काफी हद तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे के चयन में ही मिल जाएंगे। यह चेहरा ही आने वाले वक्त में BJP व संघ के आपसी रिश्तों के समीकरणों का भी संकेत होगा।

विशुद्ध राजनीति
कसौटी

रीडर्स मेल www.edit.nbt.in

■ जंगल बचाना होगा

23 दिसंबर का संपादकीय 'वन क्षेत्र पर सवाल' पढ़ा। ISFR-2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का वन क्षेत्र बढ़ा है, लेकिन ज्यादातर वृद्धि प्राकृतिक वनों के बाहर हुई है। प्राकृतिक वन कम हो रहे हैं और घने जंगल उजड़ रहे हैं। यह चिंता का विषय है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 33% हिस्सा वन क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन इसके लिए अभी बहुत काम करना है। अब तक तो यही होता आया है कि वृक्षारोपण करके अखबारों में फोटो छपा कर लोग अपना कर्तव्य पूरा कर लेते हैं। पर गर्मी आते-आते ये सारे पौधे सूख जाते हैं। कई बार ऐसे आंकड़ों को भी रिपोर्ट में शामिल कर लिया जाता है।

विभूति बुपक्या, ईमेल से

■ असंतोष का माहौल

यह पत्र 10 दिसंबर को 'खाली पीली' कॉलम में छपे लेख 'नेट का गड्ढा को खाली पीली अपुन कांईच बोलने का' से संबंधित है। लेख में भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं और उससे जुड़े मुद्दों को चुटीले अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने बाबूराव के माध्यम से समाज में व्याप्त समस्याओं जैसे महंगाई, उपभोक्तावादी मानसिकता, राजनीति और भ्रष्टाचार को बखूबी उजागर किया है। यह सच है कि हमारे समाज में कोई भी काम सही तरीके से करने के बजाय, लोग उसमें मुनाफा तलाशते हैं। यही कारण है कि समाज में अजीब से भ्रम और असंतोष का माहौल है।

प्रमोद कुमार, नोएडा

■ देश की बढ़ी साख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान 'द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर' से नवाजा गया। भारतीयों को देश के प्रधानमंत्री पर गर्व करना चाहिए। यह भारत की बढ़ती साख का परिणाम है कि कुछ समय पहले यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में एक भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया। यह गौरव की बात है।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

nbtedit@timesofindia.com
पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

भांजे की शादी में एकसाथ दिखे राज और उद्धव ठाकरे - एक खबर
- क्या राजनीति के मंच पर भी साथ दिखेंगे।

धर्मेंद्र सिंह

नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 24 दिसंबर 2024 (मंगलवार) ... [illegible]

मोदी की कुवैत यात्रा

संबंध मजबूत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कुवैत यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया कुवैत यात्रा एक ऐतिहासिक क्षण है। वे चार दशक से अधिक समय में इस खाड़ी देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-शबा के आमंत्रण पर की गई इस यात्रा से भारत और कुवैत के बीच संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता नवीनीकृत हुई है। इसके केन्द्र में आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा परस्पर समृद्धि है जो गहरी रणनीतिक साझेदारी का रास्ता खोलते हैं। भारत और कुवैत के बीच शताब्दियों पुराने संबंध हैं जिनका आधार व्यापार तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान रहा है। समय बीतने के साथ यह संबंध जीवन्त साझेदारी में विकसित हुआ जिसमें ऊर्जा, व्यापार तथा दोनों देशों की जनता के बीच संबंध शामिल हैं। आज कुवैत भारत का महत्वपूर्ण ऊर्जा सप्लायर है, जबकि भारतीय विशेषज्ञ और श्रमशक्ति कुवैत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों को रेखांकित करते हुए संकट के समय परस्पर सहायता के उदाहरणों पर जोर दिया। कुवैत में भारत के एक मिलियन से अधिक भारतीय विशेषज्ञ रहते हैं और अनिवासी भारतीयों ने कुवैत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसने स्वास्थ्यरक्षा, इंजीनियरिंग व शिक्षा समेत अनेक क्षेत्रों में योगदान दिया है।

प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए मोदी ने उनके प्रयासों की प्रशंसा की। मोदी ने कहा, 'आपकी ऊर्जा, प्रेम तथा भारत से अडिग संबंध सचमुच प्रेरणादायक हैं।

मुझे हमारे देशों के बीच संबंध मजबूत करने की आपकी भूमिका पर गर्व है।' भारत और कुवैत के बीच आर्थिक संबंध अब विस्तार के चरण में हैं। कुवैत एक प्रमुख ऊर्जा सप्लायर है और उसका भारत की ऊर्जा सुरक्षा में रणनीतिक महत्व है। इसके साथ ही अपने विशाल व लगातार बढ़ते बाजार तथा निवेश अवसरों के कारण भारत कुवैत को अपनी संप्रभु संपदा लगाने का आकर्षक लक्ष्य प्रदान करता है। अपनी चर्चाओं के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों द्वारा समृद्ध होने के दृष्टिकोण का साझा किया जिसमें 'न्यू कुवैत' के साथ 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना शामिल है। इन लक्ष्यों को एकसाथ लाने से दोनों देश परस्पर वृद्धि को बढ़ावा देने वाली साझेदारी स्थापित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कुवैत यात्रा केवल आर्थिक चर्चा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों का विकास भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने ऐसे अनेक लोगों से मुलाकात की जिन्होंने भारत-कुवैत संबंधों को मजबूत करने में योगदान किया है। इनमें अब्दुल्ला अल-बाख्न भी शामिल हैं जिन्होंने एक अनुवादक के रूप में भारतीय महाकाव्यों 'रामायण' एवं 'महाभारत' का अरबीभाषियों के लिए अनुवाद किया है। भारत और कुवैत आज भविष्य की ओर देख रहे हैं, ऐसे में यह यात्रा संबंधों का ऐसा चरण स्थापित करती है जो परंपरागत ऊर्जा संबंधों से आगे जाता है। कुवैत की विकास महत्वाकांक्षाओं के साथ भारत की तकनीकी विशेषज्ञता के सम्मिलन से प्रगति तेज होने की उम्मीद बढ़ती है। इसके साथ ही अनिवासी भारतीयों की मजबूत उपस्थिति एक सेतु का काम करती है जो संबंधों तथा परस्पर समझदारी को और गहराई प्रदान करते हैं। इस साझेदारी को मजबूत कर भारत और कुवैत न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि इस क्षेत्र के स्थायित्व और विकास में भी योगदान कर रहे हैं।

आर्थिक वृद्धि में अस्थाई सुस्ती

पिछले तीन वर्ष में प्राप्त 8% वृद्धि दर को देखते हुए वर्तमान वित्त वर्ष में 6.5-7% की वृद्धि दर बहुत प्रभावशाली नहीं लगती है। हालांकि, इस निम्न दर पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी।

उत्तम गुप्ता
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं।)

कुछ व्यापारियों के कारण लाखों छोटे एवं सीमान्त किसानों को भी अच्छी आमदनी नहीं मिल पाती है क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होने के बावजूद वे उनकी फसल औने-पौने दामों में खरीद लेते हैं। ऐसे परिदृश्य में 'टिकाऊ आर्थिक वृद्धि' के लिए मांग में वृद्धि की उम्मीद करना बहुत स्वाभाविक नहीं लगता है।

इस अस्थाई सुस्ती का कारण संभवतः सरकारी खर्च में कमी है। इससे भारत की प्रगति में ढांचागत परिवर्तनों का महत्व उजागर होता है। वर्तमान वित्त वर्ष की 30 सितंबर, 2024 को समाप्त हुई दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी की वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत दर्ज की गई जो 2023-24 वित्त वर्ष के इसी कालखंड में दर्ज 8.1 प्रतिशत से कम है। यह पिछली सात तिमाहियों में सबसे कम तथा भारतीय रिजर्व बैंक-आरबीआई के 7 प्रतिशत के अनुमान से भी काफी कम थी। यह इस वित्त वर्ष की 30 जून, 2024 को समाप्त पहली तिमाही में दर्ज 6.7 प्रतिशत से भी कम थी। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह घोषणा 'व्यवस्थागत सुस्ती' न होकर अस्थाई सुस्ती है जिसका कारण सरकारी खर्च में कमी है। यह जून की तिमाही में समाप्त चुनावों के कारण है जब आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण अनेक परियोजनायें ठहर गई थीं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि तीसरी तिमाही में विस्तार से यह खोई गतिशीलता बहाल हो जाएगी। वित्त मंत्रालय के विशेषज्ञों का कहना है कि पूरे वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.5 से 7 प्रतिशत होगी। हालांकि, पिछले तीन वर्ष में प्राप्त 8 प्रतिशत वृद्धि दर को देखते हुए वर्तमान वित्त वर्ष में 6.5-7 प्रतिशत की वृद्धि दर बहुत प्रभावशाली नहीं लगती है। हालांकि, इस निम्न दर पर भी भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। ऐसे में बहुत से लोगों का मानना है कि यह चिन्ता का विषय नहीं है। भारत की जीडीपी का लगभग 70 प्रतिशत घरेलू उपभोग पर निर्भर करता है, जबकि 30 प्रतिशत निवेश एवं निर्यात पर निर्भर है जिसमें सरकारी व निजी उपभोग शामिल है। इसी प्रकार निवेश में सरकार और निजी निवेशकों द्वारा खर्च की जाने वाली पूंजी शामिल है। पिछले पांच साल में केन्द्र सरकार ने निवेश के मामले में व्यापक जिम्मेदारी निभाई है। इसे इस तथ्य से देखा जा सकता है कि 2020-21 में 30.42 लाख करोड़, 2021-22 में 34.83 लाख करोड़, 2022-23 में 39.43 लाख करोड़ तथा 2024-25 में 48.20 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया। इसी प्रकार केन्द्र का पूंजीगत खर्च 2020-21 में 4.39 लाख करोड़, 2021-22 में 5.54 लाख करोड़, 2022-23 में 7.50 लाख करोड़, 2023-24 में 10.01 लाख करोड़ तथा 2024-25 में 11.11 लाख करोड़ रहा। केन्द्र सरकार राज्यों को भी पूंजीगत खर्च बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। 2022-23 में उसने राज्यों को 50 वर्ष के लिए 100.000 करोड़ ब्याजमुक्त कर्ज प्रदान किया है। 2023-24 में ये हस्तांतरण 130.000 करोड़ थे। वर्तमान वित्त वर्ष में इन हस्तांतरणों को 150,000 करोड़ पर सीमित रखा गया। उसने निजी क्षेत्र को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। सभी प्रोत्साहनों का मूलाधार कार्पोरेट टैक्स दर को नए विनिर्माण उद्यमों के लिए 15 प्रतिशत तथा वर्तमान उद्यमों के लिए 22 प्रतिशत करना है। इस वर्ष के बजट में विदेशी फर्मों पर कार्पोरेट टैक्स को 40 प्रतिशत से घटा कर 35 प्रतिशत किया गया।

केन्द्र ने निजी उपभोग को बढ़ावा देने की भूमिका भी निभाई है। 2024-25 के बजट में निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर में राहत दी जो प्रति वर्ष लगभग 17,500 रुपये है। इसके लिए नई आयकर व्यवस्था में टैक्स स्लैबों में परिवर्तन किया गया तथा मानक कटौती को बढ़ा कर 25,000 किया गया। कम टैक्स का अर्थ लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा बचना है जिससे उनके ज्यादा खर्च की संभावनायें बनती हैं। लेकिन केवल सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन ही टिकाऊ आधार पर उच्च वृद्धि दर सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। टिकाऊ वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए निजी उपभोग को बढ़ावा देना जरूरी है। वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत की कमी शहरी क्षेत्र में आई जो केन्द्र सरकार द्वारा चुनावों के चलते भारी खर्च न करने के कारण थी। लेकिन यह खतरे का संकेत है। इससे हमारा सामना एक व्यवस्थागत समस्या से होता है जो दशकों से वृद्धि को प्रभावित कर रही है। इसका संबंध आय एवं संपदा के वितरण में असमानता से है। आक्सफैम रिपोर्ट 'इन्क्वेलिटी किल्स' के अनुसार, भारत में 100 सबसे अमीर लोगों की संपदा में 2021 में 775 बिलियन डालर की रिकार्ड वृद्धि हुई जो भारतीय जीडीपी के 25 प्रतिशत से अधिक है। हाल में आयोजित 'टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनामिक कान्क्लेव' में 'ईटी नाऊ' से बातचीत करते हुए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा, 'ऊपर के एक प्रतिशत तथा नीचे के 5 प्रतिशत के बीच असमानता का अनुपात बढ़ा है।' पेरिस स्कूल आफ इकोनोमिक्स के प्रोफेसर तथा आर्थिक असमानता, संपत्ति वितरण व पूंजीवाद की गतिशीलता पर उल्लेखनीय काम वाले थामस पिकेटी ने कहा, 'भारतीय जनसंख्या में सर्वोच्च 10 प्रतिशत का हिस्सा अब 55-60 प्रतिशत है।' उनके अनुसार यह 30-40 प्रतिशत होना चाहिए। हम चाहे जिस स्रोत पर गौर करें, इस तथ्य को अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि भारत में आय के वितरण में भारी असमानतायें हैं। इसका संबंध लोगों के बीच 'विकास' के फलों का साझा करने से है। स्पष्ट रूप से इस साझे में असामनातायें व्याप्त हैं। भारत की सबसे बड़ी कंपनियों की वित्तीय स्थितियों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि पिछले पांच साल से बीएसई 500 सूची में शामिल निगमों के मुनाफे में दूने से अधिक वृद्धि हुई है और यह 2017-18 में 480,000 करोड़ से बढ़ कर 2021-22 में 1000,000 करोड़ तक पहुंच गया जो 47 प्रतिशत वृद्धि है।

इसका अर्थ है कि उत्पादन के आयामों को भुगतान कर्मचारी कामगारों के स्वामी पूंजी की तुलना में कम है। इसके परिणामस्वरूप मुनाफें में असमान वृद्धि हो रही है। इन मुनाफें का बड़ा हिस्सा इन कंपनियों के शेयरधारकों के पास जाता है। इस प्रकार कुल डिविडेंट भुगतान जो 2017-18 में 176,000 करोड़ था, वह 2021-22 में बढ़ कर 302,000 करोड़ हो गया जो 72 प्रतिशत अधिक है। इन पांच वर्षों में उन्होंने अपने कुल मुनाफें का 34 प्रतिशत डिविडेंट के रूप में वितरित किया। यह उच्च भुगतान अनुपात है क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियां भी अधिकतम 30 प्रतिशत डिविडेंट देती हैं। इस डिविडेंट से लाखों अन्य उपभोक्ताओं की खरीद शक्ति प्रभावित होती है। इसी प्रकार कुछ लोगों के पास भारी मात्रा में पैसा पहुंचता है जो या तो खातों में बढ़त के रूप में दिखता है या इसका बहुत थोड़ा हिस्सा शानोशौकत वाली चीजों पर खर्च किया जाता है। इस प्रवृत्ति के कारण कुछ सर्वोच्च लोगों द्वारा संपदा का सृजन ऐसे छोटे एवं मझोले उद्यमों-एसएमई में भी दिखता है जो बड़े उद्यमों से जुड़ जाते हैं, जबकि श्रमिकों को समुचित भुगतान नहीं होता है। ज्यादा लोगों को रोजगार देने के कारण विश्वास किया जाता है कि एसएमई की प्रगति से ज्यादा रोजगारों का सृजन होगा तथा आय वितरण में ज्यादा समानता आएगी। लेकिन उनके स्वामी श्रमिकों को इस लक्ष्य के विपरीत कम पैसा देते हैं। कुछ व्यापारियों के कारण लाखों छोटे एवं सीमान्त किसानों को भी अच्छी आमदनी नहीं मिल पाती है क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होने के बावजूद वे उनकी फसल औने-पौने दामों में खरीद लेते हैं। ऐसे परिदृश्य में 'टिकाऊ आर्थिक वृद्धि' के लिए मांग में वृद्धि की उम्मीद करना बहुत स्वाभाविक नहीं लगता है।

ईश्वर से सीधे जुड़ाव

मनुष्य जो ध्यान करते हैं वह हमारे मन के आराम को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए है, लेकिन यह हमारा सच्चा आंतरिक स्व है, जो पोषण के लिए तरसता है।

रवि बलूरी
(लेखक, रेल विभाग से संबंधित हैं)

ईश्वर के प्रति हमारा दृष्टिकोण अनुष्ठानों से बंधा हुआ है, जो अक्सर आध्यात्मिक संबंध के वास्तविक सार को उलझा देता है। एक अखंड संगठन के रूप में, रेलवे नौकरशाही एक समय जीवाश्म बन गई थी और अपने आंतरिक और बाहरी ग्राहकों और प्रतिद्वंद्वियों के साथ व्यवहार करते समय शुतुरमुर्ग जैसा दृष्टिकोण अपनाती थी, जब तक कि उसने यात्री और माल ढुलाई खंडों को आकर्षित करने के लिए प्रौद्योगिकी को नहीं अपनाया। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और अनुकूलनशीलता का यह प्रमुख सिद्धांत धर्म, आध्यात्मिकता और सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ हमारे संबंधों में भी लागू होता है। ईश्वर के पास जाते समय मनुष्य एक पुरानी शिक्षा पद्धति के कैदी बन गए हैं। ईश्वर और भक्त के बीच लेन-देन बाधित हो गया है क्योंकि ज्ञान और आशीर्वाद का संचरण नाली के पाइपों में बंद हो गया है, क्योंकि साधक और भक्त नपुंसक और कमजोर महसूस करते हैं। क्या हम कुछ साल पहले की दो पथ-प्रदर्शक फिल्मों को याद कर सकते हैं, O M G - ओह माय गॉड! और PK, जिसमें मनुष्य और ईश्वर के रिश्ते की खोज की गई थी? OMG में एक छोटा व्यापारी, कांजी अपने व्यवसाय के बर्बाद होने के लिए निर्माता पर मुकदमा करके धार्मिक प्रतिष्ठान की रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, जो पुरोहित और आध्यात्मिक वर्ग के लिए बहुत ही निराशा की बात है। इसी तरह, पीके- एक एलियन जो ग्रह पृथ्वी पर फंस गया है, क्योंकि उसका अंतरिक्ष यान उसके बिना ही चला जाता है - अपनी बचकानी जिज्ञासा के साथ विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थानों पर सवाल उठाता है, केवल अस्वीकृति को आकर्षित करने के लिए।

यदि कांजी के मामले में यह भगवान कृष्ण की बांसुरी और चक्र था, तो पीके के मामले में यह एक भयावह व्यवस्था की कठोर विचार प्रक्रियाओं को चुनौती देने के लिए प्रतीकात्मक गलत संख्या बन गई। एक व्याकुल पीके विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के दिव्य रूपों से जुड़ने में असमर्थ था और उसके सभी परीक्षण गलत संख्याओं के सैंडबॉक्स में समाप्त हो गए। तो, सही संख्या क्या है? यह भगवान के लिए एक वाई-फाई है। आइए हम एक पल के लिए मान लें कि मनुष्य और इस भव्य डिजाइन की अन्य सभी अभिव्यक्तियाँ कंप्यूटर, स्मार्टफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तरह हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर की तुलना वर्ल्ड वाइड वेब से की जा सकती है, जिसमें ज्ञान का भंडार है, बेशक सृजन और विनाश की क्षमता भी है।

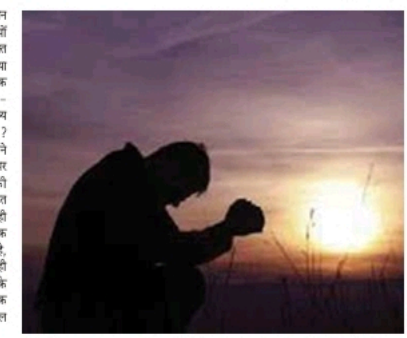

वायर्ड दुनिया में सभी गैजेट वाई-फाई के माध्यम से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। बैटरी पावर कम होने पर या सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियों (इसे कम प्राण स्तर के कारण माना जा सकता है) के कारण संचार में विचलन या व्यवधान होते हैं। पुजारी वर्ग के रूप में मध्यस्थ, गैजेट्स द्वारा सामना की जाने वाली इन गड़बड़ियों के लिए या तो भगवान के हाथों या साधक द्वारा तप की कमी को दोषी ठहराते हैं। दुनिया भर में सदियों से, जैसे-जैसे मनुष्य शुरू से ही प्रकृति के उपासक के रूप में विकसित हुए, स्थापित धर्मों तक, ज्वरग्रस्त मानव मन हमेशा अस्तित्व के स्वीकार्य और विचित्र सिद्धांतों के बारे में जिज्ञासु रहा है। सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने सभी रूपों और असंख्य रूपों में आशीर्वाद देने के लिए सुलभ हैं। हालांकि, दुखद रूप से यह गिरमो (मानव) और चैनल (वाई-फाई) है जो शायद बिग बैंग के बाद से रूपांतरित और पुनर्निर्मित हुए हैं।

वाई-फाई ईश्वर से सीधे संबंध का प्रतीक है। एक सच्चे भक्त को स्वर्गीय ट्रेन में चढ़ने के लिए आपातकालीन कोटा की आवश्यकता होती है। अनुष्ठान करने, टैरो कार्ड रीडर से परामर्श करने, डर के मारे पूजा स्थलों पर जाने, दया या वरदान मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वरीय संवाद सुनिश्चित करने के लिए डीएनए में एक चिप लगाई जाती है जिसे सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। योगिक आसनों का नियमित अभ्यास अनिवार्य रूप से हठ योग है और भौतिक शरीर के लिए एक टॉनिक है। मनुष्य जो ध्यान करते हैं वह हमारे मन के आराम को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए है, लेकिन यह हमारा सच्चा आंतरिक स्व है, जो पोषण के लिए तरसता है। आज का साधारण नश्वर भी सांस की शक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक श्रद्धा की इस स्थिति में हो सकता है। यह हमें हमारे आंतरिक स्व के सबसे करीब लाता है। यह ईश्वर से जुड़ने के लिए शुद्ध वाई-फाई है।

आप की बात

कर्मचारियों का हित देखें

इनफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति का कहना कि देश के विकास के लिए जब मोदीजी हफ्ते में 100 घंटे काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? दूसरे सांसद कार्ति चिदम्बरम के अनुसार सप्ताह में 4 कार्य दिवस होना ठीक है क्योंकि हर रोज जीवन एक संघर्ष है जिसमें अकुशल और घटिया बुनियादी ढांचे और सुविधाओं से जूझना पड़ता है। दोनों के ही विचार न तो कर्मचारियों की कार्यक्षमता के हित में है और न ही राष्ट्रहित में। मूर्ति के 70 घंटे की बात तो पूरी तरह अव्यवहारिक है क्योंकि इससे व्यक्ति की कार्यक्षमता कम होगी साथ ही सामजिक और पारिवारिक जीवन की दिनचर्या पर भी विपरीत प्रभाव पडेगा। दूसरे चिदंबरम का सप्ताह में 4 दिन कार्य का विचार भी गलत है क्योंकि 3 दिन का अवकाश व्यक्ति को आलसी भी बना सकता है जिससे उसकी अकर्मण्यता भी बढ़ सकती है। भारत जैसे विकासशील देश को विकसित बनाने के लिए सप्ताह में 6 कार्यदिवस और 9 व अधिकतम साढ़े नौ घंटे प्रतिदिन (54 या 57 घंटे) पर विचार किया जा सकता है। जो कि बहुत ज्यादा न तो अव्यवहारिक है और न ही जीवन के लिए हानिकारक। अथवा वर्तमान में जो कार्यदिवस का समय है वो भी कोई अव्यवहारिक नहीं है। इसमें अधिक अतिशयोक्ति नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित के साथ ही व्यक्ति के स्वास्थ-हित पर भी ध्यान देना जरूरी है।

-शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

सुरक्षित परिवहन की दरकार

ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन खतरे से खाली नहीं है। जान-माल के साथ ही सुरक्षा के लिए चुनौती भरा परिवहन निर्दोष लोगों और सरकार के लिए बड़ी मुसीबत है। अजमेर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एलपीजी टैंकर और रसायनों से लदे ट्रक की टक्कर में भीषण आग से 40 से अधिक गाड़ियां स्वाहा हो गईं। हादसे ने 11 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। 40 से अधिक घायल हो गए। सरकार ने भले ही मुआवजा देकर संवेदना प्रकट कर दी हो मगर यातायात व्यवस्था में चूक और नियमों के पालन की उपेक्षा बड़ी महंगी पड़ती है। देश में होने वाले हादसों का मुख्य कारण लापरवाही और नियमों को धता बताना है। सड़कों पर जब से यातायात का दबाव बढ़ा है, उचित प्रबंधन की जिम्मेदारी उठानी ही अधिक बढ़ गई है। वाहनों का सुरक्षित चालन, नियमों का सख्ती से पालन, गलत तरीके से वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई ऐसी जरूरतें जिन पर अमल किए बगैर हादसों को रोकना मुश्किल होगा। एक परंपरा बड़े हादसों के बाद प्रशासन के जागने की बन चुकी है जो समय से पूर्व जरूरी है। मुआवजों की नौबत से पहले हादसों को रोकने के ठोस उपाय किये जाना ही उचित निदान है। हमें हर हाल में दुर्घटनाओं को रोकना होगा। सरकार कदम उठाए।

-अमृतलाल मारू रवि, इंदौर

बांग्लादेश पर कार्रवाई हो

यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिन पर दिन बेकाबू हो रहे बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियां, हिन्दुओं के साथ बार-बार अत्याचार, पाकिस्तान के साथ उसकी निकटता गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया और वह जान बचाकर भारत आईं, तभी से यह बिल्कुल स्पष्ट था कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों की कठपुतली है। हिन्दुओं के साथ अत्याचार पहले भी हो रहा था, जो अब चरम सीमा पर पहुंच गया है। यह भी संकेत प्रारंभ से ही थे कि शेख हसीना को सत्ता से हटाने और बांग्लादेश को भारत के विरुद्ध खड़ा करने में पाकिस्तान के अलावा अन्य शक्तियां भी सक्रिय हैं। सबसे पहले यह समझना होगा कि इस्लामी देशों में सत्ता पलटने, हिंसा, घरेलू राजनीति, क्षेत्रीय अलगाववाद, आर्थिक संकट में भारत की किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या विद्रोही नेताओं को शरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी शरण से वहां रह रहे हिन्दुओं को यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। 57 इस्लामिक देशों में आग लगने पर दूर से तमाशा देखते हैं। क्यों किसी इस्लामिक देश ने शेख हसीना को शरण दी? बांग्लादेश का मामला केवल हिन्दुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधा भारत के साथ विद्रोह है और ऐसे में बांग्लादेश को भारत के शत्रु की मान्यता दी जानी चाहिए।

-अंकित सोनी आदित्य, धार

कड़वी हकीकत

भारत में वन क्षेत्र की स्थिति पर हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (आईएसएफआर)-2023 ने कई सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत का वन क्षेत्र बढ़ा है, लेकिन यह वृद्धि ज्यादातर प्राकृतिक वनों के बाहर हुई है। प्राकृतिक वन कम हो रहे हैं और घने जंगल कम घने हो रहे हैं।रिपोर्ट के अनुसार, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% वन क्षेत्र हो गया है। यह आंकड़ा पहली नजर में अच्छा लगता है, लेकिन जब हम इसे विस्तार से देखते हैं, तो यह पता चलता है कि यह वृद्धि ज्यादातर प्राकृतिक वनों के बाहर हुई है। प्राकृतिक वन कम हो रहे हैं और घने जंगल कम घने हो रहे हैं। यह एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि प्राकृतिक वन हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं और जैव विविधता को बनाए रखते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 33% हिस्सा वन क्षेत्र होना चाहिए। यह आंकड़ा हमें यह बताता है कि हमें अभी भी बहुत काम करना है ताकि हम अपने वन क्षेत्र को बढ़ा सकें। **-विभूति बुपक्या**, खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

47 करोड़ से अधिक यूजर्स हैं भारत में इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स के, और इस संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वहीं, 90 करोड़ से अधिक हो गई है भारत में इंटरनेट के उपयोगकर्ताओं की संख्या, स्टेटिस्टिका की एक ताजिया रिपोर्ट के अनुसार।

शिवेश प्रताप
तकनीकी प्रबंधन सलाहकार

आजकल

मानसिक स्वास्थ्य पर सार्थक पहल

मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ की पहचान की है, जिसमें इनकी चुनौतियों का समाधान करने और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को मुख्यधारा की नीतियों से जोड़ने पर अधिक ध्यान दिया गया है। वस्तुतः मानसिक बीमारियों को लेकर सरकार और समाज ने अब तक अधिक ध्यान नहीं दिया। परंतु मोदी सरकार ने इस समस्या को समझा और इसका समाधान भी कर रही है

प्रतीकात्मक

मानसिक स्वास्थ्य ऐतिहासिक रूप से भारत में सर्वाजनिक स्वास्थ्य का सबसे उपेक्षित पहलू रहा है, जो संक्रामक रोगों और बुनियादी ढांचे की कमियों की वजह से दबा हुआ था। आजादी के बाद से दशकों तक सरकारें शहर निर्माण के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने में विफल रहीं। वर्तमान केंद्र सरकार ने इस समस्या को समझा और इस दिशा में क्रांतिकारी सुधारों का उद्देश्य इसे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में एकीकृत करना एवं सभी के लिए सेवाओं को सुलभ, किफायती व न्यायसंगत बनाना है।

वस्तुतः भारत में मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत ही गलत समझा जाने वाला और कलंकित विषय बना हुआ था। लगभग 14 प्रतिशत भारतीयों को सक्रिय मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप की आवश्यकता होने के बावजूद राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16) में पाया गया कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले लगभग 80 प्रतिशत लोग सामाजिक कलंक, जागरूकता की कमी या देखभाल तक सीमित पहुंच के कारण मदद नहीं लेते हैं। यह कलंक सांस्कृतिक धारणाओं से उपजा है जो अक्सर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों को उपचार योग्य चिकित्सा समस्याओं के बजाय व्यक्तिगत कमजोरी या धार्मिक दोष के संकेत के रूप में देखते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य का मतलब केवल मानसिक बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल है, जो व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। एक स्वस्थ दिमाग उत्पादक जीवन, सामंजस्यपूर्ण समाज और संपन्न अर्थव्यवस्था का आधार है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को अगर अनदेखा किया जाए तो अपराध, बेरोजगारी, मादक द्रव्यों के सेवन और कमजोर पारिवारिक व्यवस्था जैसी सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत जैसे देश के लिए जो 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने की आकांक्षा रखता है, मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से ग्रस्त आबादी के लिए नवाचार करना, प्रतिस्पर्धा करना और अपनी आर्थिक गति को बनाए रखना मुश्किल होगा। मानसिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में एकीकृत करना अनिवार्य है।

भारत का मानसिक स्वास्थ्य परिदृश्य : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, भारत की लगभग 7.5 प्रतिशत आबादी मानसिक विकारों से पीड़ित है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16) से पता चला है कि लगभग 15 प्रतिशत भारतीय वयस्कों को सक्रिय मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है, मानसिक स्वास्थ्य खराब है और इसके लिए पर्याप्त धन नहीं है। मौजूदा स्थिति बात यह है कि देश में प्रति एक लाख लोगों पर एक से भी कम मनोचिकित्सक हैं, जबकि डब्ल्यूएचओ ने प्रति एक लाख पर तीन मनोचिकित्सक होने की सिफारिश की है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान का अनुमान 2012 और 2030 के बीच लगभग एक लाख करोड़ डालर है। ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने के लिए मजबूत नीतियों और बुनियादी ढांचे की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

अमेरिका मानसिक स्वास्थ्य पर सालाना 238 अरब डालर से अधिक खर्च करता है, जहां हर एक लाख लोगों पर लगभग 12 मनोचिकित्सक हैं। इसी तरह यूरोप में मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली अच्छी तरह से विकसित है, जहां जर्मनी जैसे देश हर 10 हजार लोगों पर 18 से अधिक मनोरोग विशेषज्ञ उपलब्ध कराते हैं। इस बीच चीन में 2013 में अपने पहले मानसिक स्वास्थ्य कानून के बाद से इस ओर जागरूकता बढ़ी है।

मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017 : केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 में प्रस्तुत किया गया था। संसद द्वारा अधिनियम पारित होने के बाद मई 2018 में यह लागू हुआ था। इस अधिनियम का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि यह मानसिक बीमारी की स्थिति वाले व्यक्तियों के मुद्दे के रूप में इसे मान्यता देता है। यह सुनिश्चित करता है कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ बहिष्कृत जैसा व्यवहार न किया जाए, बल्कि वे कानून के तहत देखभाल, उपचार और सुरक्षा के हकदार हों। यह अधिनियम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच के अधिकार को सुनिश्चित करता है, मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्डों की स्थापना को अनिवार्य बनाता है तथा उपचार से पहले सूचित सहमति की गारंटी देता है, जिससे रोगियों को सशक्त बनाया जाता है।

इस बीच तृतीयक मानसिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए सरकार ने 25 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है और 19 सरकारी मेडिकल कालेजों में मानसिक स्वास्थ्य विशेषताओं में 47 स्नातकोत्तर (पीजी) विभागों की स्थापना की है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अध्यास करने के लिए मनोचिकित्सकों और विशेषज्ञों के लिए प्रोत्साहन पेश किए हैं और प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में डिजिटल अकादमियों की स्थापना की है। इन अकादमियों ने 2018 से 42,488 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी को दूर किया है और सुनिश्चित किया है कि गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवा भी सुलभ हो।

मोदी सरकार ने 1.73 लाख से अधिक उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपग्रेड किया है, जिससे सुनिश्चित होता है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं जमीनी स्तर पर उपलब्ध हों। 767 जिलों में लागू जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक सेवाओं का विस्तार करके भारत के मानसिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया है। यह देखभाल का एक मजबूत नेटवर्क प्रदान करता है, जिसमें औषधी, मनो-सामाजिक परामर्श, आउटरीच कार्यक्रम व एंबुलेंस सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप वंचित और कमजोर आबादी तक पहुंचे, जिससे कल्याण के समग्र माडल को बढ़ावा मिले।

कुशल कार्यबल के लिए स्वास्थ्य रणनीति

ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रोकर्स द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि 46 प्रतिशत भारतीय फर्मों का मानना है कि उन्हें अपने कर्मचारियों के लिए बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता है। यह मान्यता बढ़ते स्वास्थ्य बिलों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई है, जो राजस्व वृद्धि और वेतन वृद्धि से कहीं अधिक है, जिससे व्यवसायों के लिए वित्तीय चुनौतियां बढ़ गई हैं। भारत में कार्यस्थल पर तनाव लंबे समय तक काम करने, खराब कार्य-जीवन संतुलन और सामाजिक एवं पेशेवर अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अत्यधिक दबाव से प्रेरित होता है। मोदी सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली नीतियों के माध्यम से कार्यस्थलों में मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, 2017 का मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम कर्मचारियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा की अनिवार्य बनाता है, जिससे नियोक्ताओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ भेदभाव करना अवैध हो जाता है।

मानसिक स्वास्थ्य के प्रति मोदी सरकार का बहुआयामी दृष्टिकोण एक स्वस्थ और अधिक उत्पादक भारत के लिए मजबूत नींव रख रहा है। प्रमुख परिणामों में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और टेली-मानस के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक बेहतर पहुंच और प्रारंभिक हस्तक्षेप को बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में मानसिक स्वास्थ्य को एकीकृत करना और उपचार की कमी को पाटने के लिए कुशल मानसिक स्वास्थ्य कार्यबल का विकास शामिल है।

जैसा कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, मोदी सरकार ने एक मजबूत मानसिक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, लेकिन आगे की राह में एक व्यापक मानसिक स्वास्थ्य रणनीति स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और शिक्षाविदों के साथ सहयोग के साथ-साथ अधिक पेशेवरों, निरंतर जागरूकता प्रयासों और बढ़े हुए निवेश की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य में मोदी सरकार के प्रयास भारत की स्वास्थ्य सेवा नीति में एक आदर्श बदलाव को दर्शाते हैं। जमीनी स्तर पर हस्तक्षेप से लेकर डिजिटल प्लेटफार्म का लाभ उठाने और तृतीयक देखभाल को बढ़ावा देने तक ये सुधार समग्र कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। जैसे-जैसे भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होता है, मानसिक स्वास्थ्य एक प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए।

इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करके सरकार न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुधार कर रही है, बल्कि देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को भी मजबूत कर रही है। यह एक स्वस्थ भारत की सुबह है, जहां प्रत्येक नागरिक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है। भारत सही रास्ते पर है और हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य एक विकसित राष्ट्र बनने की हमारी यात्रा का आधार बने। दशकों की उपेक्षा के बाद सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य को वह प्राथमिकता दी है जिसका वह हकदार है, जिससे एक बार फिर साबित हो गया है कि भारत प्रगति के एक नए युग की ओर अग्रसर है।

(शिवेश प्रताप)

खरी-खरी

प्रशासन की पारदर्शिता

इरन सम्मा

मुसाझैलाल मेरे पड़ोसी हैं। उनकी हर बात में नुक्ताचीनी करने की आदत है। सुबह-सुबह आ धमकते हैं चाय सुड़कने। मैं भी इस बीच उनसे बतियाता हुआ शेव बना लेता हूं और वे अपनी भीतर की भड़ास मुझ पर डाल कर चले जाते हैं। आज जैसे ही आए तो मैंने पूछा, 'क्या बात है? लग तो ऐसा रहा है कि जैसे तुम्हें पैसों की सख्त आवश्यकता है और तुम अपनी बात रखने का कोई नया तरीका तलाश रहे हो।'

मुसाझैलाल बोले, 'शर्मा जी, कभी तो सीरियस रहा करो। तुमने तीन बार मुझे उधार क्या दे दिया, मेरी बोलती बंद करना चाहते हो।'

'नहीं, ऐसा नहीं है। बात पारदर्शिता की है। तुमने लेनदेन में ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई।'

मुसाझैलाल ने कहा, 'मुझे पारदर्शिता से चिढ़ है। मानता हूं पारदर्शिता में सब साफ दिखाई देता है, लेकिन अब तक क्या दिखाई नहीं दे रहा था। किसी विभाग में घपला-गबन घोटाला जो भी हो रहा था, क्या वह हमारी पारदर्शिता नहीं है।'

मैंने बीच में ही रोका, 'आपने मुख्यमंत्री को देखा है? इस बार जो मुख्यमंत्री आए थे, वे एकदम पारदर्शी थे। जिस ओर से भी देखो एकदम आर-पार दिखाई देते थे।'

वे बोले, 'एक बार क्या, कई बार देखा है इसमें नई बात क्या है?'

'यहां तुम मात खा गए। वे एकदम ट्रांसपेरेंट हैं। उनके कार्यों में जो पारदर्शिता देखी जा रही है, उनसे तो पूरा विपक्ष भौंचक्का रह गया है।'

उन्होंने पूछा, 'मैं समझा नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि नई सरकार कुछ करना चाहती है। सारे मिनिस्टर नए डिटर्जेंट से कमीजें धो-पहनकर आए हैं। पहले की बात जाने दो। नए जनादेश की रोशनी में कार्यशैली को देखो तो पारदर्शिता से मेरी तो आंखें चौंधियां रही हैं।'

मुसाझैलाल का चेहरा लाल हो गया, वह बोला, 'तुम्हारी मति मारी गई है। पारदर्शिता को लेकर तो क्या विवाद हो सकता है, परंतु हर ओर शोर हो रहा है, लोग ठहराव में आ गए हैं। तबादलों की ताबड़तोड़ और निगमों, बोर्डों में हड़कंप- इसका मतलब तुम समझते हो?'

मैं अब यह सब समझने की कोशिश कर रहा हूं।

X पोस्ट

अगर विराट कोहली के विदेश में बसने की खबर सही है तो यह उन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। जिस देश की संसद का पूरा शीतकालीन सत्र सिर्फ इसी मुद्दे पर कि 'बाबा साहेब का अपमान किसने किया' जैसी अनावश्यक बहस में बीत जाए, वहां क्या ही भविष्य होगा।

मोक@oldschoolmonk

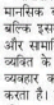

नेहरू का 60 साल पहले निधन हो गया। आंबेडकर 68 साल पहले गुजर गए। अखिर हमारे नेता पिछली सदी के दशकों में ही क्यों अटके हुए हैं। आज प्रदूषण, महंगाई, शिक्षा, टैक्स, धोखाधड़ी, रोजगार और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं करते। मनोज अरोड़ा@manoj_216

खाद्य वस्तुओं पर पांच प्रतिशत से अधिक जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए। पापकार्न पर जीएसटी के मामले से दिखता है कि टैक्स को लेकर कितना बड़ा मजाक चल रहा है। ऐसे में अर्थिक वृद्धि की रफ्तार सुस्त पड़ने पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसी कारण शेयर बाजार भी पुरानी तेजी पकड़ने को छटपटा रहा है और रुपया भी ऐतिहासिक गिरावट का शिकार हो गया है। वीर सांघवी@virsanghvi

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी दर घटाई जानी चाहिए?

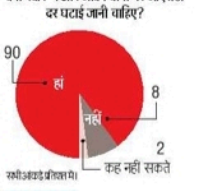

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या रविचंद्रन अश्विन के स्थान पर तनुष कोटियान के चयन का फैसला सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के घंटवारी का मत है।

जनपथ

बहना बदले बैग अरु भैया जी टी शर्ट,
सिर्फ प्रतीकों से करें राजनीति से पलटें।
राजनीति से पलटें सीरियस दिखे न कोई,
तभी सफलता दीख रही है खोई-खोई।
तनिक नहीं अंदाज कहां पर क्या है कहना,
भाई की ही राह चल रही दिखती बहना!
– ओमप्रकाश तिवारी

जयकृष्ण वाजपेयी
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बंगाल

बंगाल डायरी

प्रदेश में बांग्लादेशी आतंकियों का बड़ा नेटवर्क

पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी आतंकी संगठन, उनके तार बंगाल से जुड़ते रहे हैं। यहां से आइएसआइएस, अल कायदा, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन, हिज्ब-उल-मुजाहिदीन (हूजी), जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) समेत कई आतंकी संगठनों के आतंकियों की गिरफ्तारी होती रही है। दो अक्टूबर, 2014 को बर्द्धमान जिले के खगड़ागढ़ में आइईडी बनाते समय हुए धमाके के बाद बांग्लादेशी आतंकी संगठन जेएमबी के बड़े माड्यूल का राजफाश हुआ था और दो दर्जन से अधिक आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद भी अन्य कई आतंकी संगठनों से जुड़े आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। अब देखा जा रहा है कि सीमा पार बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद वहां की जेलों में बंद आतंकियों को रिहा किया गया है तो एक बार फिर बंगाल में उनकी सक्रियता बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बंगाल में फर्जी पासपोर्ट रैकेट का राजफाश हुआ है और आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, वह बता रहा है कि उनका संजाल काफी फैल चुका है।

बांग्लादेश घुसपैठिये और आतंकियों ने सिर्फ फर्जी पासपोर्ट नहीं, बल्कि वोटर आइकार्ड समेत कई तरह के भारतीय पहचान पत्र बना रखे हैं। पिछले दिनों हुई गिरफ्तारी में फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले जिस रैकेट का पता चला है, उस गिरोह से जुड़े पोस्ट आफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के ठेका कर्मी दीपांकर दास के गैजेट्स में मिले डाटाबेस से जांच अधिकारियों को कई अहम सुराग मिले हैं। उस डाटाबेस में लगभग 30 हजार लोगों के नाम हैं, जिनके लिए फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेज, जिसमें मुख्य रूप से जाली पासपोर्ट शामिल हैं, तैयार किए या कराए गए हैं। इसी कड़ी में जब जांच आगे बढ़ी तो जांच अधिकारियों को बंगाल में सर्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के कुछ राशन डीलरों के बारे में पता चला है, जो इस रैकेट के अहम कड़ी हैं। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि राशन डीलर फर्जी पासपोर्ट बनाने के रैकेट में अहम भूमिका निभा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिये भारतीय क्षेत्र में कदम रखने के साथ ही इस रैकेट के एजेंटों से संपर्क करते थे और इसके बाद उनके नाम से फर्जी राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। एजेंट स्थानीय राशन डीलर से उन राशन कार्डों की सूची के लिए संपर्क करते थे, जो संबंधित कार्डधारक की मृत्यु या लंबे समय से उस कार्ड के लिए आवंटित राशन न लेने के कारण हाल में रद हुए हैं। ऐसे ही राशन कार्ड का चयन किया जाता था और उसके आधार पर कार्ड के गुम हो जाने की थाने में सामान्य डायरी दर्ज कराई जाती थी। बाद में उस डायरी के आधार पर घुसपैठिये को कार्ड का लाभार्थी बताकर समाप्त हो चुके कार्ड को पुनर्जीवित किया जाता था। इसके बाद जाली भारतीय दस्तावेजों के निर्माण की अगली प्रक्रिया में वोटर आइकार्ड, फिर पैन और आधार कार्ड तथा अंत में जाली पासपोर्ट तैयार किया जाता था।

बंगाल से गिरफ्तार आतंकी अब्बास अली, मिजारुल शेख और केरल से पकड़ा गया साद (दाएं)। फाइल

इस रैकेट का राजफाश होने के बीच ही असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बांग्लादेशी आतंकी संगठन 'अंसारुल्लाह बांग्ला टीम' (एबीटी-अल कायदा की उपमहाद्वीपीय शाखा) के आठ आतंकियों को गिरफ्तार किया तो कई और नए तथ्य सामने आ रहे हैं। केरल से पकड़े गए एबीटी के आतंकी मोहम्मद साद राडी उर्फ शाब शेख का नाम बंगाल की मतदाता सूची में है। उसका वोटर कार्ड भी है। जांचकर्ताओं के मुताबिक शब शेख ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर वोटर कार्ड और पासपोर्ट बनवाया है। शाब का नाम मुर्शिदाबाद के दो विधानसभा क्षेत्रों कांदी और हरिहरपाड़ा की मतदाता सूची में है। इस बात की जांच की जा रही है कि इस बांग्लादेशी आतंकी का नाम मतदाता सूची में कब और कैसे शामिल हो गया। वोटर आइकार्ड कब बना? असम एसटीएफ ने शाब के दो करीबी आतंकियों मिनारुल शेख और मोहम्मद अब्बास अली को बांग्लादेश की सीमा से सटे मुर्शिदाबाद जिले के हरिहरपाड़ा से गिरफ्तार किया है। इसीलिए माना जा रहा है कि शाब का वोटर आइकार्ड तैयार कराने में इन दोनों की भूमिका हो सकती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि उक्त बांग्लादेशी आतंकी ने संभवतः इस राज्य के चुनाव में मतदान भी किया है। जांचकर्ताओं को पता चला कि शाब शेख के अलावा एबीटी के कई बांग्लादेशी सदस्यों का भी हरिहरपाड़ा में आना-जाना था, क्योंकि यह क्षेत्र बांग्लादेश की सीमा के करीब है।

इसी बीच रविवार को दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग इलाके से जम्मू-कश्मीर पुलिस व बंगाल एसटीएफ के संयुक्त आपरेशन में आतंकी संगठन तहरीक-उल-मुजाहिदीन के बांछित आतंकी जावेद मुंशी को गिरफ्तार किया गया है। इन आतंकियों की गिरफ्तारी तथा फर्जी राशन कार्ड, वोटर आइकार्ड, पासपोर्ट बनाया जाना यह बता रहा है कि आतंकी संगठन अपना संजाल बंगाल में कहां तक फैला चुके हैं इसीलिए इस मामले में बहुत ही गंभीरता से जांच कर इन संगठनों व रैकेट का समूल नष्ट करने की जरूरत है।

मंथन

डिजिटल उपनिवेशवाद से मुक्ति

इंटरनेट मीडिया के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया एवं समाज में वैचारिक ध्रुवीकरण को प्रभावित किया जा रहा है, लिहाजा भारत सरकार को इस संदर्भ में अपनी एक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए

डा. मुकुल श्रीवास्तव
प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय

आज के तकनीकी युग में इंटरनेट मीडिया ने हमारे संवाद और विचारों के आदान-प्रदान करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। वस्तुतः पश्चिमी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स जैसे फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम आदि हमारे डाटा का आर्थिक शोषण करने के साथ ही भारत की चुनावी प्रक्रिया, न्यायिक फैसलों और समाज में वैचारिक ध्रुवीकरण को भी व्यापक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। फेक न्यूज, बाट्स और प्रोपेगेंडा के इस दौर में भारत को अपने डिजिटल मंचों पर अधिक नियंत्रण और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता बढ़ गई है।

स्टेटिस्टिका की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 90 करोड़ के पार पहुंच गई है और यह निरंतर बढ़ रही है। भारत में फेसबुक, इंस्टाग्राम, वाट्सअप, एक्स और यूट्यूब जैसे वैश्विक प्लेटफार्म्स सबसे अधिक प्रचलित हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश कंपनियों का नियंत्रण पश्चिमी देशों, मुख्य रूप से अमेरिका के हाथों में है। हमारा अपना एक भी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म नहीं है, जो इन विदेशी एप्स के सामने खड़ा हो सके। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजारों में से एक है, अमेरिका और चीन के बाद भारत डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। तकनीकी नवाचारों के मामले में भारत की स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में काफी सुधार आया है। हाल ही में आई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 रैंकिंग में 133 देशों में भारत ने 39वां स्थान हासिल किया है, जो देश की बढ़ती तकनीकी और डिजिटल क्षमता का प्रमाण है। हालांकि इसमें अभी भी काफी सुधार की आवश्यकता है।

पिछले कुछ वर्षों में इन विदेशी प्लेटफार्म्स पर डाटा सुरक्षा, फेक न्यूज और पक्षपातपूर्ण प्रचार का प्रभाव बढ़ा है। भारत की चुनावी प्रक्रिया में भी इन कंपनियों का हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा है। साल 2023 में यूनेस्को इपसौस द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, देश में शहरी क्षेत्रों के 64 प्रतिशत लोगों ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म्स को गलत सूचनाओं और फेक न्यूज का प्राथमिक स्रोत माना, इन फेक न्यूज के प्रसार में खासकर फेसबुक, वाट्सअप और एक्स इनमें प्रमुख भूमिका निभाते नजर आए। वहीं सांप्रदायिक हिंसा और दंगों के मामले में भी इंटरनेट मीडिया एक बड़ी वजह के रूप में सामने आया है। फेसबुक की एक इंटरनल रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में हुए दिल्ली दंगों में फेसबुक और वाट्सएप पर 22 हजार से अधिक ऐसे पोस्ट्स और ग्रुप्स पाए गए, जिनमें सांप्रदायिक नफरत फैलाई जा रही थी। इसी तरह का मामला 2021 में ट्विटर (अब एक्स) पर भी सामने आया, जब भारत सरकार ने हिंसा फैलने की आशंका में उस समय तीन नए कृषि कानून विरोधी आंदोलन से जुड़े कुछ अकाउंट्स और पोस्ट को हटाने के निर्देश दिए थे। लेकिन तब उसने पूरी तरह से इसके अनुपालन से इन्कार कर दिया था। ट्विटर ने उस समय दलील दी कि यह उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और 'एंड टू एंड एन्क्रिप्शन' का उल्लंघन करेगा। इसके साथ ही वाट्सएप जो कि मेटा के स्वामित्व में है, उसने भी आइटी नियम 2021 के कुछ नियमों की अवहेलना की थी।

भारत को नहीं मिल रहा प्रत्यक्ष लाभ : उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे डी. वाई. चंद्रचूड़ इंटरनेट मीडिया के न्यायपालिका के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ इंटरनेट मीडिया समूह, जनभावना के जरिये न्यायाधीशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल में एक्स और मेटा प्लेटफार्म्स पर फैसलों की ट्रोलिंग और जनभावनाओं के जरिये परोक्ष दबाव बनाने के मामले काफी बढ़ गए हैं। मुश्किल यह है कि ये विदेशी कंपनियां भारत में काम करने के बावजूद पूरी तरह से भारतीय कानून के अधीन नहीं हैं और अक्सर अपनी वैश्विक नीतियों का हवाला देकर बच निकलती हैं। बात केवल यह नहीं है कि ये विदेशी कंपनियां भारत में प्रभाव बना रही हैं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी यह देश को बड़ा नुकसान पहुंचा रही हैं। उदाहरण के लिए, मेटा और एक्स जैसे प्लेटफार्म भारत में विज्ञापन से अरबों डालर कमाई करते हैं, लेकिन उनका बड़ा हिस्सा विदेश चला जाता है। मेटा की हालिया जारी आर्थिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत से मेटा जिसमें फेसबुक, वाट्सअप, इंस्टाग्राम शामिल हैं, इस साल भारत से 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक राजस्व की कमाई की है। लेकिन इसका कोई प्रत्यक्ष लाभ सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था को नहीं मिलता है।

अब समय आ गया है जब भारत को चीन और रूस जैसे देशों से सीख लेकर अपने स्वदेशी इंटरनेट मीडिया का इकोसिस्टम बनाने की और कदम बढ़ाना चाहिए। आज भारत में तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। आधार और यूपीआइ जैसे स्वदेशी प्लेटफार्म्स ने यह साबित कर दिखाया है कि हम तकनीकी चुनौतियों को कैसे संभाल सकते हैं। तमाम चुनौतियों के बाद भी अगर भारत अपनी इंटरनेट मीडिया प्रणाली विकसित करता है, तो यह भारत पर थोपे जा रहे डिजिटल उपनिवेशवाद का मुकाबला करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। अगर नागरिकों और सरकार का समर्थन प्राप्त हो तो स्वदेशी इंटरनेट मीडिया के लिए विशाल संभावनाएं हैं। जिससे भारत इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे आ सके और डिजिटल उपनिवेशवाद से मुकाबला कर सके।

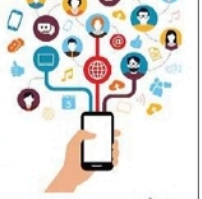

प्रतीकात्मक

****